R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

वर्ष : 22 I अंक : 05
01 से 15 दिसम्बर 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

5 State ELECTION 2023

एक्जिट पोल... कितना सच कितना फसाना!

जनता का मूड नहीं नेताओं की धड़कने बढ़ाते हैं एग्जिट पोल

साइकिल, हाथी और आरी, किसके ड्रीम पर पड़ेगी भारी...

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

पहल

9 | **644 स्कूलों का होगा कायाकल्प**

मप्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सीएम राइज स्कूलों के साथ ही अब पीएम-श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की योजना बनाई है। योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों...

राजपथ

10-11 | **चुनावी वादे कितने खरे...**

विधानसभा चुनावों के दौरान वादों की फेहरिस्त काफी लंबी हो चली है। 12वीं पास को स्कूटी, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 या 2,900 रुपए क्विंटल के अलावा बोनस की भी अतिरिक्त व्यवस्था...

मेट्रो

12 | **मेट्रो का कामर्शियल रन अप्रैल में...**

विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल-इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो गया है। अब इसके कामर्शियल रन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर में सुभाष नगर डिपो से एम्स अस्पताल साकेत नगर तक आवश्यक सिविल वर्क पूरा...

आर्थिकी

14 | **अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार**

भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन डॉलर से कुछ अधिक की थी। अब आंकड़े बता रहे हैं कि भारत 18 नवंबर 2023 की देर...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

देश में पांचों राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। मप्र में क्या भाजपा की वापसी होगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का रिकॉर्ड बनेगा या सफाया, राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज। ऐसे कई सवाल सियासी फिजा में तैर रहे हैं। माना जाता है कि एग्जिट पोल जनता का मूड बताते हैं। वोटिंग पैटर्न दिखाते हैं जिससे नेताओं की धड़कने बढ़ जाती हैं। लेकिन, ये एग्जिट पोल हमेशा पूरी तरह सच नहीं होते हैं... इसकी विश्वसनीयता हमेशा कटघरे में रहती है...

15

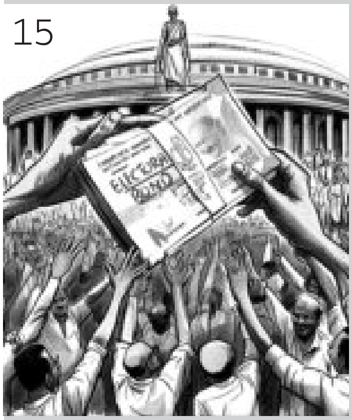

23

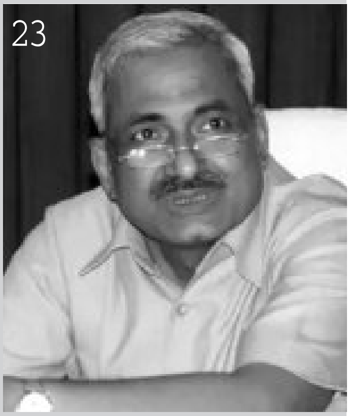

44

45

राजनीति

30-31 | **अब मिशन 2024...**

5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद दिसंबर में विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी। इसमें न्यूनतम साझा घोषणापत्र पर सभी दलों से प्रस्ताव लिए जाएंगे। जिन मुद्दों पर सहमति बनेगी, उन्हें शामिल करते हुए इंडिया गठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों...

महाराष्ट्र

35 | **मराठा आरक्षण की आग**

एक बेहद सामान्य दिहाड़ी मजदूर सा चेहरा। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे से बाल। शरीर पर साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में तेज चमक और दृढ़ विश्वास। ये हैं मनोज जरांगे, जो आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन व राजनीति का चमकता चेहरा हैं। मनोज राज्य में मराठा समुदाय...

बिहार

38 | **दांव पर लोकसभा...**

रोजगार, जातिगत सर्वे और फिर 75 फीसदी आरक्षण जैसे बैक टू बैक मास्टरस्ट्रोक चल कर नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्ष को एक तरह से मूर्छित अवस्था में पहुंचा दिया है। राजनीतिक रूप से इन चालों की काट सूझ नहीं रही हैं। ऐसे में उनके हाल के दो...

6-7	अंदर की बात
41	महिला जगत
42	अध्यात्म
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

अपनी बात

क्यों चल रहा शह–मात और घात–प्रतिघात..?

किसी कवि ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की वर्तमान स्थिति पर लिखा है...

बड़ा शोर सुनते थे आई...आई...सीबीआई, आज हर तरफ क्यों हो रही जगहंसाई
क्यों चल रहा शह-मात और घात-प्रतिघात, सैकड़ों पैबंदों से भी क्या बनेगी बात..

एक समय था जब आयकर विभाग और सीबीआई का नाम सुनते ही निष्पक्षता, भरोसेमंद और विश्वसनीयता का भाव हर व्यक्ति के मन में आ जाता था। लेकिन आज ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई को शह–मात और घात–प्रतिघात का हथियार माना जाने लगा है। जांच एजेंसियां किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ होती हैं। विडंबना यह है कि ये एजेंसियां सदैव संदेह के घेरे में ही रहती हैं। बीते कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ा है। इनके कई दिग्गज अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के घेरे में आए हैं। प्रत्येक जांच एजेंसियों में ऐसे कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी शामिल होते हैं, जो जांच प्रक्रिया को सुचारु रूप से नहीं चलने देते। ऐसे में कैसे हम कानून के राज की आशा करें? जब तक जांच एजेंसियां राजनीतिक प्रभाव से दूर नहीं होंगी, तब तक किसी भी प्रकार के सुधार की आशा नहीं की जा सकती। यह सच है कि आज के समय में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ही किया जाता है। इसी वजह से सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। सभी यह चाहते हैं कि ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता बनी रहे। इसके लिए इन्हें बिना किसी दबाव के काम करने की छूट दी जानी चाहिए। देश में अब विपक्ष के नेताओं की सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी की खबर कोई नई बात नहीं रही। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिस तरह गिरफ्तार किया गया है और जांच एजेंसी अभी तक कोर्ट में गिरफ्तारी का सबूत पेश नहीं कर पाई है उससे उसकी विश्वसनीयता कटघरे में है। केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग पहले भी होता रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब से भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई है, तब से सीबीआई, ईडी का कामकाज और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। पिछले 10 सालों मे ईडी 1500 से ज्यादा छापे मारने के बावजूद सिर्फ दर्जनभर लोगों को ही जेल भेज पाई है। केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार विपक्ष पर हमले करती रही है। इसमें इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। ऐसे ही हालात रहे तो देश में लोकतंत्र को खतरा है। सोचने का विषय ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के नेताओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी उनकी न तो गिरफ्तारी होती है और न ही मीडिया ट्रायल? क्या इन एजेंसियो में तैनात अधिकारी अपना संवैधानिक दायित्व भूलकर राजनीतिक आकाओं को खुश करने मे लगे हैं? ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह नौकरी छोड़ भाजपा में शामिल हुए और चुनाव भी लड़ा। इस तरह की चीजें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इन एजेंसियों पर जनता का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके कोई भी राजनीतिक दल जनता का दिल और चुनाव नहीं जीत सकता। पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर उनके परिवार द्वारा संचालित कंपनी से पीपीई किट खरीदने का मामला सामने आया। कर्नाटक में मंत्री पर 40 फीसदी रिश्वत लेने का आरोप लगा, लेकिन इन सभी मामलों पर कोई जांच या गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच एजेंसियों को नैतिकता के मजबूत चबूतरे पर पांव रखकर काम करना चाहिए।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 5, पृष्ठ-48, 1 से 15 दिसंबर, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

अंधकार में भविष्य

विकास की अंधी दौड़ में हर साल जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उससे काफी कम अनुपात में पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, वो देखभाल के अभाव में सूख जाते हैं। इससे आने वाले समय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

● **मीनाक्षी नागर,** सीहोर (म.प्र.)

भूजल का अधिक दोहन

भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पहले ही कहीं ज्यादा तेजी से अपने भूजल का दोहन कर रहा है। भारत में हर साल 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि भूजल के वैश्विक उपयोग का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।

● **अश्विन चौहान,** गुना (म.प्र.)

जमाखोरों पर हो कार्रवाई

रूस-यूक्रेन के बीच पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के दौरान ही इजराइल-हमास के बीच युद्ध के गहराने की आशंका के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए कारगर रणनीतिक प्रयास बहुत जरूरी है। देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार को और तेजी लानी होगी।

● **राहुल पाल,** भोपाल (म.प्र.)

गंगा की सफाई कागजी

2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने गंगा की स्वच्छता को अपनी उच्च प्राथमिकता वाला काम बताया था और इसके लिए नमामि गंगे योजना की घोषणा की गई थी, जिसका मकसद गंगा के बिगड़े रंग-रूप को बदलना और प्रदूषण पर रोकथाम था। हालांकि, इस पर काम 2016, अक्टूबर के आदेश के बाद से ही शुरू हुआ। गंगा की सफाई को लेकर किए जा रहे सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं।

● **नीलम शर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

कद्दावर नेता कितने पानी में...

मप्र विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा की प्रयोगशाला के रूप में नजर आया है। ये प्रयोगशाला 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तभी तो मंत्रियों, सांसदों और बड़े नेताओं को टिकट देकर भाजपा ने चुनाव मैदान में उतार दिया। 3 दिसंबर तक सबको मालूम हो जाएगा कि भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले अभी कितने पानी में हैं? इस बार के चुनाव में भाजपा ने दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ ही 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। जिनमें तीन केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन इन दिग्गजों की भी जान अपनी सीट की ओर अटकी नजर आ रही है। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा ने चुनाव में उतारा है।

● **राजेश बंसल,** इंदौर (म.प्र.)

राहुल का बदला स्वरूप

राहुल गांधी ने राजनीति का फंडा समझ लिया है, इसी वजह से वे सिर्फ रैलियां या फिर सोशल मीडिया के जरिए जनता से संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से तो सीधे जमीन पर जाकर लोगों से मुलाकात की जा रही है। जिन राहुल के लिए एसी रूम में बैठने वाले नेता जैसे बयानों का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने पैदल ही हजारों किलोमीटर की यात्रा कर डाली। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, नौजवानों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों से लेकर दलित-आदिवासी तक, राहुल ने सभी से मुलाकात की।

● **प्रवेश सिंह,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

छगन भुजबल नई पार्टी का आह्वान

महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल और नए खेमों का तैयार होना जारी है। मराठा आरक्षण आंदोलन का अब तक एकनाथ शिंदे सरकार कोई हल नहीं निकाल सकी है। इस बीच ओबीसी जातियों की खेमेबंदी नई टेंशन दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार में ही मंत्री छगन भुजबल इस खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है कि वह ओबीसी के नाम पर एक नई पार्टी या फिर मोर्चा भी खड़ा कर सकते हैं। 17 नवंबर को जालान में हुई ओबीसी रैली के बाद से इसके कयास लग रहे हैं। जालना की रैली में मौजूद कई वक्ताओं ने छगन भुजबल से ओबीसी मोर्चे की लीडरशिप संभालने के साथ-साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक की मांग की। महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल मराठा और ओबीसी खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ मनोज पाटिल के नेतृत्व में मराठा आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो वहीं छगन भुजबल और कांग्रेस नेता विजय वडेत्तिवार एक ओबीसी मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में हैं। दोनों नेता लंबे समय से साइडलाइन चल रहे हैं। ऐसे में इन्हें लगता है कि मराठा आंदोलन के मुकाबले वह ओबीसी जातियों को साथ ला सकते हैं। छगन भुजबल लगातार कहते रहे हैं कि मराठाओं को ओबीसी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो यह ओबीसी समाज के हक की कीमत पर होगा।

राकांपा में कोई टूट नहीं

राकांपा में टूट जगजाहिर है लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी में कोई टूट नहीं होने का दावा किया है। चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट ने फिर दलीलें रखीं। गुट ने कहा कि 30 जून से पहले जब राष्ट्रीय कार्यसमिति में शरद पवार को मुखिया माना गया था तो फिर पार्टी में टूट कहां से होगी। राकांपा का एक धड़ा अजित पवार की अगुवाई में भले ही पार्टी से अलग होकर महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गया है, लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने कहा कि पार्टी में न तो कोई टूट है, न ही कोई गुट है। ऐसे में जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं, वह गलत है। साथ ही यह भी कहा कि जब पार्टी में कोई टूट ही नहीं हुई है तो चुनाव आयोग इस मामले को सुन भी नहीं सकता है। राकांपा पर अधिकारों को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच चुनाव आयोग के सामने चल रही सुनवाई में शरद पवार गुट ने अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि 30 जून से पहले हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में सभी ने शरद पवार को पार्टी का मुखिया माना है। इनमें अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। ऐसे में पार्टी पर अधिकारों को लेकर जो दावेदारी की जा रही है, वह पूरी तरह से गलत है।

रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका!

लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी करीब पांच महीनों का समय है लेकिन उप्र का किला फतह करने के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीति बना रही हैं। इस बार प्रमुख सीटों के साथ रायबरेली और अमेठी पर भी सबकी नजरें हैं। चर्चा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2024 में चुनाव लड़ने की असमर्थता को देखते हुए इस बार पार्टी रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। खबर है कि सोनिया अपनी खराब सेहत की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले दिनों कांग्रेस की एक बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अमेठी संसदीय क्षेत्र से और प्रियंका गांधी को रायबरेली संसदीय क्षेत्र से आगामी आम चुनाव में खड़ा करने की मांग की थी। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर राहुल और प्रियंका इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो इससे उप्र में कांग्रेस को फायदा होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल ने अमेठी और केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल किया था। अमेठी में उनको भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार मिली थी, लेकिन वायनाड में भारी मतों से जीते थे। ऐसे में देखना होगा कि वो फिर अमेठी से लड़ते हैं या नहीं।

वर्गीय गोलबंदी

राजस्थान विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। मगर इस अभियान के दौरान जातीय और वर्गीय गोलबंदी की दिखी झलक से साफ है कि राजनीतिक पार्टियों की सियासी किस्मत तय करने में इस गोलबंदी की खास भूमिका होगी। खास बात यह है कि चुनाव अभियान में नजर आई इस दो स्तरीय गोलबंदी में सत्ता की दावेदार दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा की अपनी-अपनी पैठ और हिस्सेदारी है। शहरी इलाकों में भाजपा की पैठ कायम है और शहरी वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस को अब भी काफी परिश्रम की दरकार नजर आ रही है। इसी तरह राजस्थान के ग्रामीण बहुल इलाकों में कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पैठ से जूझना पड़ रहा है। राजस्थान के मतदाताओं की गोलबंदी का यह स्वरूप ही चुनाव को रोचक बना रहा, जिसमें दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने लिए अवसर देख रही हैं। यही वजह रही कि चुनाव अभियान के अंतिम दो-तीन दिनों में दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने आखिरी दांव के तौर पर तीखे शब्द बाणों के तीर चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

फ्रंटफुट पर ममता

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दलों की नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर है जिसमें कुछ ही महीने बाकी हैं। इससे पहले कई राज्यों में केंद्र और राज्यों में टकराव तेज हो गया है। नया मामला पश्चिम बंगाल का है जहां एक बार फिर ममता बनर्जी केंद्र के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही हैं। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे ईडी और सीबीआई टीएमसी नेताओं के साथ कर रही है। अब जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी छोड़ने के बाद से परेशान करने वाले और मनगढ़ंत मामलों का सामना करना पड़ा है।

साहब के रसूख की दमदारी

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक अधिकारी के रसूख की खूब चर्चा हो रही है। आलम यह है कि साहब के रसूख के कारण नियम-कायदों को ताक पर रखकर उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। कृषि प्रधान प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार किसानों को खुशहाल बनाने का दावा कर-करके थक गई है, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस है। वहीं दूसरी तरफ किसानों की उपज को रखकर साहब मालामाल हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार के घर में महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ साहब पर सरकार की खास कृपा है। इस कृपा का फायदा उठाते हुए साहब ने कई जिलों में वेयरहाउस बनवा लिए हैं। आज स्थिति यह है कि जब भी किसानों की फसल आती है तो सरकारी खरीदी के बाद सबसे पहले साहब के वेयरहाउस भरे जाते हैं। यही नहीं जब उपार्जित अनाजों को सप्लाई करने या बेचने की बात आती है तो सबसे पहले साहब के वेयरहाउस को खाली कराया जाता है। सूत्रों का कहना है कि साहब इस खेल में जमकर कमाई कर रहे हैं। आलम यह है कि साहब ने एक जिले में तो 4-4 वेयरहाउस बनवा रखे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कई लोगों ने किसानों की फसल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से वेयरहाउस बनवा रखे हैं। लेकिन हर किसी का भाग्य साहब जैसा प्रबल नहीं है। किसी-किसी के वेयरहाउस में तो किसी साल कोई फसल नहीं पहुंच पाती है। वहीं साहब जमकर चांदी काट रहे हैं।

सीएम का पीएस बनने की जुगाड़

प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी...मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह तो 3 दिसंबर और उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन भावी सरकार में अहम पद पाने के लिए अफसरों की भाग-दौड़ तेज हो गई है। इन्हीं अफसरों में दो आईएएस अफसर तो ऐसे हैं जो सीएम का पीएस बनने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये दोनों आईएएस अधिकारी चाहते हैं कि इस बार सीएम का सानिध्य उन्हें हर हाल में मिले, ताकि भावी सरकार में वे अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। गौरतलब है कि किसी भी सरकार में सीएम का पीएस होना किसी भी अफसर के लिए गौरव की बात तो है ही, साथ ही उस अफसर के पास शक्तियों की भरमार भी आ जाती है। इसलिए लगभग हर अफसर की कोशिश रहती है कि वह सीएम का पीएस बने। पुरानी सरकारों में सीएम के पीएस का पावर देख चुके दोनों आईएएस अधिकारी जुगाड़ में लग चुके हैं। इनमें से किसकी जुगाड़ लगेगी या दोनों खाली हाथ रह जाएंगे यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन अफसरों की लालसा देखकर हर कोई हैरान है और तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहां बता दें कि ये दोनों आईएएस अधिकारी महाकौशल क्षेत्र के सबसे चर्चित और अपने विकास मॉडल के लिए ख्यात जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं।

साहब की कमाई माफिया ने दबाई

प्रदेश के प्रशासनिक मुख्यालय में पदस्थ एक साहब इन दिनों काफी हैरान-परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि साहब ने अपनी काली कमाई से अपने एक दोस्त के नाम पर कुछ जमीनों की खरीदी की। अब वही दोस्त साहब को दगा दे गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासनिक मुखिया के बाजू में रहने वाले इन साहब ने एक शराब माफिया से दोस्ती कर ली। यह दोस्ती इतनी प्रगाढ़ होती चली गई कि साहब उक्त व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। उक्त व्यक्ति ने साहब को सब्जबाग दिखाते हुए उन्हें एक बड़े भू-भाग पर इन्वेस्ट करने को कहा। साहब को भी अपने दोस्त का आईडिया भा गया। उनके दोस्त ने बताया था कि उक्त जमीन पर प्लॉटिंग कर एक का दस कमाया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में रहने के कारण साहब ने उक्त भू-भाग को अपने नाम से खरीदना उचित नहीं समझा और उसे अपने माफिया दोस्त के नाम पर खरीद लिया। यानी पैसा साहब का और जमीन माफिया के नाम पर। अब उक्त शराब माफिया ने साहब को जमीन देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि उस जमीन पर प्लॉटिंग नहीं हो सकती। अब दोस्त की दगाबाजी से साहब हैरान और परेशान हैं। उधर, स्थिति यह है कि साहब इस मामले में कुछ करने की स्थिति में भी नहीं हैं, क्योंकि भू-भाग तो माफिया के नाम पर ही है। अब साहब बीच का रास्ता निकालने की जुगाड़ में हैं।

माननीय को सांप सूंघ गया...

ग्वालियर-चंबल अंचल से आने वाले एक नेताजी का हावभाव और स्वभाव देखकर लोग अब कहने लगे हैं कि लगता है कि माननीय को सांप सूंघ गया है। जिस माननीय की यहां बात हो रही है, वे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दरअसल, विगत दिनों माननीय जब कैबिनेट बैठक में शामिल होने आए थे तो उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मंत्री जी जैसे आए थे, वैसे ही बिना किसी से मेल मुलाकात और बातचीत किए चले गए। मंत्री जी की यह हालत देखकर हर कोई चकित नजर आया। किसी की समझ में यह नहीं आया कि हमेशा कैबिनेट की बैठक या किसी भी अन्य मौके पर सभी से मिलने-जुलने वाले साहब इतने शांत क्यों थे। जब खबरचियों ने इसकी पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि मंत्रीजी पर इस समय हार का डर छाया हुआ है। इस कारण वे किसी से मिलने से कतरा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार में पहली बार मंत्री बनने के बाद से माननीय का रसूख तेजी से बढ़ा। सरकार में वे फ्रंटफुट पर नजर आते रहे। हर बात में वे आगे बढ़-चढ़कर रहते थे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि चुनावी साल में माननीय को रिपोर्ट मिली है कि इस बार चुनाव में उनको हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। तब से ही साहब की रौनक चली गई है।

सर्वे की सफाई

हमारे देश में एक कहावत है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। उसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि देश में संस्कृति और नैतिकता के परचम तले राजनीति करने वाली पार्टी को भी सत्य से परहेज रहता है। इसका ताजा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में संस्कृति और नैतिकता की बात करने वाली पार्टी की सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से चुनावी सर्वे कराकर अपनी स्थिति का आंकलन करवाया था। इन्हीं एजेंसियों में एक थी इंटेलिजेंस। बताया जाता है कि इंटेलिजेंस ने चुनाव में सरकार की स्थिति का आंकलन किया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। यानी सर्वे में सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी हार होना बताया गया। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई सरकार को सांप सूंघ गया। ऐसे में पार्टी आलाकमान को हकीकत से दूर रखने और चुनावी जीत का जुगाड़ लगाने के लिए सरकार ने इंटेलिजेंस को अपनी रिपोर्ट बदलने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि इंटेलिजेंस ऐसी रिपोर्ट बनाए जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी का आसानी से जीत मिलता दिखे। जानकार अब इस खोजबीन में जुट गए हैं कि आखिर सरकार ने सत्य का छुपाने के लिए ऐसा क्यों किया है?

ईमानदार अफसर निशाने पर

9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ अफसरों ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई अफसरों ने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया, जो राजनीतिक दलों को पसंद नहीं है। ऐसे अफसरों के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई। लेकिन अफसरों की ईमानदारी को देखते हुए आयोग ने उन्हें क्लीनचिट दे दी। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। उसके बाद जो भी सरकार बनेगी वह इन ईमानदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसकी आशंका अभी से जताई जा रही है।

चुनाव बाद ईमानदार अफसरों की स्थिति क्या होगी इसका संकेत पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दे दिया है। उनकी मानें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनवा रहे हैं। भाजपा का हथियार बनकर काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी भी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। रणनीति बनाएंगे कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो, कहां पदस्थापना की जाए। वर्मा का कहना है कि अफसरों-कर्मचारियों की सारी सूची कमलनाथ के पास आती जा रही है। एक-दो दिन में सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। अखिल भारतीय सेवा के अफसरों पर सबूतों के साथ डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को जानकारी देकर कार्रवाई कराने के सवाल पर वर्मा ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ रिपोर्ट देखेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप के साथ मंथन कर निर्णय लेंगे कि क्या किया जाना है। भाजपा में भी कुछ यही स्थिति है।

सूत्रों की मानें तो जिन अफसरों ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर ईमानदारी के साथ काम किया है, वे राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर हैं। चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों में अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी हुआ। कुछ स्थानों पर कलेक्टरों और पार्टी उम्मीदवारों के बीच झड़प भी हुई। दोनों दलों ने कई कलेक्टरों और एसपी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। यह इस बात का संकेत है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार चाहे जिसकी बने, अफसरों पर गाज गिरना तय है। इसमें उन अफसरों की ज्यादा मुसीबत है, जिन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार छतरपुर जिला प्रशासन ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर अपराधों के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी नाराज हैं। नाराजगी का कारण यह है कि बिना जांच किए कांग्रेस पार्टी के दबाव में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। लेकिन इससे कांग्रेस भी नाराज है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में देरी की और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद दिग्विजय सिंह ने खजुराहो पहुंचकर धरना भी दिया। अब सरकार चाहे जिसकी बने, छतरपुर जिले के कलेक्टर व एसपी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। भिंड कलेक्टर व एसपी के खिलाफ सत्तारूढ़ दल भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को शिकायत की है कि प्रशासन की सख्ती के कारण लोग मतदान नहीं कर पाए। मुरैना कलेक्टर व एसपी की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुत नाराज हैं। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने तो चुनाव परिणाम के बाद कलेक्टर-एसपी को देख लेने तक की धमकी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से दिमनी के भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए कार्य कर रहा है। इंदौर कलेक्टर की भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत की है और कहा कि वे भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। धार एसपी पर भी कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के लिए खुलेआम काम करने का आरोप लगाया है। सीधी एसपी और कलेक्टर की मनमानी से कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट से प्रत्याशी अजय सिंह तथा पूर्व मंत्री व सिंहावल से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल काफी नाराज हैं। सीधी कलेक्टर व एसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायतें की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह व कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के बीच जिस तरह से बहस हुई वह सबके सामने है। इससे यह साफ है कि 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम के बाद सरकार जिसकी भी बने कुछ अफसरों का नपना तय है। नपने का मतलब अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा।

● सुनील सिंह

अफसर भी लगा रहे गणित

मप्र में मतदान का नया रिकॉर्ड क्या बना समीकरण भांपने वाले अफसर भी न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। अधिकांश अफसरों को समझ नहीं आ रहा है कि झुकाव किस ओर रखा जाए। ऐसे में अफसरों ने बीच का रास्ता निकालना शुरू कर दिया है और ये रास्ता है न्यूट्रल बने रहना। ऐसे अफसर बड़े नेताओं तक भी सूचना पहुंचा रहे हैं कि आचार संहिता की मर्यादा के कारण उन्हें न्यूट्रल बना रहना पड़ रहा है। उधर, नई सरकार में काम और विकास का खाका कैसा होगा। लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे इन्वेस्टर्स ने इसका खाका तैयार करके रखा है। वहीं पुराने स्तंभ भी अपनी नई प्लानिंग पूरी कर चुके हैं। वेटिंग और रनिंग मैनेजर्स की प्लानिंग बनकर तैयार है अब इंतजार हो रहा है तो सिर्फ नतीजों का। अब जिस पाली के पक्ष में नतीजे आएंगे उनके प्लेयर्स के चौके-छक्के लगना तय है।

644 स्कूलों का होगा कायाकल्प

मप्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सीएम राइज स्कूलों के साथ ही अब पीएम-श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की योजना बनाई है। योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में पीएम-श्री स्कूल स्थापित होंगे। जानकारी के अनुसार पीएम-श्री योजना के तहत प्रदेश के 644 स्कूल अपग्रेड होंगे। हर ब्लॉक से दो स्कूल चयनित किए गए हैं। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रदेश में 219 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 से 2026 तक पीएम-श्री योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से देशभर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम-श्री योजना के तहत प्रदेश के 644 स्कूल अपग्रेड होंगे। हर ब्लॉक से दो स्कूल चयनित किए गए हैं। पहले चरण में 416 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। अधिकारियों के अनुसार, इन चयनित स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय (केवी) की तरह बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। यकीन है कि पीएम-श्री योजना से लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई थी। इसका मकसद स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना था, जिससे बच्चों को ज्यादा सुविधा मिल सके। पीएम मोदी ने कहा था कि पीएम-श्री योजना भी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। पीएम-श्री योजना के तहत विद्यालयों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्ष, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक वातावरण बनाया जाएगा। सीखने एवं अलग अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था होगी। साथ ही समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रैक्टिकल, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई व्यवस्थाएं भी होंगी, जो शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होंगी। इसमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल मैदान, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 का अनुपात

पीएम-श्री स्कूलों का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी। इन स्कूलों पर सालाना खर्च 277.40 करोड़ रुपए होगा, जिसमें से 110.96 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। बता दें कि यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है, जिस दौरान राज्य सरकार इस पर 554.80 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 5 साल बाद इन स्कूलों का प्रबंधन पूरी तरह राज्य सरकार करेगी। पीएम-श्री स्कूल एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य उन स्कूलों को विकसित करना है, जहां हर छात्र देखभाल महसूस करता है। पीएम-श्री स्कूलों में छात्रों को सीखने का एक सुरक्षित और उत्तेजक माहौल मौजूद है, जहां सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है और जहां अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन अनुकूल है। पीएम-श्री की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह सीखने के लिए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि छात्रों को इस तरह से बनाया जाए कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनें। फिलहाल सरकार को पूरे देश में 20 लाख से अधिक छात्रों के इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है।

स्कूल शिक्षा विभाग को पीएम-श्री योजना की कार्ययोजना वर्ष 2024-25 के लिए दिसंबर में भारत सरकार को प्रस्तुत करनी है। विभाग ने आदेश जारी कर स्कूलों के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूर्ण कर फोटो उपलब्ध कराने को कहा है। राजधानी के महारानी लक्ष्मी बाई (एमएलबी) कन्या उमावि, बरखेड़ा को पीएम-श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। इस स्कूल को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। अन्य विकासखंडों में स्कूलों का चयन किया जा रहा है। पीएम-श्री योजना के तहत एक विकासखंड में एक प्रायमरी-मिडिल स्कूल और एक हाई या हायर सेकंडरी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। इस तरह प्रदेश के 322 ब्लॉक में दो-दो स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 219 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

जानकारी के अनुसार स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक ढांचा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों की झलक इन स्कूलों में होगी। ये स्कूल आसपास के अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे। इनमें अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे कि विद्यार्थी किताबों के अलावा प्रैक्टिकल से भी सीख सकें। प्री-प्रायमरी एवं प्रायमरी के बच्चों के लिए खेल पर विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास किया जा सके। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी का कहना है कि जानकारी के अनुसार पीएम-श्री योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 416 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है। इसकी वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि 27,360 करोड़ की लागत से 2022 से 2027 तक 146,00 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में दो स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों का चयन राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल की गुणवत्ता को देखकर ही किसी भी स्कूल का चयन होगा। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्कूलों में गुणात्मक वृद्धि हो। साथ ही बच्चे 12वीं पास करते-करते दुनिया के अंदर कॉम्पटेटिव तरीके से तैयार हो जाएं यही इसका मकसद है।

● राजेश बोरकर

मप्र में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। चुनावी समर में अपनी-अपनी जीत के लिए पार्टियों ने वादों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस अपने वचन पत्र तो भाजपा संकल्प पत्र के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। संकल्प पत्र बनाम वचन पत्र की जंग में प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता किस पर विश्वास जताकर जीत की सौगात देते हैं यह तो अब 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा।

चुनावी वादे कितने खरे...

विधानसभा चुनावों के दौरान वादों की फेहरिस्त काफी लंबी हो चली है। 12वीं पास को स्कूटी, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 या 2,900 रुपए क्विंटल के अलावा बोनस की भी अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 साल में किए गए चुनावी वादे कहां तक पूरे हो पाए? नरेंद्र मोदी जैसे प्रभावी नेता और पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद दस साल का हिसाब-किताब लगाना जरूरी है। आंकड़ों के खेल से देश को भ्रमित करना भले जारी रहे, पर कोरोना के रूप में वैश्विक महामारी हो या आर्थिक मंदी का दौर, पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू स्तर पर बढ़ती हिंसा हो, पड़ोसी राज्यों के साथ बढ़ता सीमा विवाद या कूटनीतिक रिश्ते, देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या हो या किसानों की बढ़ती आत्महत्या-मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल ही दिखी है। आज भी देश को कृषि, रोजगार, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सामाजिक-असामंजस्य की समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है।

वर्ष 2004-05 में कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 21 प्रतिशत था। पिछले 18 साल में यह घटकर करीब 16 फीसदी रह गया है। लेकिन खेतों में कार्यबल की संख्या में उस हिसाब से गिरावट नहीं आई है। कृषि देश में करीब 55 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती है। इस क्षेत्र में अनुमानित 26 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यानी करीब 55-57 प्रतिशत आबादी की कृषि पर निर्भरता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान लंबे समय से संकट में है। मोदी सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसानों को उनकी खेती से लाभकारी मूल्य तो दूर, पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा। जी-20 समिट के दौरान किए गए कृषि व्यापार समझौते से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के अनुसार, सरकार ने कई कृषि उत्पादों और पोल्ट्री उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जिससे खासकर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के सेब उत्पादकों पर संकट है।

हर वर्ग पर फोकस

कांग्रेस ने जहां अपने वचन पत्र में 11 गारंटियां दी हैं, वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 10 संकल्प लिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। इसकी टैग लाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। गरीब, किसान लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। संकल्प पत्र में 10 मुख्य संकल्प लिए गए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था। इसमें 11 मुख्य गारंटियों के साथ 101 वादे किए गए हैं। यानी मिशन 2023 का घमासान कांग्रेस की गारंटी बनाम भाजपा के संकल्प के बीच है। ऐसे में मतदाता ने किस पर अपनी मुहर लगाई है यह 3 दिसंबर का साफ हो जाएगा। अगर कांग्रेस के वचन पत्र और भाजपा के संकल्प पत्र का आंकलन करें तो हम पाते हैं कि मप्र में 2023 के चुनाव में भाजपा-कांग्रेस दोनों दलों का पूरा फोकस केवल महिला वोटर पर है। पहले से ही लाड़ली बहनों को गेमचेंजर मान रही भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद के साथ अब पक्के मकान का वादा भी कर दिया है।

देश के 16 करोड़ किसानों पर सभी प्रकार के बैंकों का करीब 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है-यानी प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपए है। कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की श्रेणी में वर्ष 2021 में 10,881 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 5,318 किसान थे और 5,563 खेतिहर मजदूर। उसी साल देश में जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, उनमें से 42,004 दिहाड़ी मजदूर थे, जबकि 4,246 महिलाएं थीं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में अभी 23 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद खराब है। रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 से 2015-16 तक देश में गरीबी से 27.5 करोड़ लोग बाहर आए, जबकि 2015-16 से 2019-21 तक 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा गांवों और शहरों में विकास की खाई को भी दिखाता है। गांवों में रहने वाले 21.2 प्रतिशत लोग गरीब हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 5.5 फीसदी है।

सालाना दो करोड़ नौकरियों के वादे और अच्छे दिन के नारे ने 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में ला दिया था। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 की नोटबंदी और 2017 के जीएसटी रोलआउट के दुष्प्रभावों के कारण 2018 में करीब 1.1 करोड़ नौकरियां चली गईं। इंडिया

स्पेंड के विश्लेषण के मुताबिक, रोजगार के बाजार में हर साल प्रवेश करने वाले 1.2 करोड़ लोगों में से केवल 47.5 लाख लोग ही श्रम बल में शामिल होते हैं। यूपीए सरकार के दशक में गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना 75 लाख नौकरियों का सृजन हुआ; जबकि 2013-19 की अवधि में कोविड से पहले केवल 29 लाख गैर-कृषि नौकरियां सृजित हुईं (सरकारी पीएलएफएस डेटा के आधार पर)। 2004 से 2019 के बीच ग्रामीण/शहरी भारत में शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ी, और फिर आर्थिक और स्वास्थ्य कुप्रबंधन के कारण कोविड के दौरान और भी अधिक बेरोजगारी बढ़ी। वर्तमान सरकार में युवा बेरोजगारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है। दूसरी ओर, वास्तविक वेतन वृद्धि भी तेजी से धीमी हो गई है।

विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। परिणाम आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। इस बीच मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों दलों ने अपना-अपना दांव चला। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटियां हैं। वहीं भाजपा ने 96 पेज के संकल्प पत्र में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े चार लाख शासकीय पदों को 6 महीने में भरने का वचन अपने पत्र में शामिल किया है। इसके साथ ही सरकार बनने पर युवाओं के लिए ही स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात भी वचन पत्र में जोड़ी है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रेजुएट युवाओं को 3 हजार रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए, जबकि दो लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 8 से 10 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। इसके लिए युवा स्वाभिमान योजना कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं भाजपा ने मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा टैग लाइन से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। गरीब, किसान से लेकर लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाड़ली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा

किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर मप्र के हर संभाग में मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू करेंगे।

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। भाजपा की सरकार आई तो गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के साथ ही धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। साथ ही जबलपुर और ग्वालियर में नई मेट्रो बनाने की भी घोषणा की है, इसके अलावा सिंगरौली और रीवा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। साथ ही गरीबों को राशन में तेल और शक्कर की किट दी जाएंगी। आईआईए के अलावा स्कूल में मिड-डे मील के साथ नाश्ता भी देंगी। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार की 18 साल की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि दूसरे दल जनता से वादा कर भूल जाते हैं। हम अपना संकल्प पत्र जारी कर इसका क्रियान्वन करने के लिए सब कमेटी बनाकर मॉनिटरिंग भी करते हैं। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी यह 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही है। भोपाल-इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेंगे। किसानों को लुभाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा रेट पर गेहूं और धान खरीदने की गारंटी दी है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 2600 रुपए में गेहूं, तो धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की बात कही थी। भाजपा ने गेहूं 2700, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया है।

भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वो मप्र का विकास हो या अन्य किसी प्रदेश के विकास की बात हो, उसके मूल में हमेशा गरीब कल्याण की बात होती है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हमारा मंत्र है- रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। 2003 में मप्र में औद्योगिक विकास की दर 0.61 प्रतिशत थी, जो आज भाजपा सरकार के 20 साल के कार्यकाल में बढ़कर 24 प्रतिशत हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि 2003 में यहां 4,231 हेक्टेयर जमीन की ही सिंचाई हो पाती थी, जो आज बढ़कर 16,284 हेक्टेयर हो चुकी है। इस बार के संकल्प पत्र में 1 करोड़ 30 लाख बहनों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ हम घर की सुविधा भी देंगे। नड्डा ने कहा कि गांव की बहनों को लखपति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलमपेंट का काम शुरू किया जाएगा। गेहूं की खरीदी हम 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और धान की खरीदी हम 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हम 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे।

● कुमार राजेन्द्र

सबका साथ सबका विकास

भाजपा ने घोषणा की है कि 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए सभी गरीब परिवारों को मुक्त राशन एवं रियायती दरों पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रह सके इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे। वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करते हुए 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे। कारीगरों को 15000 की वित्तीय सहायता, 500 का दैनिक भुगतान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक कारीगर समूह को लाभ मिलेगा। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। गिग वर्कर्स के कल्याण एवं अधिकारियों की देखरेख के लिए गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे।

मेट्रो का कामर्शियल रन अप्रैल में

विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल-इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो गया है। अब इसके कामर्शियल रन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर में सुभाष नगर डिपो से एम्स अस्पताल साकेत नगर तक आवश्यक सिविल वर्क पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। जिससे लोकसभा चुनाव से पहले मेट्रो का कामर्शियल रन भी शुरू किया जा सके। हालांकि कामर्शियल रन शुरू होने के एक महीने तक यात्रियों से किराया नहीं वसूला जाएगा, बल्कि उन्हें जाय राइड कराई जाएगी।

बता दें कि वर्तमान में एम्स से सुभाष नगर तक करीब सात किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक तैयार हो गया है। इसमें सुभाष नगर से रानी कमलापति तक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण का काम भी किया जा चुका है। यहां अभी मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल किया जा रहा है। जबकि रानी कमलापति से हबीबगंज नाके के बीच रेलवे लाइन के ऊपर स्टील ब्रिज का निर्माण होना है। जो आखिरी जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मप्र मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल में पहले चरण के संचालन के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर का 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसमें तीन माह तक ट्रायल रन करने के बाद मार्च 2024 में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त इस मार्ग की संरक्षा को परखेंगे। उनके संतुष्ट होने के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो संचालन की अनुमति दी जाएगी।

देश में मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम भी करीब 10 प्रतिशत बचा है। इसके पूर्ण होते ही कामर्शियल रन के लिए टेस्टिंग की जाएगी। अधिकारी संभावना जता रहे हैं कि अप्रैल 2024 के आखिरी सप्ताह तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रायोरिटी कॉरिडोर में एम्स से सुभाष नगर के बीच कुल आठ स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, सरगम टॉकीज, डीबी माल, केंद्रीय विद्यायल और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। जबकि हबीबगंज नाका, अलकापुरी और एम्स अस्पताल के पास मेट्रो स्टेशन का काम तीव्र गति से किया जा रहा है।

भोपाल मेट्रो में दिव्यांगों के लिए यात्रा करना आसान होगा। यहां स्टेशन, लिफ्ट और टिकट काउंटर पर दिव्यांगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहां दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सीढ़ियों के साथ दिव्यांगों के लिए अलग से साइड रेलिंग और नीचे चलने के लिए विशेष प्रकार की टाइल्स लगाई जाएगी। जिससे दिव्यांग बिना किसी सहयोगी के मेट्रो रेल से आवागमन कर सकेंगे।

गौरतलब है कि भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना की मंजूरी 30 नवंबर 2018 को मिली थी। 19 अगस्त 2019 को एमओयू साइन हुआ था। ज्वांइट वेंचर की पहली बैठक 29 दिसंबर 2020 को हुई थी। निर्माण के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर में ट्रायल रन की समय सीमा सितंबर 2023 थी। मेटो प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,941 करोड़ रुपए है। भोपाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.2 किलोमीटर का है। मप्र मेट्रो एमडी मनीष सिंह का कहना है कि मप्र मेट्रो का ट्रायल रन निर्धारित समय के अनुसार किया गया है। अब हमारी कोशिश है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर में कामर्शियल रन भी जल्द शुरू कर दें। इसके लिए जो भी काम बचे हैं, उसे समय सीमा में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों और कांट्रेक्टर को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शहर के गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक-तीन के बीच 5.9 किलोमीटर के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गलियारे पर तीन डिब्बों वाली मेट्रो रेल का प्रायोगिक परीक्षण (ट्रायल रन) किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल की सवारी भी की। इसके तहत शहर में करीब 31.50 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने शहर में कुल 1,483.48 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग-अलग परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें लव-कुश चौराहे पर बनने जा रहा प्रदेश का पहला डबल डेकर (बहुस्तरीय) फ्लाईओवर शामिल है। देश के तेजी से विकसित हो रहे प्रदेशों में मप्र इस समय सबसे आगे दौड़ रहा है। यहां होने वाले नवाचारों से अर्थव्यवस्था तो बेहतर हो ही रही है, आमजन के लिए सर्वसुविधाएं भी सुलभ होने लगी हैं। इसी कड़ी में मप्र ने विकास की राह में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन के साथ ही लोक परिवहन के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हो गई। इंदौर और भोपाल में मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है। इसके बाद जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रो जैसे तेज परिवहन माध्यम की सौगात मिलेगी।

● श्याम सिंह सिकरवार

मेट्रो में लगाई जाएंगी ब्रेल लिपि की पट्टिकाएं

प्राचीन काल के समाज में दिव्यांगता को एक कलंक माना जाता था। परंतु धीरे-धीरे समय बदलने के साथ सरकार के प्रयास और समाज में जागरूकता के चलते अब दिव्यांगों को सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। दिव्यांगों ने ज्यादातर क्षेत्रों में अपना परचम लहराकर अपना सम्मान हासिल किया है। ऐसे में दिव्यांगों की सुविधाओं को देखते हुए हर दफ्तर, सरकारी भवन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्था भोपाल-इंदौर मेट्रो में देखने को मिलेगी। मेट्रो में दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के लिए स्टेशन पर प्रवेश से लेकर कोच तक और कोच से लेकर वापस उतरने तक हर जगह ब्रेल लिपि की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। वहीं अन्य दिव्यांगजनों के लिए रैंप, व्हील चेयर से आ-जा सकने सहित अन्य सुविधाएं तैयार की जाएंगी। मेट्रो के सफर में दिव्यांग अपने आपको असहज महसूस नहीं करेंगे। मेट्रो के संचालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (सीएमआरएस) की गाइडलाइन के हिसाब से सभी मेट्रो स्टेशन पर दिव्यांगों की सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 30 सितंबर को मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल किया जा चुका है। जल्द ही लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलने लगेगी। बताया गया कि आर्थिक टीम की बैठक के बाद दिव्यांगों के लिए किराए में कुछ छूट भी दी जा सकती है।

मंत्रालय में अटका ई-ऑफिस सिस्टम

मंत्रालय के कामकाज में तेजी एवं पारदर्शिता लागू करने सरकार ने 6 साल पहले ई-ऑफिस की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है। इस कारण आज भी मंत्रालय में फाइलें मैनुअल ही चल रही हैं। ऐसे में कौन सी फाइल कहां है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जबकि प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम की बात करें तो मप्र राज्य निर्वाचन आयोग राज्य मंत्रालय समेत अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए मिसाल बन गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है। यहां फाइलों का मूवमेंट ऑनलाइन किया जा रहा है। खास बात यह है कि आयोग ने उपलब्ध संसाधनों में यह कारनामा कर दिया है। ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने के लिए आयोग ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इसके उलट प्रदेश में दो सरकारें बदल गईं, लेकिन मंत्रालय समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू नहीं हो पाया।

गौरतलब है कि मंत्रालय में वर्ष 2017 से ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने की कवायद चल रही है। इसके लिए नए कम्प्यूटर और स्कैनर खरीदे गए थे। अपर मुख्य सचिव से लेकर सहायक ग्रेड एक तक के कर्मचारियों को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया था। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में मार्च, 2018 में मंत्रियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया गया था और यह भी तय हुआ था कि कैबिनेट का एजेंडा भी मंत्रियों को ऑनलाइन भेजा जाएगा, लेकिन न अधिकारियों ने और न ही मंत्रियों ने फाइलों के ऑनलाइन मूवमेंट में कोई रूचि दिखाई।

सरकार ने तय किया था कि मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद पहले इसे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में और फिर जिला कार्यालयों में लागू किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-ऑफिस सिस्टम से हर स्तर पर जवाबदेही तय हो जाएगी। मंत्रियों, अफसरों के सामने एक क्लिक पर फाइल उपलब्ध होगी। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर अवधि तय है। इसके बाद भी फाइलें लंबित रहती हैं। इस व्यवस्था में हर फाइल का मूवमेंट ऑनलाइन होने से वरिष्ठ स्तर से पूछताछ भी की जा सकेगी। इस व्यवस्था से यह भी पता चलता रहेगा की फाइल किस स्तर पर कब से लंबित है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2018 में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के निर्णय के कुछ महीने बाद ही सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और यह सिस्टम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल, अधिकारियों-कर्मचारियों के कम्प्यूटर पर काम करने में पारंगत नहीं होने की वजह से फाइलों की गति धीमी पड़ गई थी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब होने का जोखिम सरकार चुनाव के वक्त नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए तत्कालीन मुख्य सचिव बीपी सिंह ने इसे ऐच्छिक कर दिया था। जबकि इस व्यवस्था को लागू करने सभी विभागों में कम्प्यूटर और स्कैनर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुके हैं। ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने से मंत्रालय में फाइलों की रफ्तार बढ़ जाएगी। क्योंकि हर फाइल की लोकेशन अपडेट रहेगी। ई-प्रणाली में लिपिक से लेकर मुख्य सचिव तक फाइल को निपटाने की समय-सीमा तय है। बिना किसी कारण के फाइल को नहीं रोका जा सकेगा। पिछले साल ई-ऑफिस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य विभागों से बेहतर काम किया था। लेकिन अन्य विभाग फिसड्डी रहे। एक बार कोई भी दस्तावेज इसमें आ गया तो फिर चाहकर भी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकेगा।

ई-ऑफिस शुरू होने के बाद कागजी रिकॉर्ड रखने की समस्या खत्म हो जाएगी और हर साल हजारों टन कागज की बचत होगी। डाटा सुरक्षित रखने दो डाटा सेंटर बनेंगे। दूसरा डाटा सेंटर प्रदेश के बाहर बनेगा। यदि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी स्थिति में एक डाटा सेंटर नष्ट होता है, तब दूसरे डाटा सेंटर से डाटा रिकवर किया जा सकेगा। ई-ऑफिस सिस्टम में हर फाइल ट्रेस करना आसान है। संबंधित विभाग का अधिकारी या कर्मचारी किसी भी फाइल की लोकेशन ट्रेस कर सकता है। फाइल ओके होने के बाद उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। लिपिक से लेकर मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री तक फाइल निपटाने की समय-सीमा तय है। फाइल समय पर नहीं करने के लिए कारण भी बताना होगा। ई-ऑफिस की खास बात यह है कि किसी भी इमरजेंसी में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अधिकारियों को फाइल लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक क्लिक पर फाइल ओके होगी। यदि फाइल तत्काल कॉल बैक करनी है तो संबंधित कर्मचारी-अधिकारी को एसएमएस से इसकी सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं अधिकारी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर भी लैपटॉप पर फाइल ओके कर सकते हैं।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

पिछली सरकार में लागू हुई थी व्यवस्था

ई-ऑफिस व्यवस्था शिवराज सरकार में लागू हुई थी लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिवराज सरकार ने मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने के लिए करोड़ों खर्च कर हाईटेक कम्प्यूटर एवं प्रिंटर भी लगवाए। साथ ही अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर काम करने की ट्रेनिंग दी गई थी। कुछ महीनों के लिए मंत्रालय में ई-ऑफिस पर काम भी हुआ, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से ई-ऑफिस सिस्टम ठप हो गया। अधिकारियों-कर्मचारियों के कम्प्यूटर पर काम करने में पारंगत नहीं होने की वजह से फाइलों की गति धीमी पड़ गई थी और बात वहीं रह गई। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने की तैयारी की थी। सरकार ने तय किया था कि पहले चरण में 15 अगस्त, 2019 से मंत्रालय में, दूसरे चरण में 2 अक्टूबर, 2019 से ई-ऑफिस व्यवस्था विभागाध्यक्ष कार्यालयों में और तीसरे चरण में 1 जनवरी, 2020 से जिला कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मार्च, 2020 में कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के शुरुआती दो साल कोरोना से निपटने में बीत गए, पिछले डेढ़ साल से सरकार के चुनावी मोड में होने के कारण ई-ऑफिस सिस्टम लागू करना उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा। हालांकि जीएडी ने 19 जनवरी, 2021 को जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए थे। उन्हें जिला ई-ऑफिस कार्यप्रणाली पुस्तिका-2021 भी भेजी गई थी, लेकिन इस दिशा में जिलों में आगे गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई।

अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन डॉलर से कुछ अधिक की थी। अब आंकड़े बता रहे हैं कि भारत 18 नवंबर 2023 की देर रात को ही 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर बढ़ चला है। भारत अभी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जर्मनी इस मामले में चौथे नंबर पर है जिसकी अर्थव्यवस्था 4.28 ट्रिलियन डॉलर है। इसी तरह 4.39 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान तीसरे पायदान पर है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है अगर यह आगे भी कायम रहती है तो 2025 आते-आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 26.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका की है, वहीं दूसरे नंबर पर चीन है जिसकी अर्थव्यवस्था 19.24 ट्रिलियन डॉलर है।

देश पर ढाई सौ सालों तक शासन करने वाले अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत पिछले साल ही दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। 10 साल पहले जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, ब्रिटेन तब भी पांचवें नंबर पर था। वर्ष 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के समय भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, तब 3 ट्रिलियन डॉलर के साथ ब्रिटेन पांचवें स्थान पर था। फ्रांस, ब्राजील, इटली और रूस क्रमशः छठवें, सातवें, आठवें, और नौवें स्थान पर थे। पिछले 10 सालों में भारत एक-एक करके सबको पीछे छोड़ आज 4 ट्रिलियन डॉलर के सम्मानजनक स्तर को पार कर चुका है। फिलहाल विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान 3.6 प्रतिशत है जबकि 2014 में यह 2.6 प्रतिशत था। भारत के विकास की गति को देखते हुए पहले यह अनुमान लगाया गया था कि भारत 2027 तक दुनिया की चौथी और 2029 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। लेकिन ताजा आंकड़ों तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर के उत्साहजनक बयान से यह उम्मीद जगती है कि भारत समय से पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर इजराइल और हमास के बीच सीधी जंग के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा अन्य कारकों से दुनिया के अनेक हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं, जबकि भारत में लगातार कारोबारी माहौल बेहतर हो रहा है। विश्व बैंक के 10 मानदंडों के आधार पर इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी भारत ऊपर चढ़ा है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलाव की पटकथा 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लिखी गई। तत्कालीन वित्तमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह के साथ मिलकर नरसिम्हा राव ने देश को एलपीक्यूआई राज यानी लाइसेंस, परमिट, कोटा और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई और एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत को आत्मसात किया। यह बड़ा बदलाव था, क्योंकि आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति और अर्थनीति दोनों ही समाजवादी सोवियत रूस से प्रभावित थी। रूस की ही तरह भारत में ज्यादातर उद्योगों को सरकारी नियंत्रण के तहत रखे जाने के लिए तमाम जतन किए गए थे। बिजली, सड़कें, पानी, टेलीफोन, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल आदि सेवाएं सरकारी नियंत्रण में थी और निजी क्षेत्र को उद्योगों में निवेश की अनुमति नहीं थी या अगर कहीं थोड़ी बहुत अनुमति दी भी जाती थी तो उससे कुछ चहेतों को ही बढ़ावा मिला। यहां तक कि बैंकों को भी सरकारी नियंत्रण में रखा जाता था। इसका परिणाम हुआ कि अन्य पड़ोसी देश जहां लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रगति कर रहे थे और एशियाई शेर के तमगों से विभूषित किए जा रहे थे, वहीं भारत की आर्थिक विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास ही सिमटी रही। वर्ष 1951 से लेकर 1979 तक के बीच के तीन दशक सिर्फ समाजवादी नीतियों को सही साबित करने में निकल गए और इसका खमियाजा 0.1 प्रतिशत प्रति व्यक्ति विकास दर के रूप में देखने को मिला।

आर्थिक सुधारों के लिए छिटपुट प्रयास तब शुरू हुए जब 80 के दशक में देश के सामने भुगतान संतुलन का संकट गंभीर रूप लेने लगा। वर्ष 1991 में चंद्रशेखर सरकार के दौरान यह समस्या विकराल हो गई और शर्मनाक रूप से भारत का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा। इस समस्या का एकमात्र समाधान देश के बाजार को निजी और विदेशी निवेशकों के लिए खोलना था, जिससे अब तक की सरकारें मुंह मोड़ती आ रही थी। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार करने का फैसला लिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी नीत एनडीए की सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में सरकार की दखलअंदाजी और नियंत्रण को न्यूनतम करने का काम किया। वाजपेयी सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर पहली बार देश में विनिवेश के लिए अलग से मंत्रालय तक का गठन कर दिया। उसके बाद डॉ. मनमोहन सिंह और फिर पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाते रहे।

● **विकास दुबे**

जीएसटी से मिला दम

वर्ष 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने संपूर्ण भारत को एक समान बाजार में परिवर्तित कर दिया। व्यवसाय करने की सुगमता के लिए तमाम जतन करना और राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की स्थिति तैयार करने से भी अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। इन सुधारों और बदलावों का ही नतीजा है कि आजादी के समय 1947 में मात्र 2.5 लाख करोड़ वाली अर्थव्यवस्था 2023 का नवंबर महीना आते-आते 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कुलांचे भर रही है। सरकारी रिकॉर्ड में आजादी के समय प्रति व्यक्ति सालाना आय 274 रुपए थी, वह अब बढ़कर 2 लाख रुपए हो गई है, जिसके आजादी के 100 साल पूरा होने तक 15 लाख होने की उम्मीद है। आंकड़ों में भारत के विकास की चमक है। बेशक भारत ने आर्थिक उपलब्धि हासिल की है लेकिन आम भारतीय के हालात बहुत अच्छे हो गए हों, ऐसा नहीं है।

जनता से धोखा है चुनावी बॉन्ड योजना

इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए चांदी बनाने का जरिया बन चुका है। यह बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक ऐसा नया तरीका है, जिसका खेल आम लोगों की समझ से बाहर है। अब इसकी कुछ-कुछ जानकारियां छन-छनकर बाहर आ रही हैं, जिसे लेकर एक पढ़ा-लिखा वर्ग इस चंदे की गोपनीयता को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, जो कि राजनीतिक पार्टियों को खटक रहा है। हालांकि कुछ पार्टियां, जिन्हें इस बॉन्ड से बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है, वो भी इसे सार्वजनिक करवाना चाहती हैं, ताकि चुनावी बॉन्ड का बेजा फायदा उठाने वाली पार्टियों की पोल खुल सके। दरअसल चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जिनकी अवधि 15 दिनों की होती है।

चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल सिर्फ पंजीकृत और उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों में से कम-से-कम एक फीसदी वोट हासिल किए हों। चुनावी बॉन्ड को सरकार लोकसभा चुनाव के वर्ष में अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी कर सकती है। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल पहले चुनावी बॉन्ड लॉन्च किया गया था। यानी ये चुनावी बॉन्ड भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू कराया और हैरत वाली बात है कि आज भाजपा को देश की बाकी करीब 59 मान्यता प्राप्त सक्रिय राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा चंदा मिला है। यानी इन पांच वर्षों में अकेले भाजपा को आधे से ज्यादा चुनावी चंदा मिला है। लेकिन कोई भी पार्टी यह बताने को तैयार नहीं है कि उसे चुनावी बॉन्ड के जरिये कब, कितना चुनावी चंदा मिला? इसी के चलते चुनावी बॉन्ड की वैद्यता को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की जनहित याचिका के तहत दायर किया है।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हकीकत में चुनावी बॉन्ड योजना कॉर्पोरेट घरानों से रिश्वत लेने का एक तरीका है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानकारी के नागरिकों के मौलिक अधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला दिया और कहा कि अगर नागरिकों को उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है, तो उन्हें निश्चित रूप से यह भी जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले लोग कौन हैं? प्रशांत भूषण ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड एक अपारदर्शी योजना है, जिसकी वजह से सिर्फ सरकार को ही पता होता है कि किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिये कितना चंदा मिला? बाकी कोई पार्टी भी नहीं जान सकती कि इस बॉन्ड के जरिये किस पार्टी को कितना पैसा चंदे के रूप में मिला है? पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जिन पार्टियों को किसी कंपनी या पूंजीपति के द्वारा चंदा दिया गया है, मौजूदा मोदी सरकार ने उन पार्टी नेताओं के साथ-साथ चंदा देने वाली कंपनियों और पूंजीपतियों के खिलाफ भी कार्रवाई की कोशिश की है।

दरअसल हिंदुस्तान में गुप्त चंदे का मामला तो बहुत पहले से उठता रहा है; लेकिन उसमें तब भी मोटा-मोटी पता चल जाता था कि किस पार्टी के पास कितना चंदा आया या पार्टी की आमदनी कितनी है? उसके पास पैसा कितना है? लेकिन जबसे चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा मिलने लगा है, तबसे यह गोपनीयता और ज्यादा बढ़ गई है। आज तक केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं बताया कि भाजपा को अब तक कितना चंदा मिला है? चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते पांच वर्षों में देश की राजनीतिक पार्टियों को करीब 9,208.23 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। हालांकि जानकारों के मुताबिक यह जानकारी पुख्ता नहीं है और जहां तक चंदे का सवाल है, यह इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है।

● **रजनीकांत पारे**

5 सालों में 9 हजार करोड़ से अधिक का चंदा

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, सन् 2016 से सन् 2022 के बीच के पांच वर्षों में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियों और करीब 24 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 9,208.23 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। इस चंदे में से अकेले भाजपा को करीब 5,271.97 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 952.90 करोड़ रुपए से ज्यादा और बाकी करीब 2,983.36 करोड़ रुपए का चंदा बाकी की करीब 28 राजनीतिक पार्टियों को मिला है। यह हैरत की बात है कि इतने पर भी केंद्र की मोदी सरकार दूसरी पार्टियों के नेताओं के यहां छापेमारी कराने पर आमादा है और खुद कई बड़े और जरूरी सवालों के जवाब देने से भी साफ इनकार कर देती है, जिसमें कि पीएम केयर्स फंड की जानकारी नहीं देना भी शामिल है। बहरहाल चुनावी बॉन्ड मामले पर इसी साल 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि इससे एक दिन पहले ही अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने चुनावी बॉन्ड योजना के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह योजना राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को सफेद धन (व्हाइट मनी) के रूप में इस्तेमाल करने को बढ़ावा देती है और नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी जानने का सामान्य अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि यह बात समझ से परे है कि जो पार्टियां चुनावों में अनाप-शनाप काला धन उड़ाती हैं और जो राजनीति में आने से लेकर सत्ता में आने पर भी अपने खर्च और चंदे का हिसाब-किताब गड़बड़ रखती हैं, वो किस प्रकार से काले धन को सफेद धन में बदलेंगी?

किसान कैसे बनेगा खुशहाल...?

मप्र सहित देशभर में इस समय रबी फसलों की बुवाई हो रही है। प्रदेश को अब तक सात कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने वाले किसानों का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। किसानों के टारगेट को देखते हुए बीज कंपनियों ने भी अपना मायाजाल फैला दिया है। दरअसल, अधिक उत्पादन की आस में किसान कंपनियों से महंगा बीज खरीदने को मजबूर होता है और हर बार उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान खुशहाल कैसे बनेगा?

मप्र में इन दिनों रबी फसल की बोवनी का कार्य चल रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107 लाख 33 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 9-10 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3 लाख मीट्रिक टन एनपीके खाद की जरूरत पड़ती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण न सरकार और न ही प्रशासन का ध्यान इस ओर गया। एक तरफ चुनाव प्रचार होता रहा और दूसरी तरफ अन्नदाता रबी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करता रहा। जब खेत तैयार हो गया तो बुवाई के लिए खाद का संकट खड़ा हो गया। इसको देखते हुए गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के साथ बैठक की और खाद मुहैया कराने का निर्देश दिया। कृषि और सहकारिता विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि अब तक रबी फसल की 81 लाख 71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी हो चुकी है, जो गत वर्ष से 5.33 प्रतिशत अधिक है। उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। विपणन संघ के 422 विक्रय केंद्र संचालित हैं, विपणन सहकारी समिति के 154 विक्रय केंद्रों से नगद उर्वरक विक्रय आरंभ किया है। विपणन सहकारी समितियों द्वारा अतिरिक्त 92 विक्रय केंद्र आरंभ किए गए हैं और किसानों को लाइन से बचने के लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। लेकिन किसानों का उच्च किस्म का बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान बीज के लिए कारपोरेट पर आश्रित होता जा रहा है।

पैदावार बढ़ाने के बहाने देश में निजी बीज कंपनियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। देसी बीज के बदले पहले किसानों को उन्नत बीज दिए गए और अब संकर बीज के बहाने उनको निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। भारत में आदिवासी इलाकों में देसी बीज अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन अधिक उपज के लालच में किसान हाइब्रिड बीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हरित क्रांति के बाद आनुवांशिक रूप से समान आधुनिक किस्मों और अब संकर बीजों के कारण स्थानीय किस्मों में लगातार कमी आ रही है। दरअसल भारत में हाइब्रिड बीजों के प्रति किसानों का मोह बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि हाइब्रिड बीजों वाली फसल न केवल जल्दी पककर तैयार हो जाती है, बल्कि देसी बीजों के मुकाबले अधिक उपज भी देती है। बालाघाट जिले के किसान मंजीत सिंह कहते हैं कि हाइब्रिड बीजों की वजह से धान फसल जल्दी तैयार हो जाती है, इसके

संकर बीजों ने बढ़ाई परेशानी

संकर बीजों से जुड़ी एक बड़ी चिंता यह है कि वे खराब अंकुरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, खासकर जब उनके मुताबिक तापमान, प्रकाश, लवणता और पर्यावरणीय स्थितियां नहीं मिलतीं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों के लिए संकर बीज नुकसान का सबब बन गए हैं। 2022 में मप्र में सही समय पर बारिश न होने के कारण किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल खराब हो गई। बालाघाट जिले के किसान राम ने बताया कि हाइब्रिड धान की नर्सरी लगने के 15 से 21 दिन के बीच सिंचाई बेहद जरूरी है। लेकिन बारिश न होने के कारण धान की नर्सरी ही सूख गई। पवार कहते हैं कि उत्तर-पश्चिम भारत में धान के बौनेपन की शिकायत वहां ज्यादा मिली, जहां संकर बीज लगाए गए थे। संकर बीज का केवल सर्टिफाइड बीज ही बाजार में आता है, लेकिन बहुत सी कंपनियां ट्रूथफुल लेबल लगाकर भी बीज बेच रही हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रूथफुल लेबल वाले बीज की जांच ढंग से नहीं होती, जिस कारण कंपनियां बाजार में बड़े-बड़े दावों के साथ अपने बीज बेचती हैं, लेकिन इनमें से 20 से 25 प्रतिशत पैदावार बताए गए समय पर नहीं होती। सतना जिले के प्रगतिशील कृषक बाबूलाल दाहिया कहते हैं कि कंपनियां व डीलर जो वादे मौखिक तौर पर करते हैं, उसके बारे में कहीं भी लिखित में कुछ नहीं होता।

चलते गेहूं लगाने से पहले वे लोग आलू जैसी कम अवधि की फसल लगा देते हैं। यही वजह है कि भारत में हाइब्रिड बीजों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका, चीन के मुकाबले भारत में बीज बाजार की पकड़ काफी कम है, क्योंकि भारत में अभी भी पारंपरिक देशी बीज का इस्तेमाल काफी होता है।

कृषि के मामले में मप्र लगातार कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। अनाज उत्पादन हो या दूध उत्पादन या फिर प्रोसेसिंग का क्षेत्र, हर जगह उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही किसानों की कमाई भी बढ़ रही है। सरकार ने भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से आत्मनिर्भर कृषि नाम से अभियान चलाया हुआ है। क्योंकि मोदी सरकार का फोकस किसानों की समस्याओं को दूर करके उनकी आमदनी दोगुनी करने पर फोकस किया हुआ है। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे अहम रोल बीज का होता है। बीज जितना अच्छा और स्वस्थ होगा, फसल भी उतनी ही शानदार होगी, उस पर कीट और बीमारियों का हमला भी कम होगा। यदि बीज खराब है तो अन्य तमाम साधनों जैसे खाद, सिंचाई आदि पर खर्च किया गया पैसा और मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए खेती-बाड़ी से जुड़े तमाम साधन जैसे, बीज, उर्वरक, कीटनाशी, पानी, बिजली, मशीनरी, किसान की मेहनत और तकनीकी जानकारी आदि अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनमें बीजों का महत्व सबसे ऊपर है। सभी किसान जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज सामान्य बीज के मुकाबले 25 प्रतिशत तक ज्यादा पैदावार देता है। इसलिए शुद्ध, स्वस्थ और प्रमाणित बीज ही अच्छी पैदावार का आधार होता है। प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है वहीं समय और पैसों की बचत होती है। दूसरी तरफ अशुद्ध बीज से ना तो अच्छी पैदावार मिलती है और ना ही बाजार में अच्छी कीमत। अशुद्ध बीज से उत्पादन तो कम होता ही है और भविष्य के लिए भी अच्छा बीज प्राप्त नहीं होता है।

देश में प्राइवेट बीज कंपनियों के बढ़ते कारोबार का अंदाजा मार्च 2021 में लोकसभा में प्रस्तुत कृषि संबंधी स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के हवाले से बताया गया कि भारत में बीज उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो रही है। 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 42.72 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में घटकर 35.54 प्रतिशत रह गई। जबकि इसी अवधि के दौरान बीज बाजार में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 57.28 प्रतिशत से बढ़कर 64.46 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश में लगभग 540 निजी बीज कंपनियां हैं, जिनमें भारतीय मूल के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। खास बात यह है कि लगभग 80 कंपनियां अपने स्तर पर रिसर्च एवं डेवलपमेंट का भी काम करती हैं। शेष कंपनियां पब्लिक सेक्टर द्वारा विकसित बीज का उत्पादन और विपणन करती हैं। ये कंपनियां ब्रीडर (प्रजनक) बीज का उत्पादन नहीं करती। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश निजी बीज कंपनियां फाउंडेशन और सर्टिफाइड-ट्रूथफुल लेबल वाले बीज के उत्पादन में शामिल हैं। भारतीय खाद्य और कृषि परिषद द्वारा सितंबर 2019 में बीज उद्योग परिदृश्य पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारतीय बीज बाजार 4.1 बिलियन (अरब) अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुंच गया था। इसमें 2011 से 2018 के दौरान 15.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई थी। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2019-2024 के दौरान 13.6 प्रतिशत सीएजीआर वृद्धि होगी और निजी बीज का कंपनियों का कारोबार 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। जहां तक सरकारी नेटवर्क की बात है तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 मार्च 2022 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए जिला व तालुका स्तर पर सरकार का एक मजबूत नेटवर्क है। केंद्रीय व राज्यों के 51 कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) के फसल आधारित 65 संस्थानों, 726 कृषि विज्ञान केंद्रों, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 3000 डीलरों, 17 राज्य बीज निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों के माध्यम से किसानों तक बीज पहुंचाया जा रहा है। आईसीएआर के कुछ संस्थानों ने ऑनलाइन बीज पोर्टल विकसित किए हैं। सरकार ने दलहन, तिलहन और बाजरा के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए बीज केंद्र भी शुरू किए हैं। इन सबके बावजूद हाइब्रिड बीज पर निजी क्षेत्र का बढ़ता कब्जा कई सवाल खड़े करता है।

● कुमार विनोद

चुनाव में किसान दरकिनार

मप्र में किसान सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। इसलिए पार्टियों के लिए किसान हमेशा से प्रिय बने रहते हैं। खासकर चुनाव में तो भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस किसानों को साधने पर रहता है। लेकिन इस बार के चुनाव में खेती-किसानी के मुद्दे लगभग गायब रहे। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए पार्टियों ने बाजीगरी का सहारा लिया। यानी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी किसानों के लिए सूखा रखा। यही नहीं चुनावी मैदान में किसानों की बात तक नहीं की गई। राज्य में कृषि संबंधी मुद्दे हमेशा राजनीतिक चर्चा में हावी रहे हैं और सभी दलों ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है। सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। गुणवत्तापूर्ण बीजों की अनुपलब्धता और उर्वरकों की कमी किसानों के लिए प्रमुख चिंता का विषय रही है। लेकिन चुनावी मैदान में किसानों की बात तक नहीं हुई। सरकार उन्हें कर्जदार किसान मानती हैं, जिन्होंने सहकारी बैंकों या समितियों से ऋण लिया है, जबकि आजकल किसान राष्ट्रीयकृत और निजी दोनों बैंको से ऋण लेते हैं। सहकारी बैंकों के कर्ज से किसान नहीं दबता है, क्योंकि उसमें 0 प्रतिशत ब्याज लगता है। छह-छह माह का समय मिलता है, पुनर्भुगतान भी। जबकि बैंकों में 40 दिन से अधिक का समय नहीं मिलता तो ब्याज दर भी 14 से 16 प्रतिशत तक होती है। इस स्थिति को लेकर किसान लंबे समय से सरकारों को ध्यान दिलाते रहे हैं लेकिन किसी ने योजना नहीं बनाई। ये बड़ी परेशानी है। अन्य प्रादेशिक और स्थानीय मुद्दों की तरह इस बार के चुनाव में किसानों के मुद्दे गायब रहे।

आज भी नहीं भरे त्रासदी के जख्म

पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी भी विकलांग

गैस त्रासदी के पीड़ितों का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। साढ़े तीन दशकों में राज्य और केंद्र में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन नहीं बदली पीड़ितों की किस्मत। इन्हें उतनी मदद नहीं मिली, जितने की सख्त जरूरत थी। गैस पीड़ितों को न आर्थिक मदद मिली, न ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं। हाल इतना बुरा है कि इन्हें पीने के लिए साफ और शुद्ध पानी तक नसीब नहीं है। गैस का शिकार बने परिवारों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक विकलांग पैदा हो रही है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के जन्म लेने का सिलसिला जारी है। गैस कांड प्रभावित बस्तियों में अब भी पीड़ितों की भरमार है। कहीं अपाहिज नजर आते हैं तो कहीं हांफते, घिसटते लोग। विधवाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीमार बढ़ रहे हैं। कहने के लिए तो गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल भी खोले गए हैं, मगर यहां उस तरह के इलाज की सुविधाएं नहीं हैं, जिनकी जरूरत इन बीमारों को है। एक ही रात हजारों जिंदगियां लील जाने वाली अमेरिकी कंपनी डाओ केमिकल्स को अगर उचित सजा मिल जाती, तब ही पीड़ितों के दिल को सुकून पहुंचता, मगर दुर्भाग्यवश वह भी नहीं हो सका।

गैस त्रासदी की बरसी पर 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन गैस पीड़ितों का दर्द चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। दो और तीन दिसंबर की भयावह रात के 39 साल हो जाएंगे। लेकिन लोगों के मन से वो जख्म नहीं निकल पाए हैं। दुनिया की सबसे भीषण रासायनिक औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी 1984 ने कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की जान ले ली और हजारों जानवरों और पक्षियों को निगल लिया था। साथ ही जिसने जन्म तक नहीं लिया था उसके लिए भी कहर बन गया। त्रासदी से प्रभावित हजारों-लाखों लोग आज भी लंबी बीमारी और असाध्य रोगों से पीड़ित होकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं।

घनी झाड़ियों से घिरे मौके पर आम जनता के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में एक चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। एकमात्र इमारत तीन मंजिला संरचना है, जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ कर्मचारियों के कार्यालय और निवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अभी भी बेहतर स्थिति में है। दूसरी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। यहां असामाजिक तत्वों की भी आवाजाही होती रहती है। जानकारी के अनुसार, लोहे के तीन टैंकों में से एक (टैंक- ई 610), जिसकी खराबी के कारण जहरीली एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था और रिसाव के कुछ ही घंटों के भीतर लगभग तीन हजार लोगों की मौत हो गई थी, परिसर के भीतर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। हादसे के दौरान भूमिगत टैंक ए 610 में लगभग 42 टन एमआईसी गैस थी। मप्र सरकार के भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास के अनुसार, 1,20,000 से अधिक लोग पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं और सैकड़ों लोग कैंसर, फेफड़ों की समस्याओं, गुर्दे की विफलता और प्रतिरक्षा संबंधी क्षति के कारण असामयिक मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्टों ने यह भी सुझाव दिया कि हजारों बच्चे जन्म दोष के साथ पैदा हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच एक वैश्विक जहरीला हॉटस्पाट मौजूद है, जिसने दो लाख से अधिक लोगों के लिए मिट्टी और भूजल को दूषित कर दिया है। 2016-17 में जारी बीएमएचआरसी की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि 1998-2016 के बीच की अवधि में लगभग 50.4 प्रतिशत गैस त्रासदी का शिकार हुए व्यक्ति हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और 59.6 प्रतिशत हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे।

इस गैस त्रासदी से होने वाली मौतों की संख्या में अंतर भी देखने को मिली है। अलग-अलग समय पर एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों ने हताहतों का अलग-अलग आंकड़ा दिया है। कुछ पहले की रिपोर्टों ने बताया था कि हताहतों की संख्या 5000-6000 के बीच थी, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 हो गई है। कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मरने वालों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है। हालांकि, हताहतों की संख्या के बारे में कोई सटीक डेटा नहीं है। आईसीएमआर की रिपोर्ट ने 1984-1993 के बीच किए गए अपने सर्वेक्षण में 1994 तक आपदा के कारण 9,667 मौतों का उल्लेख किया है। 1994 से आगे का सांख्यिकीय अनुमान 2009 तक 23,000 का आंकड़ा बताता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में केवल 3000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। इसके अलावा, न्याय और मुआवजे की तलाश के लिए कानूनी लड़ाई अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर में केंद्र से अतिरिक्त मुआवजे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र ने बताया कि वह गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका आधारित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त धन के रूप में 7,844 करोड़ रुपए की मांग करने वाली अपनी याचिका को आगे बढ़ाएगा। मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी, 2023 को होगी।

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सांस लेने, सांस फूल जाने संबंधी शिकायत वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। मौसम के बदलाव के कारण लोगों को समस्याएं हो रही हैं। नामदेव खुद भी गैस पीड़ित हैं, उनकी तकलीफें इन दिनों बढ़ी हुई हैं। वह आशंकित हैं कि दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण और बढ़ा है, और अब इन गैस पीड़ितों की तकलीफें और भी बढ़ जाएंगी। उनकी चिंता है कि इस ओर प्रशासन का बिलकुल भी ध्यान नहीं है। भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा कहती हैं कि गैस लगने की वजह से पीड़ितों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, श्वसन तंत्र पर गहन असर पड़ा है। कोरोना का असर भी गैस पीड़ित आबादी पर सामान्य आबादी से कई गुना अधिक था। इसलिए वायु प्रदूषण का ज्यादा असर गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य पर सामान्य आबादी से ज्यादा पड़ेगा। उनकी चिंता है कि आज भी गैस पीड़ितों की एक बड़ी आबादी मजदूरी करती है जिसकी वजह से उनके पास प्रदूषण से बचने के लिए घर पर रहने का विकल्प नहीं है। ऐसे में उनकी जिंदगी और मुश्किल भरी है। भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की नसरीन बी कहती हैं कि हम तो पहले से ही प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, ऐसे में यह बिगड़ा मौसम हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। आने वाले वक्त को लेकर हम चिंता में हैं। उनका यह भी कहना है कि अब तो गैस पीड़ितों को बेहतर इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है।

● अरविंद नारद

दम घोटू प्रदूषण

राजधानी भोपाल की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार पहुंच गया है। इसे लेकर कमिश्नर डॉ. पवन शर्मा भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कलेक्टर और निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग की और प्रदूषण को रोकने के लिए इंतजाम करने की बात कही है। राजधानी में एक्यूआई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली धूल है। अभी भोपाल में मेट्रो, कोलार सिक्सलेन समेत कई निर्माण चल रहे हैं। सड़कें भी जर्जर हैं। इस वजह से भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इधर, पॉल्युशन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ईंधन से फुल टैंक कराने पर गाड़ी का पीयूसी मुफ्त करने का निर्णय लिया है। वहीं, पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की भी तैयारी है।

शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चल रहा है। नवंबर के आखिरी दिनों के आंकड़ों की बात करें तो ईदगाह हिल्स और कोहेफिजा में 308, टीटी नगर में 278 और शाहपुरा में एक्यूआई लेवल 306 पहुंच गया। यह स्थिति दिवाली की रात से भी ज्यादा है। यानी, लोग दिवाली की रात से भी ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। शहर की हवा में प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लोगों की सेहत पर होने लगा है। अस्पतालों की ओपीडी में अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जेपी और हमीदिया हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहां आम दिनों की तुलना में दोगुने मरीज पहुंच रहे हैं। शहर में वायु गुणवत्ता मापने के लिए टीटी नगर, पर्यावास भवन और ईदगाह हिल्स में ऑटोमैटिक सिस्टम लगे हैं। इस समय तीनों ही जगह में अभी एक्यूआई 300 के पार ही चल रहा है।

राजधानी में प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। भोपाल में दो बड़े मेट्रो और कोलार सिक्सलेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सुभाष नगर से एम्स के बीच 6 किलोमीटर में मेट्रो का काम चल रहा है। वहीं, कोलार में करीब 15 किलोमीटर लंबा सिक्सलेन बनाया जा रहा है। निर्माण के चलते तोड़फोड़ भी की जा रही है। इस कारण धूल उड़ती है। हालांकि, सड़कों पर पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है, लेकिन यह उपाय काफी नहीं है। जानकारों के अनुसार विंड वैलोसिटी भी एक्यूआई बढ़ाने की बड़ी वजह है। यदि विंड प्रेशर अधिक होता है तो तुरंत ही एक्यूआई में गिरावट आती है। इसके अलावा दिनभर लगातार ओवर कॉस्ट कंडीशन भी बनी रहती है। इन दिनों लगातार सर्दी बढ़ रही है। इसके कारण वायुमंडल में मौजूद हानिकारक गैसें डिजाल्व नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से भी एक्यूआई बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पराली जला रहे हैं। इस वजह से भी प्रदूषण फैल रहा है। बैरसिया रोड, कोलार रोड के गांवों में यह स्थिति अधिक है। नीलबड़, रातीबड़, विदिशा रोड, होशंगाबाद रोड के गांवों में भी ऐसी ही स्थिति है। राजधानी के आसपास कई ईंट भट्टे भी हैं। जहां ईंटें पकाने के लिए भट्टों में आग लगाई जाती है। ये भट्टे काफी प्रदूषण करते हैं। इस कारण भी एक्यूआई बढ़ रहा है। राजधानी में कई वाहन पॉल्युशन बढ़ा रहे हैं। निगम समेत कई विभागों में आज भी पुराने मॉडल की गाड़ियां चल रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में दौड़ने वाले ऑटो रिक्शा, मैजिक समेत कई पुराने वाहन भी प्रदूषण फैला रहे हैं।

राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए अब जिला प्रशासन के अफसर भी मैदान में उतर गए हैं। 20 नवंबर को कमिश्नर डॉ. पवन शर्मा ने कलेक्टर आशीष सिंह और निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए. के साथ मीटिंग की थी। जिसमें उन्होंने बढ़ते एक्यूआई पर चिंता जताई थी और प्रदूषण पर कंट्रोल करने के इंतजाम करने को कहा था। इसके एक दिन बाद ही कलेक्टर सिंह ने जिम्मेदार अफसरों की बैठक बुलाई। जिसमें हर गाड़ी के लिए पीयूसी अनिवार्य करने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी होगी।

शहर में बढ़ते पॉल्युशन को लेकर गत दिनों कलेक्टर सिंह की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मप्र के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अध्यक्ष अजय सिंह ने प्रदूषण बढ़ने की वजह बताई थी। उन्होंने बताया कि धूल की वजह से ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। राजधानी के बड़ा तालाब में लेक प्रिंसेस क्रूज और जलपरी मोटरबोट चलाने पर दो महीने पहले 12 सितंबर को ही रोक लग चुकी है। पर्यटन विकास निगम बड़ा तालाब में क्रूज और जलपरी के साथ करीब 20 मोटर बोट का संचालन करता था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने डीजल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन को इंसानों समेत जलीय जीवों के लिए खतरा बताते हुए बंद करने का आदेश दिया था।

● **लोकेंद्र शर्मा**

सभी पेट्रोप पंपों पर पीयूसी जांच केंद्र

राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने पुराने वाहनों के पीयूसी (पाल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट की जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में कमी लाई जा सके। इसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को दोपहिया और चारपहिया समेत अन्य वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट जांचने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से पीयूसी केंद्र खोलने के निर्देश भी दिए। बता दें कि ठंड का सीजन शुरू होने के साथ शहर में निरंतर वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ रहा है। इसका कारण सड़कों पर उड़ती धूल, निर्माण कार्य और वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुंआ है। इसको लेकर गत दिनों संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें अधिकारियों से दूषित वायु के स्तर को सुधारने के लिए त्वरित कार्य योजना बनाकर तत्काल अमल करने को कहा था। इसके लिए नगर में पीयूसी जांच यूनिट की संख्या बढ़ाने और भोपाल की सभी सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कलेक्टर ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए।

खाद की किल्लत, किसान परेशान

मप्र में इन दिनों रबी फसल की बोवनी का कार्य चल रहा है। किसानों को यूरिया खाद के अलावा अन्य खाद की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पा रही है। खाद न मिल पाने के कारण खेत तैयार होने के बाद भी किसान बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। शासन-प्रशासन के चुनाव में व्यस्त होने के कारण खाद की किल्लत और बढ़ गई है। हालांकि गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय पहुंचकर खाद की स्थिति का जायजा लिया तो अफसरों ने दावा किया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है।

कृषि और सहकारिता विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि अब तक रबी फसल की 81 लाख 71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी हो चुकी है, जो गत वर्ष से 5.33 प्रतिशत अधिक है। उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। विपणन संघ के 422 विक्रय केंद्र संचालित हैं, विपणन सहकारी समितियों के 154 विक्रय केंद्रों से नगद उर्वरक विक्रय आरंभ किया है। विपणन सहकारी समितियों द्वारा अतिरिक्त 92 विक्रय केंद्र आरंभ किए गए हैं और किसानों को लाइन से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। जबकि स्थिति यह है कि प्रदेश में खाद की कमी के कारण किसान बेहाल हो रहे हैं। विपणन सहकारी समितियों पर दिनभर लाइन में लगे रहने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है।

कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107 लाख 33 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 9-10 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3 लाख मीट्रिक टन एनपीके खाद की जरूरत पड़ती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण न सरकार और न ही प्रशासन का ध्यान इस ओर गया। एक तरफ चुनाव प्रचार होता रहा और दूसरी तरफ अन्नदाता रबी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करता रहा। जब खेत तैयार हो गया तो बुवाई के लिए खाद का संकट खड़ा हो गया। खाद के लिए किसान विपणन सहकारी समितियों पर अलसुबह आकर अपना नंबर लगा देते हैं, जबकि केंद्र 11 बजे के करीब खुलता है। पांच से सात घंटे की मशक्कत के बाद किसानों को यूरिया मिल रहा है। सबसे अधिक बोवनी गेहूं की होनी है। इससे पहले अलग-अलग केंद्रों में यूरिया व अन्य खाद के लिए किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है।

प्रदेश में खाद की सबसे ज्यादा किल्लत ग्वालियर, भिंड और मुरैना क्षेत्र में नजर आ रही है। इस वजह से यहां किसान सड़कों पर उतर आए हैं। यहां मार्कफेड के गोदामों से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी गोदामों तक खाद पहुंचाने में नाकाम रही। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता भ्रष्टाचार। बड़े व्यापारियों और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद की लैबों में ठेके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबू से मंत्री तक सभी खाद की कालाबाजारी में लिप्त हैं।

किसान स्वराज संगठन के अध्यक्ष भगवान मीणा का कहना है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाजार में धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसानों से जबरन खाद के ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। मीणा ने आगे कहा कि खाद सिर्फ महंगी ही नहीं बल्कि उसके साथ किसानों को दूसरी खादें और बीज उपचारित करने वाली दवाइयां खरीदने को बाध्य किया जा रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है।

इंदौर में ही देपालपुर के पाल्या गांव के किसान हर्मेंद्र पटेल ने बताया कि किसानों को डीएपी की जगह एनपीके (12:32:16) खाद दिया जा रहा है। जो डीएपी की तुलना में महंगा होती है। वहीं केदार सिरोही का कहना है कि डीएपी (18:46:0) में 18 फीसदी नाइट्रोजन, 46 फीसदी फॉस्फोरस होता है। जबकि एनपीके में 12 फीसदी नाइट्रोजन, 32 प्रतिशत फास्फोरस और 16 प्रतिशत पोटाश होता है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए फास्फोरस बेहद आवश्यक पोषक तत्व है, ऐसे में एनपीके की तुलना में डीएपी में अधिक फास्फोरस होता है। जिससे अच्छी पैदावार होती है। लेकिन किसानों को जबरन डीएपी की जगह एनपीके डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मप्र के मालवा, निमाड़, चंबल और बुंदेलखंड (कुछ हिस्सों में) आदि इलाकों में रबी सीजन की बुवाई की जा रही है। इंदौर के आसपास के इलाकों में किसानों ने आलू, मटर और दूसरी फसलों की बोवनी शुरू कर दी है। वहीं कुछ हिस्सों में गेहूं, चना, प्याज और लहसुन जल्द लगाई जाएगी। जबकि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में सरसों तथा अन्य फसलों की बुवाई शुरू होने वाली है। प्रदेश के 29 जिलों में रबी सीजन की फसलें उगाई जाती है, इनमें इंदौर, उज्जैन, हरदा, देवास, शाजापुर, होशंगाबाद, राजगढ़, आगर मालवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, धार आदि जिले शामिल हैं।

● जितेंद्र तिवारी

उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में अफसरों ने दावा किया कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। दूसरी ओर, मतदान खत्म होने के दूसरे दिन ही कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा किसानों को महंगी खाद बेचने और खाद की बोरी में भरी खाद का वजन 50 किलो के बजाय 45 किलो करने का आरोप लगा चुके हैं। वर्मा ने कहा कि सरकार खाद के दाम बढ़ा रही है, और वजन कम कर रही है। किसानों को समय पर खाद भी नहीं दे पा रही है। इससे किसान लंबी लाइन लगाने और खाद के लिए बार-बार समितियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। रबी सीजन हो या खरीफ सीजन हर साल खाद की किल्लत होती है। अधिकारी भी पर्याप्त खाद का दावा जरूर करते हैं, लेकिन प्रदेश में खाद की कमी सामने आती है। वर्तमान में खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं।

ओपीएस के लिए बड़ा आंदोलन

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार के रक्षा विभाग (सिविल) में कर्मचारियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है, तो रक्षा विभाग के करीब चार लाख कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराया गया था। इसमें डिफेंस की 400 यूनिटों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। लगभग 99.9 फीसदी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में मत दिया है। देशभर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों की मुहिम चल रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार में 15 लाख कर्मियों की संख्या वाले दो बड़े महकमे, रेलवे और डिफेंस (सिविल) में गत दिनों पुरानी पेंशन की मांग पर राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने के लिए वोटिंग कराई गई। 400 डिफेंस यूनिट, 7349 रेलवे स्टेशन, मंडल व जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और सात रेलवे प्रोडेक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए।

केंद्र सरकार में 15 लाख कर्मियों की संख्या वाले दो बड़े महकमे, रेलवे और डिफेंस (सिविल) में पुरानी पेंशन की मांग पर राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने के लिए वोटिंग कराई गई। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7349 रेलवे स्टेशन, मंडल व जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और सात रेलवे प्रोडेक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए हैं। रेलवे कर्मियों का रिजल्ट आना बाकी है। वजह, रेलवे में करीब 11 लाख कर्मचारी हैं। अभी वोटों का मत प्रतिशत निकाला जा रहा है। कुछ दिनों में परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर कर्मचारियों का दो तिहाई बहुमत, अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में आता है, तो बहुत जल्द देश में रेलें थम जाएंगी, आयुद्ध कारखाने, जो अब निगमों में तब्दील हो चुके हैं, वहां पर काम बंद हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक दूसरे विभागों में भी हड़ताल होगी।

सी श्रीकुमार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। देश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से सकारात्मक बातचीत हुई है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर से आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फॉर्मूला बताने को तैयार हैं, जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार, पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे।

ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है, तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या दस करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय-विभाग, रक्षा कर्मी (सिविल), रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारी, ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। बतौर मिश्रा, वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है, उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार, ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। कहा जा रहा है कि 1975 के बाद देश में यह सबसे बड़ी हड़ताल होगी, जिसमें रेलवे के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे मप्र के लाखों कर्मचारी

केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के विरोध में की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मप्र के लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। यह निर्णय मप्र कर्मचारी मंच की प्रातीय प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। मप्र कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के विरोध तथा न्यू पेंशन योजना को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के समर्थन में की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मप्र के 7.50 लाख नियमित कर्मचारी एवं ढाई लाख अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के कारण राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पिछले 18 वर्षों से हो रहा है। नई पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी टूट गई है। सेवा निवृत होने पर एनपीएस के कारण कर्मचारियों को दर-दर की ठोकर खानी पड़ती है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। देश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं।

आक्रामक हो रहे चीते

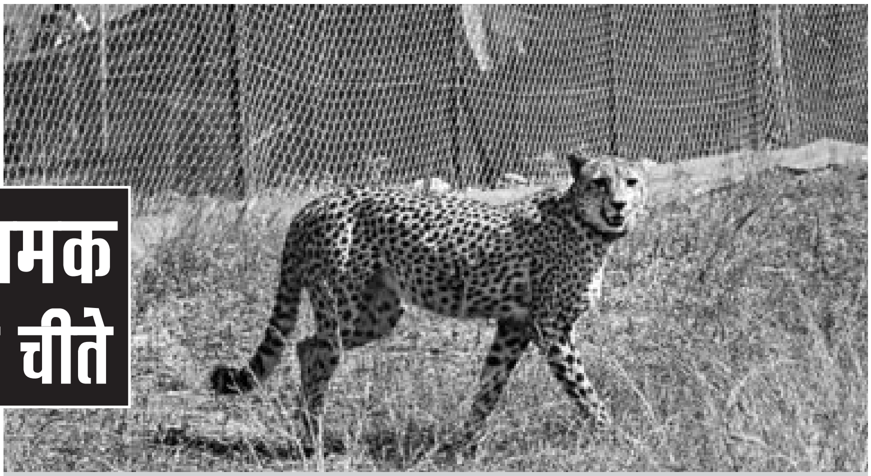

भारत में बसाने के लिए कम उम्र के चीतें उपयुक्त

कूनो नेशनल पार्क में एक के बाद एक हो रही चीतों की मौतों पर प्रोजेक्ट चीता में शामिल अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में बसाने के लिए कम उम्र के ऐसे चीतों का चयन चाहिए जो मानव की उपस्थिति के आदी हों। विशेषज्ञों ने चीतों को फिर से बसाने के लिए कूनो के स्थान पर अन्य स्थलों की पहचान करने की सलाह दी। कूनो में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से दो ग्रुपों में चीते लाए गए हैं। सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा कि कम उम्र के चीते नए माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। अधिक उम्र के चीतों की तुलना में उनके जीवित रहने की दर भी अधिक होती है। कम उम्र के नर चीते अन्य चीतों को लेकर अपेक्षाकृत कम आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं, जिससे चीतों की आपसी लड़ाई में होने वाली मौत का खतरा कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत की दर दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीका में चीतों को बसाने की कोशिश के दौरान शुरुआत में हुई दिक्कतों पर कहा कि तब 10 में से 9 कोशिश असफल हो गई थीं। रिपोर्ट में सुपरमॉम के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। सुपरमॉम दक्षिण अफ्रीका से लाई गईं ऐसी मादा चीतों को कहा जाता है, जो अधिक स्वस्थ और प्रजनन क्षमता के लिहाज से बेहतर होती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लाए गए चीतों में से सात मादा हैं और उनमें से केवल एक के सुपरमॉम होने की उम्मीद है।

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किया गया है वह पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह चीतों के बीच आपसी लड़ाई और उसके बाद जो मौतें हुई हैं, उसने विशेषज्ञों को चौका दिया है। दरअसल, हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चीतों में आक्रामकता आ रही है। चीते जो कि जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव हैं, वो पहले ही अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज इनकी वैश्विक आबादी घटकर 7,000 से भी कम रह गई है। जलवायु में आता बदलाव और बढ़ता तापमान न केवल हम इंसानों को बल्कि दूसरे जीवों को भी प्रभावित कर रहा है। यहां तक कि इसके प्रभाव से बड़े शिकारी जीव भी सुरक्षित नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन के इन शिकारी जीवों के व्यवहार पर पड़ते प्रभावों को लेकर किए नए अध्ययन में इस बात को लेकर आशंका जताई है कि बढ़ता तापमान चीते जैसे शिकारी जीवों के व्यवहार में बदलाव की वजह बन रहा है।

रिसर्च से पता चला है कि गर्मी की वजह से ये शिकारी जीव दिन में शिकार करने की जगह सुबह सूरज उगने या शाम को ढलने के बाद शिकार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गौरतलब है कि चीते आमतौर पर दिन के समय शिकार करना पसंद करते हैं। इस तरह उनके और दूसरे बड़े शिकारियों के बीच शिकार को लेकर होने वाली मुठभेड़ का खतरा कम हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी: बायोलॉजिकल साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन में दावा किया है कि गर्म मौसम के दौरान यह बड़ी बिल्लियां अपने शिकार के समय में बदलाव कर उसे सुबह या शाम के समय शिफ्ट कर सकती हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसकी वजह से चीतों, शेर एवं तेंदुओं जैसे रात में शिकार करने वाले शिकारी जीवों के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। जो पहले ही संकट में पड़े चीतों के लिए खतरा बन सकता है।

चीते जो कि जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव हैं, पहले ही अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि जहां 1975 में इनकी वैश्विक आबादी 15,000 थी, वह अब घटकर 7,000 से भी कम रह गई है। इस बारे में वाशिंगटन विश्वविद्यालय की जीवविज्ञानी और अध्ययन से जुड़ी शोधकर्ता ब्रियाना अब्राह्मस का कहना है कि, तापमान में आता बदलाव इस बात को प्रभावित कर सकता है कि बड़े मांसाहारी कैसे व्यवहार करते हैं, साथ ही यह इन जीवों के बीच के आपसी संबंधों को भी बिगाड़ सकता है। रिसर्च के अनुसार चीते केवल ताजा मांस खाते हैं। वहीं शेर और तेंदुए जैसे शिकारी खुद शिकार करने के साथ-साथ मौकापरस्त भी होते हैं। जो चीते जैसे दूसरे शिकारियों से मौका मिलने पर उनका शिकार तक छीन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीते इन दूसरी बड़ी बिल्लियों से होने वाले संघर्ष से बचते हैं और इनका सामना होने पर वो अपना शिकार तक छोड़कर चले जाते हैं।

बता दें कि अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चीता, शेर, तेंदुए और अफ्रीकी जंगली कुत्तों जैसे 53 बड़े शिकारियों पर जीपीएस ट्रैकर लगाए थे, जिन्हें उन्होंने आठ वर्षों तक ट्रैक किया था, और यह जानने का प्रयास किया था कि इस बीच वो जीव कहां गए और कब सक्रिय थे। फिर, उन्होंने इस दर्ज जानकारी को प्रत्येक दिन रिकॉर्ड किए गए उच्चतम तापमान के आंकड़ों के साथ मिलान करके देखा। रिसर्च से पता चला है कि इन शिकारी जीवों ने एक-दूसरे से होने वाले संभावित टकराव से बचने के लिए दिन के अलग-अलग समय पर शिकार करने की रणनीति विकसित की है। हालांकि रिसर्च से पता चला है कि अत्यधिक गर्म दिनों में जब दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो चीते दिन की जगह रात में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह वो बढ़ती गर्मी से बचने के लिए अपनी शिकार की आदतों में बदलाव कर रहे हैं। इसकी वजह से दूसरी बड़ी प्रतिद्वंद्वी बिल्लियों के साथ उनके शिकार के समय के बीच टकराव की आशंका 16 फीसदी तक बढ़ सकती है।

इस बारे में वाशिंगटन विश्वविद्यालय और बोत्सवाना प्रीडेटर कंजर्वेशन ट्रस्ट के जीवविज्ञानी कासिम रफीक का कहना है कि इसकी वजह से चीतों के लिए भोजन की कमी और संघर्ष के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। शोध के मुताबिक 2011 से 2018 के बीच तापमान में जो अधिकांश बदलाव देखे गए उनकी वजह मौसमी परिवर्तन था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवों के व्यवहार में जो बदलाव देखे गए हैं, वे बढ़ते तापमान के बीच गर्म होती दुनिया में क्या हो सकता है, इसकी एक झलक देते हैं। शोध के अनुसार चीतों को न केवल शेरों और तेंदुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें आवास को होते नुकसान के साथ-साथ इंसानों के साथ बढ़ते संघर्ष और उससे उपजी समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ रहा है।

● जय सिंह सेंधव

अब होगी अलग बुंदेलखंड की लड़ाई

उप्र के तेज तर्रार पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने गत दिनों लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बांदा में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से हमने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है और इसका जल्द ही रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि उप्र के 7 और मप्र के 8 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बुंदेलखंड बनाने की उनकी मांग है। बुंदेलखंड राज्य में कुल 15 जिले होंगे। सुलखान सिंह ने मांग की है कि उप्र के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर और मप्र के दमोह, पन्ना, छतरपुर, दतिया, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और अशोकनगर को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। जिसकी वजह से बुंदेलखंड में बहुत सारी समस्या बनी हुई हैं।

गठन के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए सुलखान सिंह ने इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही कहा कि बुंदेलखंड राज्य में 15 जिले शामिल करने की मांग उठाई जाएगी। आगामी लोकसभा चुनावों में इन जिलों से पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में उतरेंगे। पूर्व डीजीपी सुलखान ने कहा कि वह बांदा के ही रहने वाले हैं। वह यहां की पूरी समस्या जानते हैं। बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है, जहां तमाम समस्याएं मौजूद हैं, इसके बावजूद भी सरकारें इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बजट विकास कार्यों के लिए सरकार से आता है लेकिन प्रभावशाली लोग अपने क्षेत्र में काम लेकर चले जाते हैं, जबकि जहां जरूरत है वहां बजट पहुंच ही नहीं पाता है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि इस वजह से यहां का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। इस वजह आज भी बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है। गौरतलब है कि अभी बुंदेलखंड उप्र और मप्र के बीच बंटा हुआ क्षेत्र है, जिस वजह से इसकी पहचान दो राज्यों में बंटकर रह गई है। इसे एक नई पहचान देने के लिए और बुंदेलखंड को नया राज्य बनाने की मांग उठाते हुए उप्र के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया है। साल 2017 में जब उप्र में योगी सरकार आई, इसके बाद सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया गया था।

सुलखान सिंह बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी को गठित करने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उप्र के बांदा जिले में आयोजित हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए, इस नए राज्य में 15 जिलों को शामिल करने की मांग रखी। नए राज्य के रूप में बुंदेलखंड में उप्र के 7 जिले- बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, जालौन, महोबा तथा मप्र के 8 जिले- निवाड़ी, दतिया, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ को शामिल करने की मांग की है।

बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के गठन को बुंदेलखंड राज्य के गठन हेतु राजनीतिक आंदोलन संचालित करने का उद्देश्य बताया गया है। पार्टी की तरफ से बुंदेलखंड राज्य के सृजन का जो आधार बताया गया है, उसमें बुंदेलखंड, उप्र एवं मप्र के बीच बंटा हुआ है। बुंदेलखंड की अपनी पहचान इन दोनों राज्यों से अलग है। इस क्षेत्र में भौगोलिक, सांस्कृतिक, मानविकीय, कृषि, वाणिज्य आदि की अपने में एकरूपता है। यह क्षेत्र महाभारत काल के चेदि साम्राज्य से लेकर, अंग्रेजी शासन काल तक लगभग एक राजनीतिक क्षेत्र के रूप में रहा है। दुर्भाग्य से कुछ विखंडन अंग्रेजों ने किया और आजादी के बाद तो इसे दो हिस्सों में बांटकर अलग कर दिया गया। बुंदेलखंड की आर्थिक और विकास संबंधी आवश्यकताएं, मप्र एवं उप्र के शेष बड़े क्षेत्र से भिन्न है। राज्य के बजट पर हमारी मांगें राज्यों के शेष हिस्सों से प्रतिस्पर्धी होने के कारण हमें हमारी जरूरत के हिसाब से योजनाएं नहीं मिल पाती हैं। इतने बड़े राज्यों में जिन क्षेत्रों के लोग ज्यादा राजनीतिक प्रभाव वाले हैं, वह अधिक धन ले जाते हैं। परिणामस्वरूप बुंदेलखंड उपेक्षा का शिकार हो गया है।

बुंदेलखंड में पानी की भारी समस्या है, लेकिन सरकारों की उपेक्षा के कारण इस पर कोई संसाधन नहीं लगाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप आज बुंदेलखंड मरुस्थल बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। बुंदेलखंड के लोग सीधे और सरल, परंतु स्वाभिमानी होते हैं। हमारे यहां शिक्षा का प्रसार भी कम है। नतीजा यह है कि बुंदेलखंड में पुलिस या दूसरे मोहकमों में बुंदेलखंड के निवासी नाम मात्र के हैं। अन्य क्षेत्रों के निवासी बहुसंख्यक रूप से काबिज हैं। बुंदेलखंड के निवासियों की राजनीतिक आकांक्षाएं भी कोई दल ध्यान में नहीं रखता। किसी भी सरकार में बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व नाममात्र का रहता है। हमारे प्रतिनिधि बड़ी पार्टियों की राजनीति के कारण बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं बोल पाते हैं। सरकारी अधिकारी और नजन बुंदेलखंड के संसाधनों का मात्र दोहन कर रहे हैं। इनका कोई लाभ बुंदेलखंड को नहीं मिल रहा है।

● सिद्धार्थ पांडे

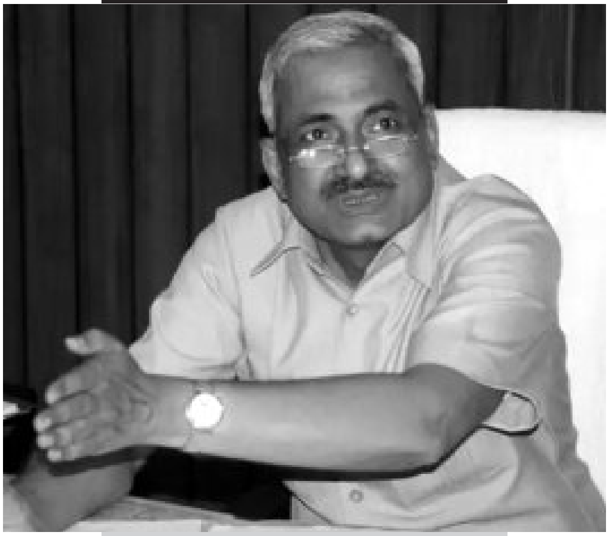

इस वजह से राजनीति में उतरे सुलखान सिंह

उप्र राज्य के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के मुताबिक उनका राजनीति में उतरने का मुख्य मकसद बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास करना है। बांदा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलखान सिंह ने केंद्र और प्रदेश में शासन करने वाली पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बुंदेलखंड की समस्याओं पर भी आवाज उठाई। उप्र के बांदा जिले के रहने वाले सुलखान सिंह का जन्म 8 सितंबर 1957 में हुआ था। 1980 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके सुलखान सिंह को साल 2017 में जब उप्र में योगी सरकार आई, इसके बाद प्रदेश का डीजीपी बनाया गया था। सुलखान उप्र के ही बांदा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1957 को हुआ था। सुलखान की शुरुआती शिक्षा बजरंग इंटर कॉलेज में हुई। उन्होंने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की है। सुलखान ने लॉ भी किया है। सुलखान सिंह उप्र कैडर 1980 बैच के आईपीएस अफसर हैं। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि उप्र के सात और मप्र के आठ जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बुंदेलखंड की मांग है। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड राज्य में 15 जिले होंगे। सुलखान सिंह ने कहा कि वह अकेले ही बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर बुंदेलखंड के अलग राज्य को बनाने को लेकर अलख जगाएंगे।

देश में पांचों राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। मप्र में क्या भाजपा की वापसी होगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का रिकॉर्ड बनेगा या सफाया, राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज। ऐसे कई सवाल सियासी फिजा में तैर रहे हैं। माना जाता है कि एग्जिट पोल जनता का मूड बताते हैं। वोटिंग पैटर्न दिखाते हैं जिससे नेताओं की धड़कने बढ़ जाती हैं। लेकिन, ये एग्जिट पोल हमेशा पूरी तरह सच नहीं होते हैं... इसकी विश्वसनीयता हमेशा कटघरे में रहती है यानी एक्जिट पोल आधी हकीकत, आधा फसाना होते हैं।

● राजेंद्र आगाल

2023 में देश के पांच राज्यों मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों के नतीजें 3 दिसंबर को सामने आएंगे। इन राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े कई एजेंसियों द्वारा डिक्लीयर कर लिए गए हैं। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार मप्र में भाजपा शिवराज सिंह चौहान के संग वापस लौट सकती है। वहीं राजस्थान में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलते हुए कांग्रेस बदलती दिख रही है। राजस्थान में भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन कांग्रेस का हाथ ऊपर है। 2018 में हुए पांच राज्यों के इन नतीजों और एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये सटीक हैं, लेकिन हां ये एग्जिट पोल हवा का रूख किस पार्टी की ओर है उसकी तस्वीरें साफ कर देते हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का आम चुनाव इसमें देखा गया था कि लगभग सभी एजेंसियों के दावे फेल हो गए थे।

दरअसल, एक्जिट पोल सैफोलॉजी का एक अहम हिस्सा है, जो सर्वे और आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक भविष्यवाणी करने की एक विधा है। इसमें किसी चुनाव में शामिल होने वालों में से कुछ से बातचीत के आधार पर वास्तविक नतीजों से पहले नतीजों की भविष्यवाणी, सैफोलाजी के जरिए की जाती है। मतलब ये नमूनों या सैंपल के आधार पर इकट्ठा हुए आंकड़ों के विश्लेषण से नतीजों की भविष्यवाणी है। अब भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। झूठी भी। या फिर सच या झूठ के करीब भी। चूंकि एक्जिट पोल का आधार सैंपल है, इसीलिए एक्जिट पोल की एक्यूरेसी या सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि सैंपल कैसे, कहां से और किस आधार पर लिए गए हैं। अब सवाल है कि जब एक्जिट पोल हो ही रहा है, तो कोई गलत क्यों करेगा? बिना सैंपल के तो एक्जिट पोल होगा नहीं? जब सैंपल लेना ही है तो कोई गलत क्यों लेगा? यही वो सवाल हैं जिसके जवाब में एक्जिट पोल का कच्चा चिट्ठा छुपा है। यूं तो दुनियाभर में सैफोलॉजी में **एरर ऑफ मार्जिन की गुंजाइश** रखी जाती है। लेकिन भारत के संदर्भों में गलती की यह गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। दरअसल, एग्जिट पोल करने वालों की एक टीम होती है जो वोटरों से सवाल करती है जब वे मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे होते हैं। मतदान के दिन इकट्ठा की गई इसी जानकारी के आधार पर चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी की जाती है। इस बार के एग्जिट पोल के रुझान ने सियासी समीकरण और गुणा-भाग की चर्चाओं को तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि मप्र चुनाव में सपा (चुनाव चिन्ह साइकिल) बसपा (चुनाव चिन्ह हाथी) और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (चुनाव चिन्ह आरी) ने रही-सही कसर पूरी कर दी। इन छोटे दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा पहुंचते देखा जा रहा है।

कितना सही होता है अनुमान

मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। इन सर्वे में छत्तीसगढ़ और मप्र में टाइट फाइट बताई गई है, जबकि राजस्थान में भाजपा को सत्ता मिलने का अनुमान है। हालांकि आज तक के सर्वे में यहां भी मुकाबला करीबी होगा। यहां भाजपा को 41 फीसदी ही वोट मिलेंगे, जबकि कांग्रेस को 42 पर्सेंट वोट मिल सकते हैं। वहीं न्यूज-18 के सर्वे का कहना है कि भाजपा को यहां बड़ी जीत मिलेगी और वह 111 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। कांग्रेस को 74 सीटें ही मिलने का अनुमान है। आज तक के मुताबिक राजस्थान में कांटे की टक्कर रहेगी। सर्वे कहता है कि भाजपा को राज्य में 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 86 से 106 सीटें हासिल हो सकती हैं। राजस्थान को लेकर यह एकमात्र पोल है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जाहिर किया गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, जबकि मप्र में भाजपा सत्ता पर काबिज है। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस को कांग्रेस ने कड़ी चुनौती दी है। यहां भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन किसी को बहुमत न मिलने की स्थिति में उसकी भूमिका अहम हो सकती है।

आज जब एक बार फिर राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मतदान के बाद हुए एक्जिट पोल को लेकर माहौल गर्म है तब सवाल यह भी उठता है कि उनके सही या गलत साबित होने का प्रतिशत क्या है? बहुत इतिहास में न भी जाएं तो 2014 का लोकसभा चुनाव इसका बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। उस समय जितने भी एक्जिट पोल थे वो सब एनडीए को बहुमत या बहुमत के आसपास पहुंचता तो बता रहे थे लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अकेले भाजपा 282 सीटें हासिल कर लेगी। उस समय सिर्फ एक नई नवेली एजेंसी चाणक्या ने दावा किया था कि एनडीए को 340 सीटें मिल सकती हैं। जब चुनाव परिणाम आए और एनडीए को 336 सीटें मिलीं तो रातों-रात टुडेज चाणक्या की चर्चा चारों ओर हो गई। इसलिए तब से लेकर अब तक जब भी कहीं चुनाव होते हैं तब टुडेज चाणक्या के अनुमानों पर जरूर नजर रखी जाती है। मसलन इस बार भी चाणक्या और एक्सिस ने ही सबसे अधिक उलटफेर भरा अनुमान लगाया है। अब तक के अनुमान के उलट टुडेज चाणक्या ने दावा किया है कि मप्र में भाजपा तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मप्र में भाजपा और राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का अनुमान पूर्व में किए गए सभी राजनीतिक आंकलनों को ध्वस्त करता है। तेलंगाना में कांग्रेस कोई चमत्कार कर सकती है इसका अनुमान तो पहले से लगाया ही जा रहा है।

टीवीटुडे-एक्सिस एक्जिट पोल ने भी मप्र में भाजपा की वापसी का अनुमान लगाया है जबकि बाकी सर्वे एजेंसियां कमोबेश राजस्थान में भाजपा तो मप्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगा रही हैं। अब तक का एक्जिट पोल का इतिहास देखें तो सटीक

बंगाल चुनाव में फ्लॉप रहे एग्जिट पोल

2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। भाजपा ने इतना जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था कि लग रहा था वहां मोदी लहर पैदा हो गई है। एग्जिट पोल के नतीजों ने भी यही संकेत दिए। ज्यादातर एजेंसियों-चैनलों ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया था लेकिन नतीजों ने बता दिया कि भाजपा का ग्राफ जरूर बढ़ा लेकिन भगवा पार्टी ममता बनर्जी का किला नहीं हिला पाई। हालांकि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव रहे हों या उप्र का 2012 का चुनाव, एग्जिट पोल ने सटीक अनुमान लगाया। इस लिहाज से देखें तो एग्जिट पोल को पक्का तो नहीं कह सकते लेकिन एक संकेत या संदेश जरूर दे जाते हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का आम चुनाव, इसमें लगभग सभी एजेंसियों के दावे फेल हो गए थे। 2004 में दावा किया गया था कि एनडीए की वापसी हो रही है लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई। 2009 में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 2014 में मोदी लहर में एग्जिट पोल काफी हद तक सटीक अनुमान लगा पाए। 2014 के चुनाव में सबसे सटीक दावा चाणक्य एजेंसी का रहा था। उसका अनुमान था कि एनडीए को बंपर 340 सीटें मिल सकती हैं और यूपीए 70 पर सिमट जाएगी। नतीजे लगभग यही रहे। 2019 के आम चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स 300 के आसपास सीटें दे रहे थे लेकिन इतनी सीटें अकेले भाजपा ले आई।

जनमन को कितना जानते हैं एक्जिट पोल?

मतदान के दौरान लोगों का मत जानना और मतगणना से पहले उसे सबको बता देने का नाम एक्जिट पोल है। इस एक्जिट पोल की शुरुआत टीवी न्यूज की देन है। 1967 में अमेरिका और जर्मनी में टीवी चैनलों के लिए इस पद्धति का प्रयोग करके यह जानने की कोशिश की गई कि स्थानीय चुनावों में जनता किसे चुनने जा रही है। क्रमशः यह गति आगे बढ़ी और दुनियाभर में जैसे-जैसे टीवी न्यूज का प्रसार हुआ एक्जिट पोल का भी विस्तार होता गया। भारत में एक्जिट पोल का इतिहास काफी पुराना है। 1957 में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपनियिन द्वारा जनमन जानने का प्रयास किया गया था। इसके बाद दूरदर्शन की शुरुआत और प्रसार के दौर में भी जनमन जानने का काम जारी रहा। लेकिन 24×7 न्यूज चैनलों के आगमन के साथ इसका भारतीय चुनावों में व्यापक विस्तार हो गया। शुरुआत में यह इतना अधिक बेलगाम था कि मतदान के विभिन्न चरणों के दौरान ही सर्वेक्षण करके बताता रहता था कि किस चरण में किस पार्टी को लीड मिल रही है। जब चुनाव आयोग को यह महसूस हुआ कि इससे तो पूरी वोटिंग प्रभावित हो रही है तब मतदान के दौरान एक्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। अब टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियां मिलकर मतदाता का मूड तो जान सकती हैं लेकिन उसे चैनल पर प्रसारित नहीं कर सकतीं। इसके लिए उन्हें आखिरी दिन के मतदान का इंतजार करना होता है ताकि उनके प्रसारण से मतदाता के मूड पर कोई प्रभाव न पड़े। टीवी चैनलों के लिए यह एक फायदे का सौदा होता है क्योंकि इस दौरान दर्शकों की संख्या बढ़ती है और उनके एयरटाइम का रेट भी। जो सर्वेक्षण एजेंसियां होती हैं उनके लिए भी यह एक नियमित काम बन गया है। हर लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले वो व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करने का दावा करके अपने लिए व्यावसायिक अवसर पैदा करती हैं। फिर इन सर्वेक्षणों का विश्लेषण करने वाले सैफोलॉजिस्ट भी होते हैं जो दावा करते हैं कि वही हैं जो जनता का मूड समझ सकने में कामयाब हैं। इसलिए उनकी बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन यह सब तब तक काम का है, जब तक वास्तविक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते। जैसे ही वास्तविक चुनाव परिणाम घोषित होते हैं, किसी को याद नहीं रहता कि किस एक्जिट पोल ने क्या दावा किया था। मतगणना से पहले जिस प्रक्रिया पर घंटों-घंटों टीवी पर बहस होती है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं, चुनाव परिणाम सामने आते ही उस एक्जिट पोल की किसी को याद भी नहीं आती।

आंकलन की बजाय तुक्का ही साबित हुए हैं। कई बार ये नतीजों के आसपास पहुंचते हुए दिखते हैं तो कई बार बुरी तरह ध्वस्त नजर आते हैं। वहीं टुडेज चाणक्या भी कई बार सटीक आंकलन नहीं कर पाया है। 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टुडेज चाणक्या ने भाजपा द्वारा 152 सीटें जीतने का दावा किया था लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने इसके लिए माफी भी मांगी थी। असल में सर्वे कंपनियां कई तरीकों से जनमन को भांपने की कोशिश करती हैं। इसका सबसे सटीक तरीका मतदान करके बाहर आ रहे लोगों का मन जानना है। इसके अलावा पिछले वोटिंग पैटर्न को भी आधार बनाया जाता है। दलों के गठबंधन की गणना की जाती है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर मतदान को जांचा-परखा जाता है। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है सर्वेयर द्वारा वोटरों से की गई बातचीत। उसकी बातचीत के आधार पर सर्वे एजेंसियों का सारा दारोमदार रहता है। इसलिए सर्वे सैंपल की साइज को बहुत अधिक महत्व मिलता है। यानी जितनी ज्यादा संख्या में गों से बातचीत उतना अधिक सटीक आंकलन होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वोटिंग करने वाला वोटर सर्वेयर को सही जानकारी देता है? आज जब पार्टियों के घोषित समर्थक या मतदाता मुखर होकर नजर आने लगे हैं तब भी भारत में सामान्य मतदाता ने किसे वोट किया है इसे गुप्त ही रखता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में वो कभी किसी अनजान व्यक्ति को यह बताने से बचता है कि उसने किसे वोट किया है। बताएगा भी तो सही बता देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा करने के पीछे उसका अपना समाजशास्त्र होता है। वह जिस भी समाज में रहता है वहां राजनीतिक गोलबंदी से बचना चाहता है, इसलिए किसे वोट दिया है इसको आमतौर पर गुप्त ही रखता है। आखिरकार उसके घर जो भी वोट मांगने आता है, वह किसी को ना भी तो नहीं करता है, फिर यह कैसे बता देगा कि किसे वोट दिया और किसे नहीं दिया?

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति में एक बात साफ है, कांग्रेस और उनकी मौजूदा स्थिति। 3-4 एग्जिट पोल में उनकी संख्या 69 से 42 तक दिखाई गई है, यानी वहां पर कांग्रेस के वोटों में बड़ी गिरावट है। दूसरी तरफ भाजपा की सीटें 15 से बढ़कर 46 हो गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की तेज बढ़त को दर्शाता है। यह साफ हो गया है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भाजपा भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव का कहना है कि असली वोट शेयर सीट शेयरिंग में नहीं दिखता। जहां तक आरोपों की बात है तो गंदी राजनीति शुरू हो गई है। महादेव ऐप में भी आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले कहा गया था कि 508 करोड़ रुपए बरामद हुए। वोटर परिपक्व हो गए हैं। लोग इसे राजनीतिक मानते हैं। इसलिए इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका कहना है कि पिछले पांच साल में ढाई-ढाई साल को लेकर हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। हमने सर्वसम्मति से फैसला किया कि आलाकमान जो तय करेगा वही होगा। हम अटकलें नहीं चाहते, क्योंकि इससे रिश्तों में भी तनाव पैदा होता है। इसलिए हमने इसे आलाकमान पर छोड़ने का फैसला किया है।

पांच राज्य, पांच समीकरण...

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, तीन राज्यों में सत्ता की वापसी होने की संभावना है। जबकि तेलंगाना और मिजोरम में सत्ता विरोधी लहर हावी रही है। वहां दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ दल को सत्ता गंवानी पड़ सकती है। अभी मप्र में भाजपा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में मप्र में एक बार फिर भाजपा को जबरदस्त जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस को दोनों राज्यों में भाजपा से थोड़ी बढ़त हासिल है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) मुश्किल में दिख रही है। वहां चार एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, मिजोरम में विपक्षी छह दलों का गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट अप्रत्याशित रूप में उभर रहा है। वहां मुख्यमंत्री जोरमथांगा के मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) पर हार के खतरे की घंटी बज रही है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो पांचों राज्यों में नए समीकरण कुछ भी हो सकते हैं।

मप्र की 230 सीटों पर मतदान हुआ है। बहुमत के लिए 116 सीटें होना जरूरी है। इंडिया टुडे के मुताबिक, राज्य में भाजपा 140-162 के बीच सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की सीटें 68-90 के बीच आ सकती हैं। तीन अन्य उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद निर्दलीय या सपा-बसपा-जीजीपी से जीतने वाले उम्मीदवारों का रुख साफ हो सकेगा। हालांकि, भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं से इन छोटी पार्टियों के नेता संपर्क में हैं। 2018 में पहले जिन निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, वे नेता 2020 के उलटफेर के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। जानकार कहते हैं कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आती हैं या बहुमत के करीब होता है, उसे निर्दलीय और छोटे दलों का सहयोग-समर्थन भी हासिल होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114, भाजपा ने 109, बसपा ने दो, सपा ने एक और चार निर्दलीय ने जीत हासिल की थी।

राजस्थान में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त

राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहां बहुमत के लिए 100 सीटें होना जरूरी है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, कांग्रेस बहुमत हासिल कर सकती है। यानी राजस्थान में कांग्रेस 30 साल पुराना ट्रेंड तोड़कर वापसी कर सकती है। राज्य में कांग्रेस को 86-106 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा भी पीछे से कड़ी टक्कर दे रही है। भाजपा को 80-100 सीटें मिल सकती हैं। अन्य छोटे दलों और बागी-निर्दलीय भी 9-18 सीटें जीतने की स्थिति में है। एग्जिट पोल के रुझान के बाद राजस्थान में छोटे दलों और बागी-निर्दलीय की पूछ-परख बढ़ने वाली है। चूंकि, कांग्रेस और भाजपा दोनों बहुमत के करीब हैं। अगर कुछ सीटों का नुकसान होता है तो यही छोटे दल और बागी किंगमेकर बनकर उभर सकते हैं। जानकार यह भी कहते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियों की नजरें भी इन छोटे दलों के नेताओं पर हैं। 2018 के चुनाव के बाद अशोक गहलोत ने बसपा के सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करके चौंका दिया था। इस बार भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली रणनीति सामने आ सकती है। जानकार कहते हैं कि एग्जिट पोल में छोटे दलों-बागी निर्दलीय को करीब 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच 180 सीटों के बीच लड़ाई है। इन सीटों में ही सत्ता का बंटवारा होना है। नतीजों के बाद ही सरकार बनने-बिगाड़ने के नए समीकरण बनेंगे। राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने साधने की राजनीति शुरू कर दी। जानकार कहते हैं कि वसुंधरा राजे और गहलोत दोनों के करीबी नेता भी इस बार बागी के तौर पर चुनावी मैदान में है। कुछ सीटों पर जीतने की स्थिति में भी हैं। अगर ये चुनाव जीतकर आते हैं तो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थीं। भाजपा 73 सीटों पर सिमट गई थी। बसपा ने छह, आरएलपी ने तीन, निर्दलीय 13 और अन्य दलों से 5 उम्मीदवार चुनाव जीते थे।

2018 में क्या था एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल की सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती है। 2018 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल की बात करें तो उनके अनुमान राजस्थान और मप्र में आए असल परिणाम के आसपास थे। लेकिन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए उनकी भविष्यवाणियां काफी अंतर से गलत साबित हुई थीं। राजस्थान के लिए सभी प्रमुख एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 200 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। पांच एग्जिट पोल में कांग्रेस को औसत 117 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। यह असल आंकड़ों के सबसे करीब था। रिपब्लिक-सीवोटर और इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस के लिए काफी बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। हालांकि, कोई भी प्रमुख सर्वेक्षण निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी जैसे छोटे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था, जिसने क्रमशः 13 और छह सीटें जीतीं थीं। मप्र में 7 प्रमुख एग्जिट पोल के औसत ने कांग्रेस पर भाजपा की मामूली जीत की भविष्यवाणी की थी। 230 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा था। जबकि केवल एबीपी न्यूज-सीएसडीएस ने कांग्रेस के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया, टाइम्स नाउ-सीएनएक्स और इंडिया-सीएनएक्स ने भाजपा के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। कांग्रेस ने 2018 में 114 सीटें जीतीं, बहुमत से केवल एक सीट कम और भाजपा से केवल पांच सीटें अधिक। सात में चार एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई गई थी।

काका पर भरोसा बरकरार

छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव है। बहुमत के लिए 46 सीटें होना जरूरी है। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी टाइट फाइट है। यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। यहां तक कि त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस थोड़ी आगे है और 40-50 सीटें जीतने का अनुमान है। जबकि भाजपा 36-46 सीटें जीत सकती है। अन्य 1-5 सीटें जीत सकते हैं। सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस को 42 फीसदी और भाजपा को 41 फीसदी वोट शेयर मिल सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 23 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। जबकि भाजपा को 26 सीटों का फायदा हो सकता है। 2018 में कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थीं। जबकि भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई थी। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए अन्य छोटे दलों के उम्मीदवार किंगमेकर बनकर उभर सकते हैं। अगर कांग्रेस या भाजपा बहुमत से थोड़ा पीछे रहती हैं तो छोटे दलों-निर्दलीयों की मदद लेना चाहेंगी। ऐसे में यह दल-उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस के बागी भी चुनावी मैदान में हैं। कुछ सीटों पर ये उम्मीदवार अच्छी स्थिति में हैं। अमित जोगी की पार्टी भी चुनाव में दमखम के साथ मैदान में देखी गई है।

विपक्षी के पक्ष में जबरदस्त रुझान

मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव हैं। बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत होगी। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, मिजोरम में विपक्षी गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट 28-35 सीटें जीत रहा है। यानी सरकार बनाने की स्थिति में देखा जा रहा है। सर्वे में अनुमान लगाया गया कि मुख्यमंत्री जोरमथांगा का मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) का लगभग सूपड़ा साफ है। उसे केवल 3 से 7 सीटें ही मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 2-4, भाजपा को 0-2 सीटें मिल सकती हैं। दरअसल, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा और उनकी पार्टी एमएनएफ के खिलाफ बहुत तगड़ी सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। वहीं, 74 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी लालदुहोमा के नेतृत्व में जेडपीएम (जोरम पीपुल्स मूवमेंट) के पक्ष में जबरदस्त लहर है। लालदुहोमा ने कांग्रेस के टिकट पर मिजोरम से 1984 का लोकसभा चुनाव जीता था। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो और उनकी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट एक गठबंधन पार्टी में शामिल हो गए थे। जेडपीएम ने प्रमुख विपक्ष दल बनने के लिए 8 विधानसभा सीटें जीतीं थीं। जेडपीएम पार्टी का जन्म दिल्ली में आप की ही तरह एक आंदोलन से हुआ था। इस पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार युवा हैं और 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे शहरी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। लालदुहोमा भारतीय राजनीति में पहले ऐसे शख्स हैं, जिन पर दल-बदल कानून के तहत एक्शन हुआ और लोकसभा में संसद सदस्यता गंवानी पड़ी।

एग्जिट पोल का इतिहास

दुनिया का सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस वक्त जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन ने न्यूयॉर्क में एक चुनावी सर्वेक्षण किया था। इसमें पोलिंग सेंटर से वोट डालकर बाहर आने वाले लोगों से पूछा गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के किस उम्मीदवार को वोट दिया है। सर्वे के दौरान मिले आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इलेक्शन जीत जाएंगे। यह पहला एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ और रूजवेल्ट ने चुनाव जीता। देखते ही देखते एग्जिट पोल दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद 1937 में ब्रिटेन में भी पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल कराया गया। भारत में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल की शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है। तब चार्टर्ड अकाउंटेंट से पत्रकार बने प्रणय रॉय ने वोटरों का मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल किया था। शुरुआती सालों में एग्जिट पोल मैग्जीन में छपा करते थे। 1996 का लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के लिहाज से काफी अहम था। उस समय दूरदर्शन पर एग्जिट पोल दिखाए गए थे। ये पहली बार था जब टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए। ये सर्वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था। उस चुनाव में सीएसडीएस ने अपने एग्जिट पोल में खंडित जनादेश का अनुमान लगाया था। हुआ भी ऐसा ही था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा।

केसीआर गंवा सकते हैं सत्ता

तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव हैं। बहुमत के लिए 60 सीटें जरूरी हैं। यहां 2014 राज्य गठन के बाद से के चंद्रशेखर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति) की सरकार है। यानी 9 साल से केसीआर का सत्ता में दबदबा रहा है। लेकिन, इस बार सर्वे में केसीआर को तगड़ा झटका लगने का अनुमान लगाया गया है। चार एग्जिट पोल बताते हैं कि इस बार कांग्रेस को बीआरएस पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस औसत अनुमानित संख्या के तौर पर 61 सीटें तक जीत सकती है। जबकि केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस को 46 सीटें जीतने का अनुमान है। चार एग्जिट पोल के औसत के अनुसार, राज्य में बड़े स्तर पर चुनावी अभियान शुरू करने वाली भाजपा को सिर्फ सात सीटें जीतने की संभावना है। यहां जन की बात, पोलस्ट्रैट, मैट्रिज और टुडेज चाणक्य का सर्वे लिया गया है। जानकार कहते हैं कि टीआरएस सत्ता में रहने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। गठबंधन के रास्ते भी तलाशेगी। अगर बहुमत के लिए करीबी आंकड़ा रहा तो भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो बीआरएस को सत्ता से काफी दूर रखते हैं। लेकिन भाजपा और फिर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीआरएस के सत्ता में वापसी की संभावना बढ़ सकती है। ये दोनों बीआरएस को समर्थन देते हैं तो वो बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। फिलहाल, नतीजे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नर्मदा किनारे अवैध निर्माण

राजस्व रिकार्ड की जांच हो

म प्र की जीवन-रेखा नर्मदा के किनारे अवैध निर्माणों के दिन लदेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नर्मदा के उच्च बाढ़ स्तर नहीं बल्कि सामान्य जल स्तर से 300 मीटर के भीतर के निर्माणों को अवैध की श्रेणी में डाला गया है, इसलिए नए सिरे से कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने नर्मदा किनारे निर्माण की गाइडलाइन पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए नर्मदा नदी प्रदेश के जिन जिलों से निकलती है, उसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए गाइडलाइन पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की है।

गौरतलब है कि दयोदय सेवा केंद्र द्वारा नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे में अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए नर्मदा मिशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं, पूर्व मंत्री व भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा डिंडौरी में बिना अनुमति नर्मदा नदी के लगभग 50 मीटर के दायरे में बहु मंजिला मकान बनाए जाने को भी चुनौती दी गई थी। इसके अलावा एक अवमानना याचिका सहित तीन अन्य संबंधित मामले को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। मामले की पूर्व में सुनवाई के दौरान जबलपुर नगर निगम की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2008 के बाद नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे में तिलवाराघाट, ग्वारीघाट, जिलहेरीघाट, रमनगरा, गोपालपुर, दलपतपुर, भेड़ाघाट में कुल 75 अतिक्रमण पाए गए हैं। इसमें से 41 निर्जी भूमि, 31 शासकीय भूमि तथा तीन आबादी भूमि में पाए गए हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि नदी के अधिकतम जलभराव क्षेत्र से 300 मीटर दूरी निर्धारित है। सरकार की तरफ से टाउन एंड कंट्री के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि रिवर बेल्ट से 300 मीटर निर्धारित है। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश जवाब की प्रति पक्षकारों को प्रदान करने के निर्देश जारी करते हुए आदेश जारी किए।

विगत दिवस हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से अवगत कराया गया कि नर्मदा नदी के हाई फ्लड लेवल से नहीं, बल्कि सामान्य जलस्तर से 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। टीएनसीपी के नियमों के तहत यही प्रविधान है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने उक्त जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर के लिए अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित कर दी। नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के प्रतिबंधित जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। प्रतिबंधित जोन के 300 मीटर के दायरे में राइटेरियन जोन और हाई फ्लड लेवल जोन भी शामिल है। नदी के दोनों किनारों को राइटेरियन जोन की श्रेणी में रखा गया है। राइटेरियन जोन में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़-पौधे पानी को संरक्षित करने के साथ नदी को कटाव से बचाते हैं। बारिश के दौरान नदी के उच्चतम जलस्तर को हाई फ्लड लेवल जोन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार नदी के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण और खुदाई नहीं की जा सकती है। याचिका में आरोप लगाया है कि तिलवारा में नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में बड़े स्तर पर निर्माण किए जा रहे हैं। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने तर्क दिया कि 300 मीटर के दायरे में यदि निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो नर्मदा नदी का मूल स्वरूप परिवर्तित होने का खतरा बढ़ जाएगा। नदी के प्रतिबंधित जोन में किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हाईकोर्ट ने बाद में इस मामले को पूरे प्रदेश में नर्मदा तटों के लिए व्यापक कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यभर में नर्मदा के उच्चतम बाढ़ के स्तर से 300 मीटर दायरे के सभी निर्माण हटाकर रिपोर्ट पेश की जाए। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के पालन में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 30 मई, 2019 को हाईकोर्ट ने नर्मदा के 300 मीटर प्रतिबंधित दायरे में निर्माण पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार को हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के अंदर हुए निर्माणों का ब्यौरा पेश करने को कहा था। इस पर राज्य शासन की ओर से यह जवाब दिया गया।

उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर आश्चर्यजनक तरीके से नर्मदा नदी के बेसिन में बने अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों को बचाया जा रहा है। राजस्व निरीक्षकों व पटवारियों की मिलीभगत से नर्मदा किनारे की जमीनों को निजी व्यक्तियों के नामों पर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इस निर्देश के पालन में सरकार की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि पहले भी बताया जा चुका है कि नर्मदा के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर का दायरा प्रतिबंधित नहीं है। बल्कि टीएंडसीपी के नियमों के तहत नदी के सामान्य जलस्तर से 300 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू होता है। इस पर कोर्ट ने जवाब की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिए। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि नदी के अधिकतम जलभराव क्षेत्र से 300 मीटर दूरी निर्धारित है। सरकार की तरफ से टाउन एंड कंट्री के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि रिवर बेल्ट से 300 मीटर निर्धारित है। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश जवाब की प्रति पक्षकारों को प्रदान करने के निर्देश जारी करते हुए उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश चंद्र तथा अधिवक्ता सौरभ कुमार तिवारी ने पैरवी की।

● राकेश ग्रोवर

अब मिशन 2024 की बारी

> मप्र, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में मतदान के बाद अब सबकी नजर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर है। हालांकि मतदान के बाद से ही इंडिया गठबंधन मिशन 2024 की तैयारी में जुट गया है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान गठबंधन की गांठ हर किसी को देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अभी तक जिस तरह एक दिखा है, उस तरह आगे भी रह पाएगा। भाजपा का दावा है कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन खंडित हो जाएगा।

5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद दिसंबर में विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी। इसमें न्यूनतम साझा घोषणापत्र पर सभी दलों से प्रस्ताव लिए जाएंगे। जिन मुद्दों पर सहमति बनेगी, उन्हें शामिल करते हुए इंडिया गठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद दिसंबर में ही इंडिया के सभी घटक दलों के बड़े नेता किसी एक राज्य में बैठेंगे। अभी यह तय नहीं है कि यह राज्य कौन सा होगा। नतीजे आने के बाद ही स्थान तय होगा। सूत्रों के मुताबिक, इस बार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर मंथन होगा। इन मुद्दों में जातीय जनगणना सबसे ऊपर होगी। इसके अलावा रोजगार और आय गारंटी से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल किए जाएंगे। अधिकांश मुद्दे राष्ट्रीय होंगे, लेकिन राज्य स्तर के प्रमुख मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही हो। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर भी इंडिया गठबंधन अपनी स्पष्ट राय रखेगा। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, इस बारे में समन्वय समिति में शामिल नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई है। घटक दलों की बैठक से पहले समन्वय समिति न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर होमवर्क करेगी। उसके बाद ही इन प्रस्तावों को मुख्य बैठक में रखा जाएगा।

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इन तीन राज्यों में से दो राज्य इस समय कांग्रेस के पास हैं। महत्वपूर्ण तो भाजपा के लिए भी है। लेकिन भाजपा के लिए कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के पास अभी एक राज्य है मप्र। वहां भी असल में वह पिछली बार हार गई थी। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मप्र को भाजपा की झोली में डाल दिया था। कांग्रेस तीनों में से दो राज्य हार गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। उसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। भाजपा तीन में से दो राज्य जीत जाए, तो उसके लिए उपलब्धि होगी। एक भी जीते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहां तक मोदी का सवाल है तो हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि तीनों राज्य हार कर भी लोकसभा चुनाव में मोदी ने इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। उससे पहले भी देख चुके हैं कि लोकसभा चुनावों पर राज्य विधानसभा के चुनाव नतीजों का असर नहीं होता।

कांग्रेस को अपना कद घटने का अहसास

जाहिर है कि कांग्रेस को इससे अपना कद घटने का एहसास होगा और वो फिर वहां अपनी मर्जी चलाने के लिए मैदान में अपनी मनचाही सीटों पर अलग से टिकट देने की कोशिश करेगी। क्योंकि उसे हर जगह अपने बड़े होने का रुतबा भी कायम रखना है। कांग्रेस की दावेदारी मप्र से भी ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में कांग्रेस को वापसी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहां मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूती और वसुंधरा राजे की भाजपा शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी, पार्टी में स्थानीय उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए चेहरों और सांसदों को मैदान में उतारना भाजपा को भारी पड़ सकता है। मप्र में भी भाजपा की यही स्थिति बनी हुई है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहां भी कांग्रेस को जीत का पक्का भरोसा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मजबूत नेता हैं और सरकार को वहां भी वापसी का विश्वास है, जिसकी पुष्टि सर्वे ने भी कर दी है। जाहिर है कि कांग्रेस वहां भी अपने किसी सहयोगी दल को ज्यादा सीटें देने से बचेगी। इसी प्रकार से मिजोरम में भी कांग्रेस को जीत का भरोसा है। क्योंकि उसके पड़ोसी राज्य मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल है, उससे पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हुई है और लोगों में उसके प्रति जिस प्रकार से गुस्सा देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि मिजोरम में कांग्रेस मजबूत हो सकती है।

लेकिन कांग्रेस अगर दो राज्य हार गई तो उसकी लोकसभा चुनावों की सारी रणनीति धरी रह जाएगी। खुद को दूसरों से बड़ा बताने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में इंडी एलायंस के किसी दल से गठबंधन नहीं किया। अलबत्ता तीन महीनों के लिए इंडी एलायंस को बर्फ में डाल दिया।

नीतीश, अखिलेश और केजरीवाल मप्र में सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तीनों को ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस की रणनीति यह है कि वह पांच में से तीन राज्य जीत जाए। तेलंगाना और मिजोरम में तो वह सोच भी नहीं रही। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को कड़ी टक्कर दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस तीनों हिंदी भाषी राज्यों पर ही दांव लगाकर बैठी है। कांग्रेस की रणनीति यह है कि अगर उसके मन मुताबिक नतीजे आए, तो वह क्षेत्रीय दलों को कहेगी कि वह अकेले भाजपा को हराने में सक्षम है। इसलिए सीटों के बंटवारे में उसका हक ज्यादा बनता है। लेकिन अगर कांग्रेस तीनों राज्यों या दो राज्यों में हार गई तो उत्तर भारत के सारे दल लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ठेंगा दिखाएंगे। न केजरीवाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भाव देंगे, न अखिलेश यादव उप्र में भाव देंगे। न लालू और नीतीश बिहार में उतना भाव देंगे, जितनी उम्मीद कांग्रेस लगाकर बैठी है। इसलिए तीनों राज्य जीतना कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीन महीने पहले तक कांग्रेस तीनों राज्यों में जीत रही थी। यह ओपिनियन पोल बता रहे थे। कांग्रेस ने इन्हीं ओपिनियन पोल को देखकर अखिलेश, केजरीवाल और नीतीश को भाव नहीं दिया। जबकि अब ओपिनियन पोल बदल चुके हैं। नए ओपिनियन पोल में भाजपा मप्र और राजस्थान जीत रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में महादेव एप ने मुकाबला कड़ा कर दिया।

मप्र और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने मतदान से एक दिन पहले ही राजस्थान में अपने चुनावी भाषण में इन दोनों राज्यों में जीत का दावा कर दिया। उन्होंने तो मुख्यमंत्री बघेल के हारने की भविष्यवाणी भी कर दी है। बघेल अपने चचेरे भाई विजय बघेल और अमित जोगी के साथ तिकोने मुकाबले में गए थे। अमित जोगी कांग्रेस के वोट काटकर विजय बघेल का रास्ता खोल रहे थे। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार में सरगुजा की बहुत भूमिका थी। यह टीएस सिंहदेव का इलाका है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी। इसलिए 2018 में सरगुजा की सभी 17 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। अब सरगुजा कांग्रेस के हाथ से खिसकता दिख रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने वायदा करके भी उन्हें ढाई साल बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मोदी ने चुनाव से दो दिन पहले यह कहकर आग में घी डाल दिया कि बघेल ने दस जनपथ में पैसे पहुंचा दिए थे। इसलिए टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि 17 में से सात-आठ सीटें जीत लेंगे। कुल मिलाकर इन सब बातों से जिस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का सुरक्षित किला बताया जा रहा था। उस छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को कड़ा मुकाबला दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की एक-एक राजनीतिक चाल महत्वपूर्ण होती है। वह आगे की सोचकर ही कदम रखते हैं। उन्हें पता था कि इन दोनों राज्यों में 14 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 15 को भी प्रचार का मौका ढूंढ लिया। चुनाव से 24 घंटे पहले उन्होंने झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर जाने का प्रोग्राम बना रखा था। वहां जाकर उन्होंने 24 हजार करोड़ की परियोजनाओं का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया था। भाजपा मानती है कि इससे मप्र और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोटरों पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा।

अब वोटिंग से अंदाज लगाना मुश्किल हो गया है। पहले माना जाता था कि अगर पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन मप्र में 2003 से लेकर इस बार तक वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। इसके बावजूद 2008 और 2013 में भाजपा जीती। 2018 में जब किसी को बहुमत नहीं मिला था, तब उसकी सीटें जरूर घटीं, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से आधा प्रतिशत ज्यादा था। इस बार भी 2018 के मुकाबले करीब आधा प्रतिशत वोट बढ़ा है। 2018 में 75.6 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 76.2 प्रतिशत वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 2018 में 76.45 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 75.72 प्रतिशत हुई है, यानि 0.73 प्रतिशत कम वोटिंग हुई।

● विपिन कंधारी

इंडिया गठबंधन में अभी से दरार

सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी महागठबंधन इंडिया में दरार की चर्चा के बाद अखिलेश यादव ने खुलकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस की विधानसभा में सीटों को न बांटने की स्थितियां लोकसभा में भी बनी रहेंगी। अखिलेश ने कहा है कि अगर अभी विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर का गठबंधन नहीं होगा। इंडिया से पहले पीडीए बन गया था। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ऐसा लगता है कि यह अपने-अपने वर्चस्व को बचाए रखने की लड़ाई है; जो हर राज्य में सामने आनी ही है। और यह लड़ाई यूपीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक ही नहीं, बल्कि एनडीए में भी शुरू से ही रही है। इसलिए मप्र में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे के लेकर बात नहीं बनना कोई नई बात नहीं है और न ही इस पर भाजपा के नेताओं को बहुत खुश होने की जरूरत है। हालांकि जिस प्रकार से मप्र में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर नोकझोंक हुई, दोनों तरफ से बयानबाजी सामने आई और जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से मैदान में उतारते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उससे आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन की फूट के संकेत मिलते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि गठबंधन में मप्र के अंदर कांग्रेस और सपा में पड़ी दरार यह साबित करती है कि गठबंधन में शामिल सभी 26 पार्टियों के बीच इस तरह की चुनौतियां आगे भी आड़े आएंगी-ही-आएंगी। इसकी वजह यह है कि जहां जिस पार्टी का वर्चस्व होगा, वो वहां की सीटों पर समझौता करने को राजी नहीं होगी और जहां जिस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होगा, वो वहां पर सीटों की मांग करेगी। इस प्रकार से सभी पार्टियों का हर चुनाव में अपनी अलग राह होगी और इससे नुकसान भी इंडिया गठबंधन को ही होगा, जो कि भाजपा के नेता भी चाहते हैं।

मनमानी पर कैसे लगेगी लगाम?

राजनीति में लोकतंत्र और शुचिता के लिए तीन अहम मुद्दे देश के सामने हैं। ये तीनों ही मुद्दे पहली बार सामने नहीं आए, इससे पहले भी इन तीनों मुद्दों पर कई बार बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये तीनों मुद्दे कई बार आ चुके हैं। पहला मुद्दा है राज्यपालों की मनमानी का, दूसरा मुद्दा है स्पीकरों की मनमानी का और तीसरा मुद्दा है चुने हुए मुख्यमंत्रियों की मनमानी का। तीनों मुद्दे इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब वक्त आ गया है कि इन तीनों मुद्दों पर अंतिम फैसला हो जाए।

सबसे पहले हम राज्यपालों की मनमानी और केंद्र सरकार की ओर से राज्यपालों के राजनीतिक दुरुपयोग पर बात करते हैं। 1994 के एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति राज लगाने की मनमानी पर तो नकेल लग गई है। लेकिन राज्यपालों की ओर से चुनी हुई सरकारों के कामकाज में संवैधानिक बाधाएं पैदा करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए डांट पिलाई है कि वह चुनी हुई विधानसभा से पारित बिलों पर लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल और तमिलनाडु के संबंध में केंद्र सरकार और राज्यपाल कार्यालयों को नोटिस जारी किया है। संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास तीन ही विकल्प हैं, या तो वह बिल पर दस्तखत करें, या राष्ट्रपति को भेज दें, या अनुमति रोक लें। सवाल यह है कि राज्यपाल अपने पास कितने दिनों तक बिलों को पेंडिंग रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा है कि क्या राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए बिलों को पेंडिंग रख सकता है। तमिलनाडु के 12 बिल राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित पड़े हैं। जैसे ही 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को डांट पिलाई, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने दो बिल तो राष्ट्रपति को भेज दिए, बाकी दस बिल नामंजूर करके सरकार को भेज दिए। सरकार ने तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और 18 नवंबर को वे सभी 10 बिल जस के तस फिर से पास करवाकर भिजवा दिए। जब विधानसभा दूसरी बार पारित करके बिल भेजती है, तो वह बिल मनी बिल के बराबर हो जाता है। राज्यपाल के पास उसे पारित करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। हां अगर उस बिल से उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती हो रही हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को समय दिया है कि वह उन 10 बिलों पर 10 दिन में फैसला लें।

केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल के पास 8 बिल लंबित हैं, जिनमें से कुछ तो दो साल से लंबित हैं। मजेदार बात यह है कि केरल के तीन अध्यादेशों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी, जबकि वे तीनों बाद में विधानसभा से बिलों के रूप में पास भी हो गए। इनमें से कुछ बिल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति से संबंधित हैं। केरल सरकार ने राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने का बिल पास किया है। परंपरा के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। वह इसलिए ताकि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। लेकिन गैर भाजपा सरकारों के राज्यपालों की ओर से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर मनमानियों के चलते सरकारों और राज्यपालों में टकराव हुआ। टकराव के चलते पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल विधानसभाओं ने राज्यपालों को कुलाधिपति पद से हटाने के बिल पास किए हैं।

राज्यपाल ही कुलाधिपति होंगे, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्य

सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं

राज्यपालों की नियुक्तियों और उनकी शक्तियों को लेकर सरकारिया कमीशन ने एक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी। विपक्ष में रहते भाजपा उन सिफारिशों को लागू करने की मांग करती थी। भाजपा ने यहां तक कहा था कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद वह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगी। सरकारिया कमीशन का सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले एक पैनल बनाया जाए, जिसमें उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाए। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 153 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2016 में कहा कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम करते हैं। जहां-जहां राज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम नहीं करते, वहीं पर टकराव की स्थिति पैदा होती है। बीच-बीच में अनेक बार राज्यपाल के पद को खत्म करने की मांग भी उठी है, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियां लंबे समय से राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग करती रही हैं।

सरकारों को पूरा अधिकार है कि वह इस संबंध में कानून बनाकर संशोधन कर सके। लेकिन किसी भी राज्यपाल ने इन बिलों को मंजूरी नहीं दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को निर्णायक फैसला लेना होगा कि अगर राज्यपाल कुलाधिपति रहता है, तो कुलपतियों की नियुक्ति में उसकी कितनी भूमिका होगी या नहीं होगी। वैसे इस संबंध में यूजीसी ने 2018 में एक नियमावली बना दी थी, उसी नियमावली के मुताबिक ही कुलपतियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

दूसरा प्रमुख मुद्दा स्पीकरों की मनमानी का है। दलबदल कानून के अंतर्गत फैसला करने का अंतिम अधिकार सदन के स्पीकरों का था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को स्पीकर के फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है। एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ हो, तो स्पीकर दलबदल पर कार्रवाई की लंबित याचिका पर फैसला नहीं कर सकता। आमतौर पर दलबदल सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होता है, और स्पीकर भी सत्ताधारी पक्ष का होता है। इसलिए या तो वह अयोग्यता की याचिका पर कुंडली मारकर बैठ जाता है या सत्ताधारी दल के पक्ष में फैसला दे देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय आई थी कि स्पीकर को यथाशीघ्र फैसला करना चाहिए। जनवरी 2020 में तीन जजों की बेंच ने कहा कि स्पीकर को याचिका दाखिल होने के तीन महीनों के भीतर फैसला करना होगा।

जब स्पीकर ने तीन महीनों में भी फैसला नहीं किया, तो तीन महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल करके मंत्री बने दो विधायकों को मंत्री पद से हटा दिया था और कोर्ट के अगले फैसले तक उन्हें विधानसभा में प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि समय सीमा तय करने का काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती। जबकि अभी अक्टूबर में उसी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को कहा कि 31 दिसंबर तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गुट के विधायकों और एनसीपी के अजित गुट के विधायकों पर दलबदल कानून के अंतर्गत दाखिल याचिकाओं पर फैसला करें। एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को दलबदल पर कार्रवाई का अधिकार स्पीकर से वापस लेकर किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णायक फैसला करे और संसद दलबदल कानून की विसंगतियों को खत्म करने के लिए नया बिल लाए।

तीसरा मुद्दा है मुख्यमंत्रियों की मनमानियों का। वे भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों में गिरफ्तार अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर रहे। जिससे लोकतंत्र कलंकित हो रहा है। ऐसे उदाहरण हाल ही में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली में देखने को मिले। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार गिर नहीं गई, उसके दो मंत्री जेल में थे, जिनमें एक तो महाराष्ट्र का गृह मंत्री था। अक्सर ऐसा होता है कि राज्यपालों का उन्हीं मुख्यमंत्रियों के साथ विवाद होता है, जहां केंद्र सरकार की विरोधी पार्टी की सरकार होती है। पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल और केरल हाल ही के विवादों के ताजा उदाहरण हैं। इन सभी राज्यों के राज्यपालों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में सीपीएम की सरकारे हैं, ये चारों ही राजनीतिक दल भाजपा विरोधी और इंडी एलायंस का हिस्सा हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बारे में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप को पता है कि आग से खेल रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते, इसलिए उन्हें चुनी हुई सरकारों के कामों में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। पंजाब में लंबे समय से राज्यपाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच जंग छिड़ी हुई थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल की ओर से भेजे गए किसी भी पत्र का जवाब नहीं दे रहे थे, इस पर राज्यपाल पुरोहित ने राज्य सरकार को एक धमकी भरा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि राज्य सरकार उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए उन्हें मजबूर होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ेगा कि पंजाब में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार का आरोप है कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरह का विवाद बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच चलता रहा। अब कुछ उसी तरह का विवाद तमिलनाडु सरकार और वहां के पुलिस पृष्ठभूमि के राज्यपाल आररन रवि के बीच चल रहा है।

2014 के बाद यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने किसी राज्यपाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की हो। पहले भी कई राज्यपालों की भूमिका पर कोर्ट सवाल उठा चुकी है, तो कईयों को फटकार लगा चुकी है। 2016 में जब उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ ने एक अवांछित टिप्पणी भी की थी कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट नहीं हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य में सरकार रहेगी या नहीं, यह फैसला सिर्फ विधानसभा में हो सकता है। कोर्ट ने विधानसभा में मत विभाजन का निर्देश दिया, जहां विधानसभा में कांग्रेस बहुमत हासिल करने में सफल रही।

● इन्द्र कुमार

राज्यपालों को फटकार

2016 में पूर्व आईएएस अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई जब उन्होंने बहुमत होते हुए भी कांग्रेस सरकार को अपदस्थ कर दिया था। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी और फिर कांग्रेस के ही एक बागी को मुख्यमंत्री बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने राज्यपाल जेपी राजखोवा को बर्खास्त कर दिया था। इस समय तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल और तेलंगाना के राज्यपालों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन सभी राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यपालों की मनमानी की शिकायत की है। राज्यों का कहना है कि राज्यपाल संविधान के तहत काम नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के बाद राज्यपाल की भूमिका पर बड़े पैमाने पर सुनवाई करने की बात कही है। देश में अभी 14 राज्यों में उन पार्टियों की सरकार है, जो केंद्र की सत्ता में शामिल नहीं है।

मुद्दे खाली, गारंटी पूरी

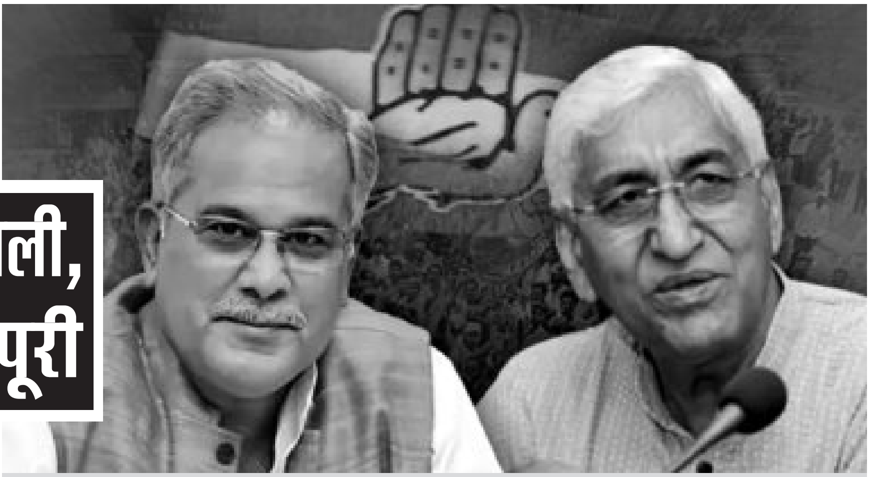

महंगाई को काबू करने की कवायद

बेरोजगारी और खासकर खाद्य वस्तुओं की महंगाई से लोगों की तंगी का एहसास अब केंद्र सरकार को भी होने लगा है। तभी तो केंद्र सरकार 27.5 रुपए प्रति किलो भारत आटा नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए बेचेगी। जाहिर है, मौजूदा नीतियों की वजह से सरकार के वश में न महंगाई पर काबू कर पाना है, न रोजगार सृजन के उपाय कर पाना। दिक्कत यह है कि कोई भी उन उपायों की ओर नहीं मुड़ रहा है जो लोगों की जिंदगी में वाजिब बदलाव ला सकें। मसलन, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्तियां देने की बात तो की जाती है लेकिन अस्पतालों और स्कूलों में सुधार की कोई बात नहीं करता, न ही दवाइयों के दाम पर अंकुश लगाने की बात होती है, न शिक्षा संस्थानों में फीस कम करने की बात होती है। उदारीकरण के दौर में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा जगजाहिर है। मतलब यह कि कोई भी निजीकरण और बाजारवादी नीतियों को बदलने की बात नहीं करता। बहरहाल, अगले पन्ने विधानसभा चुनाव वाले पांचों राज्यों में वादों और गारंटियों की फेहरिस्त से रूबरू कराते हैं और साथ ही चुनावी परिदृश्य का एक खाका पेश करते हैं। 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे न सिर्फ अगली सियासत की धार तय करेंगे, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों का नैरेटिव भी तय कर सकते हैं।

अमूमन चुनावी नारे और घोषणा-पत्र मौजूदा और अगली सियासत की झांकी पेश करते हैं। पुराने चुनावों को याद कीजिए तो कमोबेश सियासत की धारा भी वैसी ही बहती रही है। अलबत्ता, खासकर घोषणा-पत्र तो लंबे सफर में न सिर्फ अपनी अर्थवत्ता खोते गए हैं, बल्कि जुमले बनकर भी रह गए। कुछ दशक पहले तक पार्टियों के घोषणापत्रों को गंभीरता से लिया जाता रहा है, लेकिन घोषणापत्र, दृष्टिपत्र, संकल्पपत्र, वचनपत्र और अब गारंटी तक के इस सफर में मायने इस कदर खो गए हैं कि ये मतदान की तारीखों के आसपास जारी किए जाते हैं, मानो कोई पढ़ने की जहमत न ही उठाए तो बेहतर। यही नहीं, कई बार इनमें और आम पर्चे में फर्क करना भी मुश्किल होता जा रहा है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घोषणा-पत्र जारी करते समय रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सवाल में कहा भी, लंबी-चौड़ी घोषणाएं कौन पढ़ता है, इसलिए प्वाइंटर में जिक्र किया गया है। वजह शायद यह है कि नीतियों के बदले कल्याणकारी गारंटियों का दौर आ गया है। यानी जिस नीतिगत बदलाव से बड़े पैमाने पर सामाजिक पहल की जिम्मेदारी कल्याणकारी राज्य की हुआ करती थी, अब उसका जिम्मा पार्टियों ने ओढ़ लिया है। सो, जो पार्टी ज्यादा लुभावनी गारंटियां दे, वह चुनावी जीत की उम्मीद उतनी ही ज्यादा करती है।

बेशक, यह सिलसिला नब्बे के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद के दशकों में कुछ-कुछ धीरे-धीरे शुरू हुआ, जब ज्यादातर मुख्यधारा की पार्टियों में आर्थिक नीतियों को लेकर फर्क मिट गए। कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, वाम रुझान वाली पार्टियों का भी आर्थिक नजरिया बड़े और विदेश पूंजी निवेश को अकाट्य-सा मानने लगा। यानी नव-पूंजीवाद में सभी उम्मीद खोजने लगे। मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि दरअसल आजादी के बाद से ही ट्रिकल डाउन की नीति अपनाई गई और कहा गया कि समृद्धि रिस-रिस कर निचले तबके में जाएगी, लेकिन ऐसा होना नहीं था। गरीब और गरीब बनते गए। अब जब उदारीकरण के बाद के दशकों में बड़े और संगठित उद्योगों का दौर बुलंदी पर आया तो ऑटोमेशन वगैरह से रोजगार घटने लगे। नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया। फिर जो ज्यादा रियायतें देता है, उसे वोट मिलने की उम्मीद होती है।

यकीनन, इस दशक में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा है और महंगाई भी बेकाबू है। फिर, निजीकरण को बढ़ावा और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के दौर में कल्याणकारी राज्य की पूरी अवधारणा ही खत्म कर दी गई। ऐसे में पार्टियों ने तात्कालिक राहत देकर लोगों को अपना मुरीद बनाना शुरू किया। हाल के दौर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल लाभार्थी वर्ग तैयार करने की मंशा में दिखती है। जैसे 2022 में उप्र के विधानसभा चुनावों के दौरान बाकायदा लाभार्थी शब्द राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया गया। कहा गया कि भाजपा एक तथाकथित लाभार्थी चेतना की वजह से जीत गई। बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं थीं। उप्र में उस चुनाव में सपा के अखिलेश यादव ने भी जाति जनगणना समेत फिर लैपटॉप बांटने जैसे कई वादे किए। प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं... नारे के साथ कई गारंटियों का ऐलान किया था। उसके पहले बिहार में राजद के तेजस्वी यादव ने सरकार बनते ही दस लाख नौकरियां देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं और कई मदों में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने का वादा किया, लेकिन लाभार्थी वर्ग शब्द तो भाजपा की ओर से ही आया।

जब विपक्षी पार्टियों ने भी कल्याणकारी कार्यक्रमों का ऐलान शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं में कहा कि रेवड़ियां बांटने वाले देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वे और उनकी पार्टी हर चुनाव में केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में लोगों को अपनी योजनाओं का लाभ गिनाने से नहीं चूकते रहे हैं। इसी साल के शुरू में कर्नाटक में भाजपा को उम्मीद थी कि कुछ 6 करोड़ मतदाताओं में 4 करोड़ लोग केंद्र या राज्य की योजनाओं के लाभार्थी हैं जिनके वोट से जीत मिल जाएगी, लेकिन नतीजे एकदम उलटे आए।

दरअसल कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद केंद्र सरकार के लिए यूपीए सरकार के दौर के मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे कानून ही काम आए। यूपीए सरकार के 2013 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन साल तक 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल बीपीएल परिवारों को मुहैया कराना था। कोरोनाकाल में मोदी सरकार ने इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से 5 किलो अनाज मुफ्त देना शुरू किया। फिर, जनवरी 2023 से इसे सालभर के लिए बढ़ा दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में ऐलान किया कि इसे बढ़ाकर पांच साल यानी 2028 तक किया जा रहा है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

मराठा आरक्षण की आग

एक बेहद सामान्य दिहाड़ी मजदूर सा चेहरा। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे से बाल। शरीर पर साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में तेज चमक और दृढ़ विश्वास। ये हैं मनोज जरांगे, जो आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन व राजनीति का चमकता चेहरा हैं। मनोज राज्य में मराठा समुदाय को ओबीसी दर्जा देकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग को लेकर सक्रिय हैं। उनके लिए मराठा युवा जान देने तक को तैयार हैं। इस बीच राज्य की तीन पहियों की शिंदे सरकार बदहवासी में है। राज्य में मराठा मुख्यमंत्री और एक मराठा उपमुख्यमंत्री होने के बाद भी किसी की समझ नहीं आ रहा है कि इस मांग का समाधान क्या हो?

महाराष्ट्र की राजनीति और आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे का उदय आठ साल पहले गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के रूप में अनाम से चेहरे हार्दिक पटेल के चमत्कारी नेता के रूप में उदय से काफी कुछ मेल खाता है। यह बात अलग है कि बाद में हार्दिक खुद राजनीति के शतरंज का मोहरा बन गए और आज वो उसी भाजपा से विधायक हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने कभी समूचे गुजरात को हिला दिया था। अब मनोज जरांगे का हश्र क्या होता है, यह देखने की बात है, लेकिन यह मानने में हर्ज नहीं है कि आज महाराष्ट्र में गुजरात ही खुद दोहरा रहा है। ध्यान रहे कि इस देश में जातिवादी राजनीति का आरक्षण एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि यदि आरक्षण को हटा दिया जाए तो जातिवादी राजनीति महज एक जाति आधारित वोटों की गोलबंदी या फिर समाज सुधार के सात्विक आग्रह रूप में शेष रहती है। भारतीय समाज और खासकर हिंदुओं में सामाजिक न्याय के तहत संविधान में दलित व आदिवासियों के लिए जिस आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसने अब मानों यू टर्न ले लिया है। पहले माना जाता था कि जाति व्यवस्था के कारण विकास की दौड़ में पीछे रही जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों व राजनीतिक आरक्षण देकर उन्हें प्रगत समुदायों के समकक्ष लाया जा सकता है और सामाजिक समता का एक लेवल कायम किया जा सकता है।

दरअसल, वोटों की राजनीति ने सामाजिक समता के इस काल्पनिक मॉडल को जल्द ही सरकारी रेवड़ी और राजनीतिक प्रभुत्व की चाह में तब्दील कर दिया, इसीलिए समाज की मध्यम जातियों ने पहले ओबीसी के तहत आरक्षण मांगा और मिला। अब वो जातियां भी खुद को पिछड़ा कहलवाना चाह रही हैं, जो 70 साल पहले आरक्षण को राजनीतिक दान समझकर हिकारत के भाव से देखती थीं। अब विडंबना है कि आज महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार, राजस्थान में गुर्जर और हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग इसी संवैधानिक जातीय अवनयन में अपने सामाजिक उन्नयन की राह बूझ रही हैं। आरक्षण की लॉलीपाप अब उन जातियों को भी तीव्रता से आकर्षित कर रही है, जो सदियों से समाज में श्रेष्ठताभाव में जीने की आदी रही हैं। यानी अब यदि उन्हें भी आरक्षण मिले तो वो किसी भी जाति के नाम का आवरण ओढ़ने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ इन जातियों में सामाजिक समता को लेकर कोई बुनियादी मानसिक बदलाव का होना नहीं है, केवल आर्थिक बेहतरी और राजनीतिक सत्ता पाने की तात्कालिक स्वार्थसिद्धी ज्यादा है। इसी का नतीजा है कि आरक्षण की राजनीति में अब नए और समाज की निचली पायदान से आने वाले खिलाड़ियों की गुंजाइश बन रही है। यह उस स्थापित नेतृत्व के प्रति जनता का गहरा अविश्वास भी है, जो आरक्षण की फुटबाल को इस पाले से उस पाले में ठेलते रहे हैं।

41 वर्षीय मनोज जरांगे का जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले के मातोरी में हुआ। स्कूली शिक्षा उन्होंने वहीं जिला परिषद के स्कूल में पाई। तीन बेटियों और एक बेटे के पिता मनोज शुरू से ही मराठा आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में उन्होने अपना संगठन शिवबा संघटना बनाया। यूं मराठा आरक्षण आंदोलन पुराना है, लेकिन चार साल ठंडे पड़े आंदोलन में आग पैदा करने का काम जरांगे ने ही किया है। आजकल अंबड गांव के अंकुशनगर के निवासी जरांगे के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा जीने मरने का सवाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेची। जालना जिले के आंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन कर रहे जरांगे का तर्क है कि चूंकि मराठा जाति मूलत: कृषक जाति है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी है।

खेती अब लाभ का व्यवसाय नहीं रहा, इसलिए मराठों को अन्य पिछड़ी जाति वर्ग में आरक्षण दिया जाए। जरांगे दो साल पहले भी 90 दिनों तक अनशन कर चुके हैं, लेकिन तब उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि वह आंदोलन शांतिपूर्ण था। उनके दूसरे अनशन के दौरान मराठा आरक्षण में आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया था। तब राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मराठों को आरक्षण के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

● **बिन्दु माथुर**

हार्दिक पटेल से तुलना क्यों?

उधर जरांगे के बरक्स गुजरात के एक गांव में 20 जुलाई 1993 को जन्मे हार्दिक पटेल भी एक सामान्य पाटीदार परिवार से हैं। उनके पिता और छोटे कारोबारी भरत पटेल कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। पढ़ाई में कमजोर रहे हार्दिक कॉलेज की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आ गए और छात्र राजनीति करने लगे। बीकॉम करते हुए वो सहजानंद कॉलेज छात्र संघ के निर्विरोध महासचिव चुने गए। हार्दिक ने कॉलेज में ही 2012 में पाटीदार युवाओं का एक समूह सरदार पटेल ग्रुप ज्वाइन किया। एक माह के अंदर ही हार्दिक इस ग्रुप की वीरमगाम शाखा के अध्यक्ष बन गए। लेकिन साथियों से विवाद के टकराव के बाद उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया। हार्दिक के मन में पाटीदार आरक्षण की आग तब सुलगी जब उनकी बहन मोनिका ज्यादा नंबर लाने के बाद भी 2015 में सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में असफल रहीं, क्योंकि पाटीदारों को आरक्षण नहीं था। इसके बाद हार्दिक ने ठान लिया कि वो पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे।

राजस्थान में कांग्रेस, भाजपा और सभी पार्टियों का सारा दारोमदार अब सीधे ओबीसी वोटरों पर है। भाजपा की कोशिश है कि ओबीसी वोटर उसके साथ जुड़ा रहे, तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी उसे सीधा लाभ होगा इसीलिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी मोदी और भाजपा दोनों की काट में ओबीसी को अपने साथ जोड़े रखने पर पूरा फोकस किए हुए है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं, तो क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के हनुमान बेनीवाल भी अपने ओबीसी होने को ही फोकस कर रहे हैं।

राजस्थान की आबादी में ओबीसी मतदाता सर्वाधिक लगभग 48 फीसदी होने और 200 विधानसभा सीटों में से सीधे-सीधे 150 सीटों पर निर्णायक होने के बावजूद ओबीसी को सामान्य वर्ग में ही गिना जाता हैं, क्योंकि विधानसभा सीटों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए ही है। राजस्थान में एससी 18 फीसदी और एसटी 14 फीसदी हैं, जबकि ओबीसी सबसे ज्यादा 48 फीसदी हैं। ओबीसी वर्ग में तीन सबसे बड़ी जातियां जाट, गुर्जर व माली-सैनी ओबीसी के ताकतवर समुदाय गिने जाते हैं। ओबीसी में जाटों की हिस्सेदारी लगभग 10 फीसदी है, गुर्जर 7.5 फीसदी और माली-सैनी 6.5 फीसदी के आसपास हैं। हालांकि, राजस्थान में जाटों और दलितों की दोस्ती का भाजपा पर असर क्या होगा, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, मगर कांग्रेस को सीधा नुकसान और भाजपा को लाभ जरूर होगा, यह दिख रहा है। जाट, गुर्जर व माली-सैनी, ये तीनों जातियां ताकतवर होने व सबसे ज्यादा होने के बावजूद 2018 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों में से 38 सीटों पर जाट विधायक जीते, गुर्जर 8 और माली-सैनी केवल 2 ही विधायक जीते। माली-सैनी विधायक सबसे कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस समाज ने अपनी ताकत की राजनीतिक एकजुटता कभी नहीं दिखाई और ज्यादातर लोग भले ही वोट भाजपा को भी देते रहे, मगर समाज ने अपनी सारी ताकत तीन बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत में निहित मान ली है, क्योंकि वे ही माली-सैनी के सबसे बड़े नेता भी हैं। जाटों में कई नेता हैं, लेकिन जाट राजघराने धौलपुर रिसायत की पूर्व महारानी होने के कारण वसुंधरा राजे जाटों की भी सबसे बड़ी नेता हैं और इन दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) जैसे क्षेत्रीय दल के मुखिया के रूप में जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो गुर्जरों में सचिन पायलट कद्दावर नेता गिने जाते हैं। जाट समुदाय के लोग राजस्थान में कम से कम 65 विधानसभा सीटों पर हार-जीत को प्रभावित करते हैं, इसी कारण दोनों पार्टियों में कुल मिलाकर लगभग 20 फीसदी विधायक पदों पर जाट जीतते हैं।

राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 33 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची 142 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, जिसके लिए बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने 10 फीसदी जाटों और 18 फीसदी एससी को मिलाकर दलित-जाट मतदाता का गठबंधन बनाया है। इसका अगर सही और सीधा असर रहा, तो माना जा रहा है कि यह आने वाले विधानसभा के चुनावी समीकरण बदलने में जबरदस्त सफल रहेगा। बेनीवाल ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से भी राजस्थान में हाथ मिलाया है। भाजपा जान रही थी कि इस गठबंधन के कारण ओबीसी को साधने का उसका निशाना चूक सकता है, इसी वजह से भाजपा हनुमान बेनीवाल का निशाना असफल बनाने की कोशिश में बेहद सधे हुए कदमों से अपनी चाल चल रही है। भाजपा ने अपने कद्दावर जाट नेताओं के सामने आरएलपी-दलित गठबंधन के कमजोर उम्मीदवार देने के मामले में बेनीवाल को मना लिया है, ऐसा साफ लग रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आए थे, तो उन्होंने ओबीसी वर्ग को भाजपा द्वारा दिए गए फायदों को गिनाते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखती है, खासतौर पर वंचित वर्ग का। मोदी जब यह कह रहे थे, तो उनके दिमाग में स्पष्ट तौर पर यही था कि राजस्थान में ओबीसी से बड़ा वंचित वर्ग और कोई नहीं है।

साफ दिख रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ओबीसी के सबसे बड़े वर्ग जाटों को साथ रखे रहने की पूरी कोशिश में है, तो गुर्जर वोट भी बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ तेजी से जुड़ रहा है, जो कि पिछली बार नहीं था। इसका सीधा फायदा भाजपा की सीटों में इजाफा करेगा। राजस्थान में भाजपा जान रही है कि ओबीसी वर्ग के वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा उसी के पास है। अशोक गहलोत ओबीसी वर्ग से होने और लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ओबीसी को कांग्रेस के साथ जोड़ने में कोई खास सफल नहीं रहे हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कांग्रेस के लिए ओबीसी वोट की चुनौती

राजनीति के जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत को इस बार के मुख्यमंत्री काल में फ्री हैंड तो मिला, मगर कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक हालातों और सचिन पायलट द्वारा हर कुछ माह में कुर्सी हड़पने की कोशिशों के कारण वे पूरे पांच साल अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। इसके कारण वे ओबीसी को अपने साथ नहीं जोड़ सके। गहलोत जाति से सैनी (माली) हैं मगर उनकी अपनी ही जाति के वोट उनके विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा (जोधपुर) को छोड़कर लगभग 70 फीसदी से ज्यादा पूरे राजस्थान में भाजपा को मिलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता सचिन पायलट भी गुर्जर होने के कारण होने को तो ओबीसी ही हैं, मगर वे गुर्जर या ओबीसी नेता के रूप में स्वयं को स्थापित करने से बचते रहे। अपने समुदाय में उनका जबरदस्त प्रभाव है। गुर्जर भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन 2018 के चुनाव में पायलट के मुख्यमंत्री बनने की आस में गुर्जर मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया था। पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता के करीब तो पहुंची, मगर बहुमत 200 में से 100 सीटों पर ही होने की वजह से सरकार के कभी भी गिरने की संभावना में गहलोत ही सबसे सही नेता होने के कारण कांग्रेस ने पायलट को किनारे कर दिया और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, तो गुर्जर भी कांग्रेस से बिदक गया। इस चुनाव में पायलट शांत-शांत से हैं और गुर्जर कांग्रेस को मजा चखाने की फिराक में फिर से भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहा है।

सपा से बिगड़ी बात!

उप्र की राजनीति में विपक्ष के कैंप में दो सवालों पर खूब चर्चा हो रही है। पार्टी दफ्तरों से लेकर चौक चौराहों तक पहला सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? क्या इन दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है? वैसे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। लेकिन इन दिनों दोनों पार्टियों में जबरदस्त ठनी हुई है। दोनों एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दे रही हैं। कांग्रेस ने मप्र में समाजवादी पार्टी के लिए सीट नहीं छोड़ी। तो अब अखिलेश यादव भी मप्र का बदला उप्र में लेने की चुनौती दे रहे हैं।

क्या राहुल और प्रियंका गांधी इस बार उप्र से चुनाव लड़ सकते हैं? कांग्रेसी ही नहीं, इस सवाल का जवाब भाजपा वाले भी जानना चाहते हैं। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का संकेत दिया है। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। अब वे केरल के वायनाड से सांसद हैं। राहुल और प्रियंका गांधी लंबे समय से उप्र नहीं आए हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ही उप्र प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने मना नहीं किया। वे कह सकती थीं कि वहां से तो सोनिया जी लड़तीं हैं। पार्टी के कुछ नेता इस बात की तरफ इशारा करने लगे हैं कि प्रियंका रायबरेली और राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के उप्र प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी ऐसा ही चाहते हैं। फैसला तो नेहरू गांधी परिवार को लेना है। पर पार्टी के नेता मानते हैं कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है।

दीवाली पर इस बार कांग्रेस की तरफ से अमेठी के हजारों लोगों को तोहफे दिए गए। किसी को दिए का पैकेट, तो कुछ को कपड़े, तो कई लोगों को मिठाई मिली। लेकिन गिफ्ट के हर पैकेट पर प्रियंका और राहुल गांधी की फोटो लगी हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे कांग्रेस के नेता दीपक सिंह बताते हैं कि हर दीपावली में लोगों को मिठाई भेजी जाती है। लोकसभा चुनावों से पहले राहुल और प्रियंका के फोटो वाले गिफ्ट के पैकेट की अमेठी में बड़ी चर्चा है। ऐसे ही तोहफे अमेठी की भाजपा सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से भी भेजे गए हैं। अमेठी में दो बार राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला हो चुका है। एक बार राहुल जीते तो एक बार स्मृति ईरानी। प्रियंका गांधी का रोल अब तक अपनी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने का ही रहा है। रायबरेली के कांग्रेसी दिल्ली जाकर प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और सपा इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन मप्र विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है तो सवाल उठता है कि उप्र में लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां कैसे दोस्ती निभाएंगी। वहीं, सपा उप्र में कांग्रेस को देख लेने की धमकी दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन उप्र में बिखरने की स्थिति में दिख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।

मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच तल्खियां देखने को मिली हैं। मप्र में दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रही हैं। दरअसल, कांग्रेस ने सपा के लिए मप्र में एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। इसके साथ ही कई सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नुकसान भी कर रही है। जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलते हुए दिख रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मप्र विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश-डिंपल के साथ ही सपा की पूरी ब्रिगेड ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है।

मप्र विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ी दूरियों का अहसास भाजपा को भी है। भाजपा इसका फायदा उठाने से चूकने वाली नहीं है। अब तो भाजपा इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगी है। यदि सपा-कांग्रेस में उप्र के अंदर बात नहीं बनी तो भाजपा का उप्र की 80 में से 80 सीटों को जीतने का दावा सच भी साबित हो सकता है। वहीं, अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। प्रियंका और राहुल गांधी क्या उप्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही भाजपा भी जानना चाहती है। भाई-बहन लोकसभा चुनाव उप्र से लड़ेंगे, उनकी क्या रणनीति है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं। वहीं, प्रियंका गांधी ने उप्र विधानसभा हार के बाद उप्र प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही दोनों भाई-बहन लंबे समय से उप्र नहीं आए हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा

लोकसभा चुनाव में यदि प्रियंका गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी मानना है कि यदि राहुल और प्रियंका उप्र से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा पार्टी को मिलेगा। नेहरू-गांधी परिवार को तय करना होगा कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं, मप्र चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी से कई बार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं, पार्टी के कई बड़े नेता भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि प्रियंका और राहुल उप्र से चुनाव लड़ सकते हैं।

दांव पर लोकसभा चुनाव

रोजगार, जातिगत सर्वे और फिर 75 फीसदी आरक्षण जैसे बैक टू बैक मास्टरस्ट्रोक चल कर नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्ष को एक तरह से मूर्छित अवस्था में पहुंचा दिया है। राजनीतिक रूप से इन चालों की काट सूझ नहीं रही हैं। ऐसे में उनके हाल के दो बयानों और कुछेक आपराधिक घटनाओं के कारण बिहार और नीतीश कुमार लगातार चर्चा में हैं या कहें कि गलत तरीके से चर्चा में बनाए रखने (राजनीतिक मजबूरीवश) की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार का समाज विपक्ष के इन झांसों में आ जाएगा, या कि वह फिर रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार-तेजस्वी यादव के महागठबंधन के साथ और मजबूती से जुड़ेगा?

मीडिया और मतदाताओं का एक मुखर किंतु छोटा ही हिस्सा नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान से इतना खुश हो गया, मानो उनके हाथ कुबेर का खजाना लग गया हो। बिहार में विपक्ष यह भूल गया कि उनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्ल फ्रेंड, ताड़का जैसा अट्टाहस और जेएनयू में कंडोम के ढेर जैसे बयान देने के बाद भी स्पष्ट बहुमत पाते रहे हैं। यानी, जनता की नजर में, मतदाताओं की नजर में इन राष्ट्रीय नेताओं के राजनीतिक बयान से अधिक महत्व एजेंडे का रहा, मुद्दे का रहा, वादों का रहा, कामों का रहा, जो इन नेताओं या पार्टियों ने किए या करने के सपने दिखाए। तो फिर यही फॉर्मूला नीतीश कुमार के केस में क्यों नहीं लागू होगा?

क्यों नहीं बिहार की जनता बजाए उनके जनसंख्या नियंत्रण बयान पर ध्यान देने के इस बात पर ध्यान देगी कि कैसे वे लगातार लाखों सरकारी-स्थायी रोजगार का सृजन कर रहे हैं, कैसे वे सामाजिक न्याय को मजबूती से लागू करने के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या पिछले 10 सालों में क्या हिंदुस्तान के किसी आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ है कि किन्हीं एक बयान के कारण परिणाम उलट गए हो? ऐसा कुछ याद तो नहीं आता। उलटे पिछले कुछ सालों के दौरान राजनीतिक भाषणों और शब्दों की गरिमा चहुंओर गिरी है। भाषाई मर्यादा तार-तार होती चली गई, उसके मुकाबले देखा जाए तो नीतीश कुमार तब भी एक जेंटल राजनेता नजर आते हैं, जो भाषाई मर्यादा आमतौर पर नहीं खोते!

हां, कहने वाले यह जरूर कह सकते है कि सदन के भीतर जिस तरह से नीतीश कुमार मांझी के बयानों पर अपना आपा खो दिए और यहां तक कहा डाला कि मेरी मूर्खता के कारण मांझी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। निश्चित तौर पर संसदीय गरिमा को देखते हुए उन्हें यह सच नहीं बोलना चाहिए था। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। राजनीति शास्त्र का नवांकुर भी जानता होगा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत बात नहीं की थी लेकिन यह बयान पोलीटिकली करेक्ट नहीं था। और यही हुआ भी। विपक्ष ने तत्काल मांझी के आवास पर बैठक की और इसे महादलित के अपमान के तौर पर प्रचारित करने की कोशिशें शुरू कर दीं। राजनीतिक रूप से ऐसा ही होना था, हो भी रहा है लेकिन क्या मांझी, जो खुद कई सीटों से चुनाव लड़कर, बमुश्किल जीत पाते हैं, इतना दमखम रखते हैं कि अपनी जाति के वोट को जहां चाहे वहां ट्रांसफर करवा दें?

फिर नीतीश कुमार की पार्टी के महादलित नेताओं की हैसियत क्या रह जाएगी? फिर अशोक चौधरी और रत्नेश सदा जैसे नेताओं की क्या वकत रह जाएगी? और मांझी पर यह आरोप लगते रहे हैं, खुद भाजपा के लोग भी मानते हैं कि वे बिहार में राजनीति का इस्तेमाल अपने और अपने बेटे और रिश्तेदारों को सेट करने के लिए करते हैं। उनके बयान, उनके काम, उनकी मंशा कहीं से भी ऐसी नहीं दिखती कि वे अपने समुदाय की गरीबी और जहालत से परेशान हों और उसे दूर करना चाहते हों। ऐसे में अकले मांझी बयान से नीतीश कुमार के रोजगार और आरक्षण सीमा बढ़ाने जैसे मास्टरस्ट्रोक बेअसर हो जाएंगे, बिहार में विपक्ष के लिए ऐसा सोचना भी राजनीतिक रूप से खुशफहमी का शिकार बनने जैसा होगा।

● **विनोद बक्सरी**

सरकार के लिए अपराध एक चुनौती!

बेशक बिहार में अब भी अपराध गुड गवर्नेंस के लिए एक चुनौती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री एनसीआरबी के डेटा का हवाला देकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिहार जैसे राज्य का जीडीपी ग्रोथ रेट भले अधिक हो लेकिन क्राइम को लेकर भी आमजन के बीच जो परसेप्शन बना है, वह चिंताजनक है और महागठबंधन सरकार को इसे लेकर सचेत और सतर्क रहना चाहिए। मसलन, बालू माफिया की अति-सक्रियता एक बेहद चिंताजनक विषय है। यह संगठित अपराधिक गिरोह की तरह चलता है। लैंड और लीकर (शराब) माफिया भी बदलते बिहार की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं। हाल ही में एक पुलिस अधिकारी पर जिस तरह से बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर चलाकर उनकी हत्या कर दी, यह न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। अब महागठबंधन सरकार को गंभीरता से इस पर फाइनल अटैक करने की जरूरत हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर रोजगार सृजन और आरक्षण के जरिए सामाजिक न्याय की लड़ाई से मिल रही प्रतिष्ठा पर धब्बा ही लगेगा। क्या नीतीश कुमार ऐसा चाहेंगे, क्या तेजस्वी यादव ऐसा चाहेंगे कि उनकी साख, उनकी मेहनत, उनके नेक इरादों पर ऐसे बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया काला धब्बा लगा दें? शायद कभी नहीं। तो, ऐसा लगता है कि जिस तरह से मौजूदा बिहार सरकार कई मोर्चों पर काम करते हुए एक समग्र सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश में जुटी हुई है, इसी के साथ ही उसे अपराध को लेकर भी जीरो टोलरेंस नीति बनानी चाहिए?

बांग्लादेश ने बढ़ाई चिंता

बांग्लादेश बीआरआई में भी सहयोगी

बांग्लादेश अब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में भी सहयोगी है। बांग्लादेश के लिए चीन का यह आश्वासन वाशिंगटन की इस धमकी को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि इस साल के अंत में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं हुए तो उसकी कीमत शेख हसीना की सरकार को चुकानी पड़ेगी। भारत की दुविधा यह है कि जिस शेख हसीना को अमेरिका टारगेट कर रहा है, उनका समर्थन भारत करता रहा है। भारत ने शेख हसीना का विश्वास जीतने के लिए काफी निवेश भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को एक नया आयाम दिया है। श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव में चीन काफी हद तक अपनी जड़ें जमा चुका है। यदि बांग्लादेश भी उसके प्रभाव में आता है तो भारत के लिए पड़ोसी मुल्कों से ही चुनौतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी।

बांग्लादेश में होने वाला संसदीय चुनाव चीन और अमेरिका दोनों के लिए जोर आजमाइश का खेल बनता जा रहा है। अमेरिका खुलेआम शेख हसीना की सरकार को बार-बार यह धमकी दे रहा है कि यदि अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव बिना किसी हिंसा के नहीं हुए तो वाशिंगटन ढाका के लिए अपनी नीतियां कड़ी कर सकता है। अमेरिका वीजा से संबंधित चेतावनी पहले ही जारी कर चुका है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को अमेरिका आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अब बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास ने ढाका में मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह सलाह दी है कि वह विपक्षी दल बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के साथ बैठक करें और चुनाव के अनुकूल माहौल बनाएं। इस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से हालात वहां बिगड़ रहे हैं, उससे इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बांग्लादेश में मिलिट्री शासन न लागू हो जाए। शेख हसीना अमेरिकी दखल से काफी परेशान हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अमेरिका को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि वह विपक्ष के साथ तभी बातचीत करेंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बातचीत के लिए बैठेंगे। जाहिर है इन शब्दों में उन्होंने यही संकेत दिया कि अमेरिका उनको कोई निर्देश न दे। इसके आगे हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लोग हत्यारों से कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव होगा और तय समय पर होगा। प्रधानमंत्री ने बीएनपी पर आरोप लगाया है कि यह पार्टी चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने पर तुली हुई है।

भारत के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चीन और अमेरिका का बांग्लादेश में दखल यदि आगे और बढ़ता है तो भारत के लिए मूकदर्शक बने रहना संभव नहीं होगा। भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी मुल्क का मामला नहीं है, बल्कि सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश में एक स्वतंत्र किंतु लिबरल सरकार का होना जरूरी है। यदि यहां भी कोई मजहबी और शरिया लागू करने वाली सरकार आती है या फिर कोई मिलिट्री विद्रोह होता है तो वहां रह रहे लगभग डेढ़ करोड़ हिंदुओं के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में शेख हसीना का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। बीजिंग ने शेख हसीना की सरकार के साथ मिलकर कई परियोजनाएं शुरू की हैं। बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण (बीडा) के आकड़ों के अनुसार कम से कम 15 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में प्रत्यक्ष निवेश लेकर आई हैं। इसके अलावा, पिछले साल 1.5 अरब डॉलर के एफडीआई प्रस्ताव भी आए थे। बांग्लादेश बैंक के आंकड़े कहते हैं कि देश में चीन से एफडीआई की वार्षिक वृद्धि 13.5 प्रतिशत रही। 2015 में चीन से प्राप्त निवेश सिर्फ 56 मिलियन डॉलर का था, जो अब 12 गुना बढ़ गया है।

दूसरी तरफ अमेरिका शेख हसीना को लोकतंत्र का दुश्मन बता रहा है। इसी साल सितंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि अपने 14 वर्षों के कार्यकाल में शेख हसीना ने पुलिस, सेना और अदालतों तक पर कब्जा कर लिया है। हर जगह उन्होंने अपने वफादारों को भर दिया है और उन्हें यह बता भी दिया है कि उनके नियमों का पालन न करने के परिणाम क्या होंगे। हसीना ने संस्थाओं का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया है। उनके निशाने पर कलाकार, पत्रकार, कार्यकर्ता और यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ प्रतिशोध का गहरा और व्यक्तिगत अभियान चलाया है।

2023 में बांग्लादेश ने चीन के लिए अपने सभी दरवाजे खोल दिए। दोनों देशों के बीच उड़ानें बढ़ रही हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। अधिक संख्या में चीनी बांग्लादेश आ रहे हैं और अधिक बांग्लादेशी चीन जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 23 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले थे। वहां जो मुख्य बातें हुईं उनमें जिनपिंग का शेख हसीना को यह आश्वासन भी था कि बीजिंग बाहरी हस्तक्षेप से बांग्लादेश को बचाएगा।

● ऋतेन्द्र माथुर

mycem cement
HEIDELBERGCEMENT
mycem power
Trusted German Quality
Over 150 Years
Send 'Hi' 7236955555

महिलाएं होंगी गेम चेंजर!

मप्र में 17 नवंबर को हुए मतदान में रिकॉर्डतोड़ 77.15 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। 66 साल में सबसे अधिक वोटिंग इस बार हुई है। इसके साथ ही महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में इस बार ज्यादा मतदान किया है। जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक 35 विधानसभा सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के मतदान में जो अंतर साल 2018 में था, लगभग उसी तरह 2023 में भी देखने को मिला है। पिछले चुनाव में महिला-पुरुष के वोट में 1.95 प्रतिशत का अंतर था, जबकि इस बार 2.18 प्रतिशत का है। हालांकि ये जरूर है कि पिछली बार 50 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा थी, लेकिन इस बार 35 सीटों पर मामला सिमटा हुआ है। इन 35 सीटों में से 24 सीटें तो अकेले विंध्य की हैं।

गौरतलब है कि विंध्य क्षेत्र में कुल 30 सीटें आती हैं। यहां की करीब 24 सीटों पर महिलाओं ने बंपर वोटिंग की है। सबसे रोचक बात ये है कि जिन 24 सीटों पर सबसे ज्यादा बंपर वोटिंग की गई है, उनमें से 2018 में 19 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही महाकौशल की 7 सीटों पर महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। उधर भोपाल के दक्षिण पश्चिम में भी पुरुषों ने 58.61 प्रतिशत तो महिलाओं ने 59.66 प्रतिशत वोट डालें। जिन सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से आगे रहीं, उनमें चित्रकूट, रैगांव, नागोद, मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मउगंज, देवतालाब, मनगवां, गुढ़, चुरहट, सीधी, सिहावल, चितरंगी, धौहनी, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, जैतपुर, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, मानपुर सिहोरा, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, लांजी, परसवाड़ा, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, पवई, पन्ना, मुलताई शामिल हैं।

मप्र विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर मतदान हो गया है। इसके बाद हार-जीत का मंथन शुरू हो गया है। इस बार महिलाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया है। प्रदेश की 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। पिछली बार दो प्रतिशत मतदान बढ़ा तो सरकार बदल गई थी। हालांकि विंध्य की 29 सीटों में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले थे, जिसमें से 19 पर भाजपा जीती थी। जबकि 2018 में 44 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। महिलाओं के बढ़े मत प्रतिशत को भाजपा लाड़ली बहना का असर बता रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ बदलाव के लिए मतदान बता रही है। प्रदेश में कुल मतदान 77.15 प्रतिशत में से 78.21 प्रतिशत पुरुष और 76.03 प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया है। पिछली बार 74.01 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था।

मप्र विधानसभा चुनाव में 77.15 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। प्रदेश की 35 विधानसभा में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। वहीं 29 सीटें ऐसी है, जहां महिलाओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इस बार 1 हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 945 हो गई है। जबकि 2018 में 10 सीटों पर महिलाओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी। वहीं, 1 हजार पुरुषों पर महिला वोटरों की संख्या 917 थी। महिलाओं की बंपर वोटिंग को लेकर भाजपा इसे लाड़ली बहना योजना का असर मान रही है तो कांग्रेस इसे नारी सम्मान का प्रभाव। गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव को लाड़ली बहना योजना के दम पर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपए देने की घोषणा की।

राज्य में युवा चार फीसदी के आसपास हैं, जिन्हें अपने पाले में रखने के लिए कांग्रेस ने वादों की एक फेहरिस्त सामने रखी है। इनमें सरकारी भर्ती का कानून, स्टार्ट अप नीति और 1500-3000 रुपए हर महीने आर्थिक मदद शामिल है। वहीं भाजपा हर एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय बनाने और 3,800 टीचरों की भर्ती करने की बात कर रही है। साथ ही वह हर परिवार में एक रोजगार या खुद के रोजगार के मौके मुहैया कराने का जिक्र कर रही है। बात किसानों की करें तो उनके लिए गेहूं और धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का जिक्र दोनों दल कर रहे हैं। महिला वोटर को यहां के चुनाव में किंगमेकर माना जा रहा है। इसकी वजह भी साफ है। राज्य में महिला वोटरों की तादाद 2 करोड़ 72 लाख तक पहुंच गई है और करीब 29 सीटें ऐसी हैं, जिन पर आधी आबादी का वोट बाजी पलट सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक के भाषणों में महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र होता दिखा। शिवराज सिंह चौहान अपनी दावेदारी लाड़ली बहना स्कीम के बल पर ही सामने रख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि महिलाएं उनकी नैया एक बार फिर पार लगा देंगी। अधिकतर इलाकों में महिलाएं इस बात को मान भी रही हैं कि लाड़ली बहना योजना की किस्तें उनके अकाउंट में आ रही हैं। लाड़ली बहना स्कीम के असर को काटने के लिए कांग्रेस ने भी महिला वोटर्स को फोकस कर अपना कैंपेन प्लान किया। लाड़ली बहना के जवाब में कांग्रेस नारी सम्मान योजना ले आई। महिलाओं के लिए खासकर लाड़ली बहना योजना और नारी सम्मान योजना को लेकर जिस तरह से दोनों पार्टियों में होड़ दिखी, उससे समझ आता है कि महिला वोट पर कब्जे को लेकर दोनों राजनीतिक दल कितने बेचैन हैं। शिवराज सभाओं में मंच पर महिला वोटर से भावनात्मक अपील कर रहे थे, तो कमलनाथ भी उन्हें इमोशनल चिट्ठी लिख रहे थे। अब इनमें से किसका इमोशन भारी पड़ेगा, यह देखना बाकी है।

● ज्योत्सना

महिलाएं जिसके साथ, सत्ता उसके हाथ

मप्र की 230 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की गूंज पूरे प्रदेश में है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजे पर नजर डालें तो समझ आता है कि लोग क्यों कह रहे हैं कि पलड़ा इस वक्त किसी के भी पक्ष में झुक सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा (41.02 प्रतिशत) और कांग्रेस (40.89 प्रतिशत) दोनों का वोट शेयर लगभग समान था और सीटों का अंतर सिर्फ पांच था। भाजपा ने 230 में से 109 और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं। राज्य ने 2020 में जो राजनीतिक उथल-पुथल देखी, उसके बावजूद इस बार के चुनाव में कोई लहर या अंतर्धारा नहीं दिखी। मतदान प्रतिशत, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है- 77.15 प्रतिशत रहा, जो मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। कई लोग इस भारी मतदान को राज्य में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों पक्षों ने कई लोकलुभावन वादे किए।

रामकथा सुन्दर कर तारी

जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कभी अचानक से कोई ऐसी विपत्ति आ खड़ी होती है, जिससे पार पाने में इंसान खुद को असमर्थ पाता है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो हर कोई अपने आराध्य देव का नाम लेता है। आराध्य देव का नाम लेने के अलावा कई ऐसे मंत्र हैं, जो इंसान को किसी भी तरह के संकट से उबारने में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि आपको भी किसी तरह का संकट या चिंता सता रही है, तो आप रामचरित मानस की चौपाइयों का सहारा ले सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति, भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि रामचरितमानस की चौपाइयां इतनी प्रभावशाली हैं कि इसके पाठ मात्र से धन की कामना रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए रामचरितमानस की केवल इन चौपाइयों का पाठ करने मात्र से शुभ फल मिलता है।

भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। शनि की दशा में भगवान राम को वनवास तथा सीताजी का हरण हुआ। इस समय रुद्रअवतार हनुमानजी से उनका मिलन हुआ। जिनका अवतार ही शनिप्रदत्त दुखों के निवारण के लिए हुआ था। हनुमानजी के सहयोग से रामजी ने शनि की दशा में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया। भगवान राम को कलयुग में मानव को शनिग्रह या मायाजनित कष्टों का पूर्ण ज्ञान था जिसके लिए उन्होंने अपने परमप्रिय भक्त हनुमान को धरती में ही रुकने का आदेश दिया। प्रभु श्रीराम ने हनुमान से कहा कि जहां-जहां रामायण का पाठ होगा, वहां आपका वास होगा तथा शनि और कलयुग प्रदत्त कष्ट वहां से भाग जाएंगे। प्रभु श्रीराम के आदेश पर ही हनुमानजी ने तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना करवाई। यही रामचरितमानस कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने के लिए रामबाण के समान है। जहां-जहां रामचरितमानस का पाठ होता है वहां भगवान हनुमानजी अवश्य पधारते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में ऐसी क्षमता है कि इन चौपाइयों के जप से ही मनुष्य बड़े-से-बड़े संकट में भी मुक्त हो जाता है। इन मंत्रों का जीवन में प्रयोग अवश्य करें, प्रभु श्रीराम आप के जीवन को सुखमय बना देंगे।

संपत्ति प्राप्ति के लिए

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं।
सुख संपत्ति नानाविधि पावहिं।।

मनोकामना पूर्ति एवं सर्वबाधा निवारण हेतु

कवन सो काज कठिन जग माही।
जो नहीं होइ तात तुम पाहीं।।

आजीविका प्राप्ति या वृद्धि हेतु

बिस्व भरन पोषन कर जोई।
ताकर नाम भरत असहोई।।

शत्रु नाश के लिए

बयरू न कर काहू सन कोई।
रामप्रताप विषमता खोई।।

भय व संशय निवृत्ति के लिए

रामकथा सुन्दर कर तारी।
संशय बिहग उड़व निहारी।।

अनजान स्थान पर भय के लिए

मामभिरक्षय रघुकुल नायक।
धृतवर चाप रुचिर कर सायक।।

भगवान श्रीराम की शरण प्राप्ति हेतु

सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना।
सरनागत बच्छल भगवाना।।

विपत्ति नाश के लिए

राजीव नयन धरें धनु सायक।
भगत बिपति भंजन सुखदायक।।

रोग तथा उपद्रवों की शांति हेतु

दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहिं ब्यापा।।

हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्रीराम की पूजा और उनकी भक्ति जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली मानी गई है। यही कारण है कि भगवान राम के भक्त दशहरे के उस महापर्व पर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं, जिसे विजय पर्व या फिर कहें विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम कथा और उनका गुणगान करने वाली चौपाइयों में इंसान की हर समस्याओं का हल छिपा हुआ है, जिसे विजयादशमी के दिन सच्चे मन से जाप करने पर साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस की उन चमत्कारी चौपाइयों के बारे में जानते हैं, जिसे जपते ही जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है।

अच्छी सेहत के लिए मानस की चौपाई

कहते हैं कि तंदुरूस्ती हजार नियामत है। यही कारण है कि हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि वह हमेशा तन और मन से स्वस्थ रहे, लेकिन कई बार कुछ लोगों के जीवन में कुछ रोग ऐसे आते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं या फिर कुछ लोगों को हमेशा तमाम तरह के रोग घेरे रहते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो अच्छी सेहत का वरदान पाने के लिए दशहरे के दिन नीचे लिखी चौपाई को भगवान श्रीराम की पूजा में अधिक से अधिक जाप करें और आगे भी प्रतिदिन जारी रखें।

दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहिं ब्यापा।।

अमंगल से बचने के लिए मानस की चौपाई

यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में हर समय कोई न कोई संकट बना रहता है या फिर आए दिन आपको करियर-कारोबार से लेकर निजी जीवन में नुकसान झेलना पड़ता है तो आपको अशुभता से बचने और शुभता को पाने के लिए प्रतिदिन श्रीरामचरितमानस की नीचे दी गई चौपाई का पाठ प्रात:काल सूर्योदय के समय तन और मन से पवित्र होकर करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसीदास जी की इस चौपाई का सच्चे मन से जप करने पर सोचा गया हर काम बगैर किसी बाधा के संपन्न होता है।

मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी।।

पैसों की किल्लत दूर करने वाली मानस की चौपाई

हिंदू मान्यता के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई सभी दुख को दूर करके सुख और संपत्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। यदि आप इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपनी जरूरतें पूरा कर सकें तो आपको धन-धान्य की प्राप्ति के इस चौपाई का जाप दशहरे के दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन करना चाहिए। मान्यता है कि इस चौपाई का जाप करते ही व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। उसे धन और संपत्ति दोनों का सुख प्राप्त होता है।

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं।
सुख संपत्ति नानाविधि पावहिं।।

● ओम

ट्रिग्नोमेट्री

कॉलेज में एडमिशन हुआ, कुछ सहेलियों के साथ रोज ही जाने लगी। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था। घर मे पापा बहुत नियम कायदे वाले थे, लड़को से बात नहीं करने की हिदायत देते रहते थे। पर मजबूरन उस शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था, को एजुकेशन...क्या करते। मैंने ही मन में ठाना था, सिर्फ पढ़ाई ही करूंगी, और कुछ नहीं।

दो-चार दिन मुझे अकेले कॉलेज जाना पड़ा। मेरी गणित की प्रोफेसर एक महिला ही थी, अधिक उम्र भी नहीं थी। एक दिन एक लड़के ने रास्ते से ही मुझे बात करनी चाही, आप वहीं हैं न, जो मास्टरजी की बेटी हैं।

मैं भी आपकी क्लास में हूं, कोई पुस्तक की जरूरत हो तो बताइएगा।

रोज कुछ न कुछ बातें सुनकर मैं पहचानने लगी कि ये लाइन मार रहा है। एक दिन मुझे एक पन्ने में कुछ लिखकर कुछ पकड़ाया, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज हल कर देना।

मैंने क्लास में आकर एक नजर उस कागज को देखा और गणित की प्रोफेसर महोदया को पकड़ाया, मैम ये मनोज का ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न हल कर दीजिए।

फिर तो मजा आ गया, मैम ने जोर से पूरी क्लास को सुनाया, जानू, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या अपना समय एक्स, वाई, जेड, साइन थीटा, कॉश थीटा में बर्बाद कर रही हो। आओ तुमको मूवी दिखाऊं, मसाला डोसा खिलाता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें देखने कॉलेज आता हूं। उसके बाद ये मनोज जी उस कॉलेज में कभी नहीं दिखे।

- भगवती सक्सेना गौड़

न करना अब याद

न करना अब याद वफाएं
न यादों में आना तुम।
नदिया के तट कहां मिलते हैं
सोच के दिल समझाना तुम।।
मिलन के मौसम आएंगे फिर
मन को मत भरमाना तुम।
फिर रंगों की होगी बारिश
मत यह ख्वाब सजाना तुम।।
विरह-वेदना का विष सारा
चुपके से पी जाना तुम।
न करना अब याद वफाएं
ना यादों में आना तुम।।
एक परवाना शमा की लौ से
जब जाकर टकराया था।
प्यार की खातिर उसने जलकर
अपना आप मिटाया था।।
हाल पे उसके छोड़के उसको
प्रीत की रीत निभाना तुम।
न करना अब याद वफाएं
न यादों में आना तुम।।
यादों का जब कोई परिंदा
दिल की मुंडेर पे आ बैठे।
गुजरे हुए मुकाम के किस्से
यारा तुम्हें सुना बैठे।।
सच कहता हूं ऐसे पंछी को
ना दाना पाना तुम।
न करना अब याद वफाएं
न यादों में आना तुम।।
बंजर धरती पर एहसास की
बेलें कहां पनपती हैं।
टूटे हुए जज्बात की यारा
चूड़ियां कहां खनकती हैं।।
पत्थर की इस दुनिया को
न दर्द की खनक सुनाना तुम।
न करना अब याद वफाएं
ना यादों में आना तुम।।

- अशोक दर्द

कुली

नींद तो नहीं कह सकते, जरा सी झपकी लग गई थी। बुरा सपना था, एक अजीब सी आकृति, कटे हुए हाथ के साथ, खड़ा है एक अपाहिज शरीर। अचानक शोर से सपना टूटा।

ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी। इस स्टेशन पर आकर रुकने वाली आज की यह अंतिम ट्रेन थी। यात्री, एक-एक कर, ट्रेन से उतरने लगे। मैं बड़ी उम्मीद से हर यात्री को देख रहा था, कोई यात्री पुकारेगा- कुली-ई-ई या इस बार भी निराशा ही हाथ लगेगी।

ट्रेन से एक साहेब उतरे। मात्र एक सूटकेस और थैलानुमा एक बैग। जब वह ट्रेन से उतर रहे थे तो लग रहा था उनके पैर में कोई तकलीफ है, उसकी पीड़ा उनके चेहरे के हाव-भाव से लग रही थी। ट्रेन से उतर कर वह खड़े हो इधर-उधर देखने लगे।

साहेब, कुली चाहिए? एक उम्मीद मेरी आंखों में जगी। नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं है कुली की।

वे सूटकेस को व्हील पर खींचते हुए आगे बढ़ गए, मुझे लगा वो व्हील नहीं मेरे दोनों कटे हाथ हैं, और यहां खड़ा है, मेरा अपाहिज शरीर।

- सुनीता मिश्रा

जीतने की कला सीखें भारतीय खिलाड़ी

अंततः ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप-2023 अपने नाम कर भारत का विजय रथ थाम दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मायूस होते हुए छलके आंसू के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतने वाली भारतीय टीम को बड़े फाइनल जीतने की कला सीखनी होगी। अहमदाबाद में भी भारतीय खेमे से कई चूक हुईं और वर्ल्डकप हाथ से फिसल गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवर में 240 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाकर मैच को जीत लिया। कंगारू टीम के लिए ट्रेविस हेड ने 141 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। मार्नश लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। मिचेल मार्श 15, डेविड वॉर्नर सात, स्टीव स्मिथ चार रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद दो रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता बना है। वहीं, भारत का तीसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। उसने टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन 11वें मुकाबले में टीम पिछड़ गई। भारत को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार 2003 में रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली टीम ने हराया था। इससे पहले भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 66 रन और विराट कोहली ने 54 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 और सूर्यकुमार यादव ने 18 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 10 रनों का योगदान दिया। इन पांच खिलाड़ियों के अलावा कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। रवींद्र जडेजा 9, मोहम्मद शमी 6, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल 4-4 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह एक रन ही बना पाए। मोहम्मद सिराज 9 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को दो-दो सफलता मिली। ग्लेन मैक्सवेल और एडम जम्पा ने एक-एक विकेट लिए।

भारत ने मैच में यह पांच गलतियां न दोहराई होतीं तो नतीजा कुछ और होता। पहला, कप्तान रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में लगातार दो गेंदों पर 10 रन बनाए, जिसमें एक चौका और छक्का शामिल है, लेकिन यहां वो धैर्य खो बैठे। एक और छक्के के प्रयास में ट्रेविस हेड के एक बेहतरीन कैच द्वारा आउट हो गए। यदि रोहित शर्मा थोड़ा सा धैर्य रखते तो निश्चित रूप से मैच की स्थिति कुछ और हो सकती थी। दूसरा, इस वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भी भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। शुरुआत में 2 रन के स्कोर पर भारत ने तीन विकेट गंवा दिए थे और मैच को विराट कोहली और केएल राहुल ने संभाला था। इस बार भी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर ही पूरा भार आ गया था, लेकिन विकेट बचाए रखने के चक्कर में दोनों जरूरत से ज्यादा धीमा खेले। पूरा दबाव टीम पर आ गया। एक खराब शॉट खेलते हुए विराट कोहली आउट हो गए और टीम लड़खड़ा गई। मिडिल ऑर्डर की नाकामी भारत को भारी पड़ी, क्योंकि बीच के ओवर्स में भारत ने कोई खास स्कोर नहीं बनाया। जहां 10.2 ओवर में भारत का स्कोर 81 रन था, वहीं 35.5 ओवर में यह 178 रन ही बना, यानी भारत ने 25 ओवरों में 100 रन भी नहीं जोड़े।

तीसरा, भारत की फील्डिंग बेहद खराब रही। जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर ही डेविड वार्नर के बल्ले से गेंद लगकर स्लिप में गई थी, लेकिन फर्स्ट स्लिप पर खड़े विराट कोहली उसे देखते रह गए, जबकि उन्हें कैच की कोशिश करनी चाहिए थी। यदि पहली गेंद पर विकेट गिर जाता तो ऑस्ट्रेलिया भारी दबाव में आ जाती। विकेट कीपिंग भी बेहद खराब रही। केएल राहुल पूरे मैच के दौरान आसान से अवसर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड बढ़ाते रहे। बाय के रनों की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया को एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिला और भारत ने एक्स्ट्रा में 18 रन दे दिए। चौथा, पूरे टूर्नामेंट में जिस शक्तिशाली गेंदबाजी के भरोसे भारत जीतता आ रहा था, वो सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी फुस्स साबित हुई। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय स्पिनरों की पोल खुली थी और वो 20 ओवर में एक विकेट ही ले पाए थे। कुछ यही कहानी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुई। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 20 ओवर कराए और दोनों को कोई सफलता नहीं मिली। दोनों ने 20 ओवर में 99 रन दे दिए। रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव की जगह यहां आर अश्विन को खिलाया जाना चाहिए था। खासकर कुलदीप यादव को बदलकर आर अश्विन को खिलाया जा सकता था, क्योंकि अश्विन एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं।

पांचवां, भारतीय टीम को आगामी टूर्नामेंट में मानसिक रूप से मजबूत रहने और बड़े अवसरों पर कैसे जीता जाता है? यह कला ऑस्ट्रेलिया से सीखने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। यदि आईसीसी टूर्नामेंट के पिछले 10 साल देखे जाएं तो भारत 2014 में टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल हारा, 2015 में वर्ल्डकप का सेमीफाइनल हारा, 2016 में टी-20 वर्ल्डकप का सेमीफाइनल हारा, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारा, 2019 में वर्ल्डकप का सेमीफाइनल हारा, 2019-20 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा, 2021 में टी-20 वर्ल्डकप ग्रुप स्टेज पर हारा, 2022 में टी-20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, 2021-23 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा और अब वर्ल्डकप फाइनल हार गया।

● आशीष नेमा

विश्व कप में पहली बार ऑलआउट हुई टीम

भारत के लिए इस मैच में विराट कोहली और केएल राहुल ने चौथे विकेट के लिए 67 रन की सबसे बड़ी साझेदारी की। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। रोहित, कोहली और राहुल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्यकुमार बड़े मौके पर फेल हो गए। भारत पहली बार इस विश्व कप में ऑलआउट हुआ है और मैच भी हार गया। इस तरह भारत का 10 साल का आईसीसी ट्रॉफी का सूखा अब भी जारी है। खास बात यह है कि इस साल टेस्ट चैंपियनशिप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती और वर्ल्डकप का फाइनल भी जीता। घर में इतना बड़ा टूर्नामेंट हारना निश्चित रूप से भारतीय प्रशंसकों को खल रहा है, लेकिन खेल को खेल भावना से ही लिया जाना चाहिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत वर्ल्डकप फाइनल की गलतियों से सीखेगा और भविष्य में वर्ल्डकप घर लेकर आएगा।

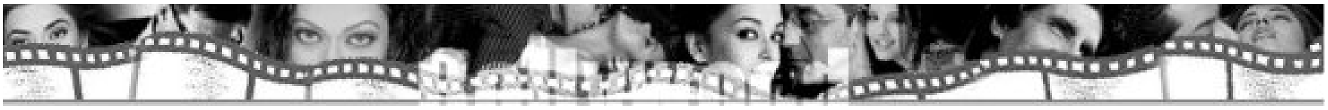

175 दिनों तक थिएटर्स में देखी गई कमल हासन की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश

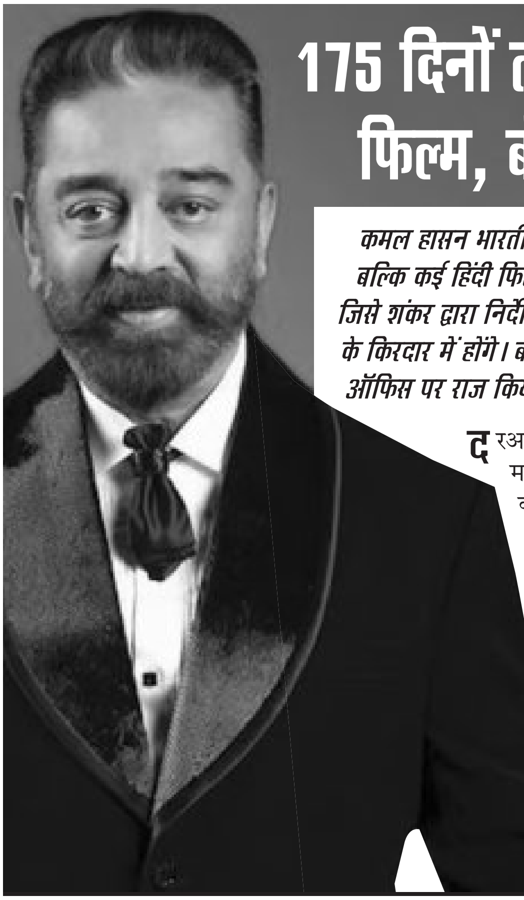

कमल हासन भारतीय सिनेमा के बड़े स्टार हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने न सिर्फ साउथ बल्कि कई हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। इन दिनों वे अपनी इंडियन-2 में बिजी हैं, जिसे शंकर द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा वे प्रोजेक्ट-के में भी आने वाले हैं जिसमें वे एक विलन के किरदार में होंगे। बहरहाल, यहां हम उनकी उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे वक्त तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया और जो 100 ही नहीं बल्कि 150 दिनों से ज्यादा वक्त तक सिनेमाघरों में चली थी...

दरअसल, यहां हम कमल हासन की थेवर मगन के बारे में बात कर रहे हैं जो बीते दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसका निर्देशन भरत द्वारा किया गया था जबकि इसकी कहानी कमल हासन ने लिखी और वे इसके प्रोड्यूसर भी थे। थेवर मगन में कमल हासन लीड रोल में थे और उनके अलावा शिवाजी गणेशन, हासन, रेवती, गौतमी और नासर भी अहम रोल में थे। इन सबके अलावा सपोर्टिंग रोल्स में कल्लापार्ट नटराजन, काका राधाकृष्णन, सांगिली मुरुगन और वडिवेलु थे। फिल्म में लोगों ने हर एक किरदार को पसंद किया और अपना प्यार दिया। ये फिल्म 25 अक्टूबर साल 1992 को दिवाली के दौरान रिलीज हुई थी और ये सिनेमाघरों में पूरे 175 दिनों तक चली थी। इसके रिलीज के बाद दर्जनों फिल्में आईं लेकिन इसने सिनेमाघरों में लंबे वक्त तक कब्जा किया। इसके लिए कई लोगों के निगेटिव रिएक्शन्स भी आए, बावजूद इसके फिल्म ने सिनेमाघरों में 175 दिनों का सफर पूरा किया। ये बात शायद ही कोई जानता होगा कि तमिल भाषी फिल्म थेवर मगन को 65वें अकादमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन नॉमिनेट नहीं किया गया।

1960 में चली थी दिलीप कुमार की ऐसी आंधी, चपेटे में आए गए थे सारे एक्टर

60 के दशक में वैसे तो दिलीप कुमार बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे। उस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर को दी थी, लेकिन साल 1960 में आई उनकी 2 फिल्मों ने हंगामा मचा दिया था और दोनों ही फिल्में आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं, जिनके नाम मुगले–ए–आजम और कोहिनूर हैं। 1960 में दिलीप कुमार सारे एक्टर पर भारी पड़ गए थे।

मुगल-ए-आजः विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, यह फिल्म साल 1960 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

बरसात की रातः यह फिल्म साल 1960 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।

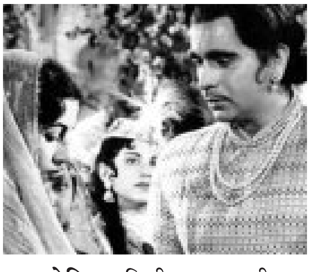

कोहिनूरः दिलीप कुमार की यह फिल्म साल 1960 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

चौदहवीं का चांदः यह साल 1960 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी।

जिस देश में गंगा बहती हैः यह फिल्म साल 1960 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

कबीर सिंह के लिए शाहिद नहीं, रणवीर सिंह थे संदीप रेड्डी की पहली पसंद

शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाका मचाया था, वो अपने आप में कमाल था। इस फिल्म ने शाहिद के अकाउंट में भी एक 100 करोड़ी फिल्म जोड़ दी। लेकिन इस फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खुलासा किया है कि शाहिद कपूर इस फिल्म के लिए उनके पहली पसंद नहीं थे। बल्कि वो बॉलीवुड के खिलजी यानी रणवीर सिंह को अपना कबीर सिंह बनाना चाहते थे। लेकिन रणवीर ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। इतना ही नहीं, कई लोगों को शाहिद के साथ इस फिल्म को बनाने पर भी शक था। लेकिन इस फिल्म में कबीर सिंह बन शाहिद ने कई लोगों के मुंह बंद कर दिए। संदीप ने

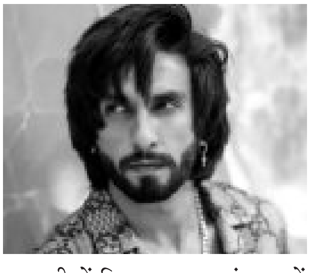

हाल ही में दिए एक ताजा इंटरव्यू में बताया, मुझे लगातार मुंबई से अर्जुन रेड्डी फिल्म का रीमेक बनाने के लिए फोन आ रहे थे। मैंने सबसे पहले रणवीर सिंह को अप्रोच किया। मैं उन्हीं के साथ ये फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन बातचीत के बाद रणवीर ने तय किया कि कैरियर के इस पड़ाव पर ये फिल्म नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी डार्क फिल्म है। इसके बाद उन्होंने शाहिद के साथ ये फिल्म बनाई।

मुंह वाला मंत्री!

असंख्य गूंगे-बहरे मंत्रियों को संभाला जा सकता है, लेकिन एक अदद मुंह वाले मंत्री को संभालना सबसे मुश्किल काम है। अक्सर बोलने वाला मंत्री गूंगे-बहरों के बीच कैंसर बनकर उन्हें भी यह रोग लगा देता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिवाय दूर रहने के। सत्ता अक्सर लूटने में इतनी लिप्त रहती है कि उसे जनकल्याण भी एक बीमारी सी लगती है।

कल कमाल हो गया। जनता ने पहली बार एक ऐसे मंत्री को देखा जो मुंह से बोलता था। चुनाव जीतने के बाद हाथ, पैर, आंख, नाक से बोलने वाले मंत्री अक्सर मुंह का इस्तेमाल सिर्फ रैलियों में करते हैं। किंतु इस मंत्री ने मुंह का इस्तेमाल कर अपने दल के साथ-साथ जनता को भी आश्चर्यचकित कर दिया। मीडिया ने भू-बकासुर, धनखाऊ और जनता की समस्याओं के प्रति चुप्पी साधने वाले इस कुंभकर्णी मंत्री के बारे में लाख कार्यक्रम चलाए, लेकिन यह मंत्री अंगद पैर की भांति सत्ता पर अड़ा रहा। मीडिया और जनता लाख चिल्लाते रहे लेकिन वह भीष्म प्रतिज्ञा की तरह चुप रहकर शांतचित्त बना रहा।

पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि भोजन के सिवाय सब कुछ डकारने वाले इस मंत्री का मुंह कैसे खुल गया! दलाध्यक्ष ने कहा कि असंख्य गूंगे-बहरे मंत्रियों को संभाला जा सकता है, लेकिन एक अदद मुंह वाले मंत्री को संभालना सबसे मुश्किल काम है। अक्सर बोलने वाला मंत्री गूंगे-बहरों के बीच कैंसर बनकर उन्हें भी यह रोग लगा देता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिवाय दूर रहने के। सत्ता अक्सर लूटने में इतनी लिप्त रहती है कि उसे जनकल्याण भी एक बीमारी सी लगती है।

अचानक से मुंह खोलने वाले मंत्री जी ने पिछले दो दशक से लूटपाट का ऐसा कीर्तिमान बनाया कि सभी नवजात मंत्रियों के लिए वह आराध्य लूटपुरुष बन गया। पिछले दिनों वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बहाने कठपुतली का तमाशा देख बैठा। उसने देखा कि बंदर और मदारी के तमाशे में बंदर मदारी को नचा रहा था। उसे अपनी याद हो आई। वह जनता को नचाने में सिद्धहस्त था। नेताजी के पास हमेशा नए-नए आइडिया तैयार रहते थे। नई सरकार बनने पर उसने पानी-पूरी की तर्ज पर घोटाला-पूरी का स्टाल लगवाया था। कांट्रेक्टरों को उनके कार्यक्रमों का शिद्दत से इंतजार रहता था। उसने वादा कर रखा था कि अबकी जमीन पर भवन बनाए बिना जेबों में रुपयों का भवन बनाएगा। वादे के मुताबिक उसने कांट्रेक्टरों की जेबों में इतने रुपए भवन बना दिए कि दूसरे मंत्रियों को उनका पत्ता काटने के लिए कमर कसनी पड़ी। मंत्रियों के दल ने लोहे को लोहा और रुपए को रुपया काटने वाले फार्मूले की तर्ज पर मंत्री जी को पद से हटवा दिया।

मंत्रियों के वाट्सएप ग्रुप में खबर आई कि आज शाम को सब लोग मीटिंग हॉल में मंत्री को मुंह खोलते हुए लाइव देख सकते हैं। मंत्रीगण चौंक गए। मैसेज के जवाब में कई जिज्ञासाएं आईं। मंत्रीगण पूछ रहे थे- मुंह खोलना क्या होता है? खोलने पर प्रभाव कैसा होता है? यह भी जानना चाहते थे कि इससे बचने के उपाय क्या हैं? पिछली बार एक मंत्री ने डकार लेने के लिए मुंह खोला था कि मीडिया ने उसे राई का पहाड़ बनाकर सरकार गिरा दी थी। इसलिए इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से ही सबको बता देना चाहिए कि वे कितना बड़ा मुंह खोलेंगे, कैसे खोलेंगे और क्यों खोलेंगे? मंत्रियों ने पूछा मुंह खोलने पर जीभ दिखाई देगी कि नहीं। मंत्रियों का एक बड़ा समूह जीभ वाले मंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए मरा जा रहा था। बेहतर हो कि मुंह खोलने वाले मंत्री की जीभ को जूम किया जाए, जिससे कि हजार चूहे खाने के बाद हज को जाने वाली बिल्ली की जीभ का रंग, आकार कैसा होता है? देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तय समय के अनुसार मंत्री जी को बुलाया गया। उन्हें मुंह खोलने के लिए कहा गया। बाकी के मंत्री चौंक गए। अरे! ये क्या इनकी जीभ ही नहीं है! जीभ कम से कम एक मीटर लंबी होगी, ऐसा सोचकर मंत्रीगण आए थे। किंतु यह क्या इनकी जीभ ही नहीं है! मानो ऐसा लगा ये तो आगे चलकर बड़ा खेला करने की योजना बना रहा है! दलाध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में जीभ न रहना स्वनियंत्रित जीभधारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिनकी जीभ होती हैं उन्हें काफी सोचना-समझना पड़ता है जबकि बिना जीभ वालों के लिए लूटना एक मात्र धर्म होता है।

● **डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

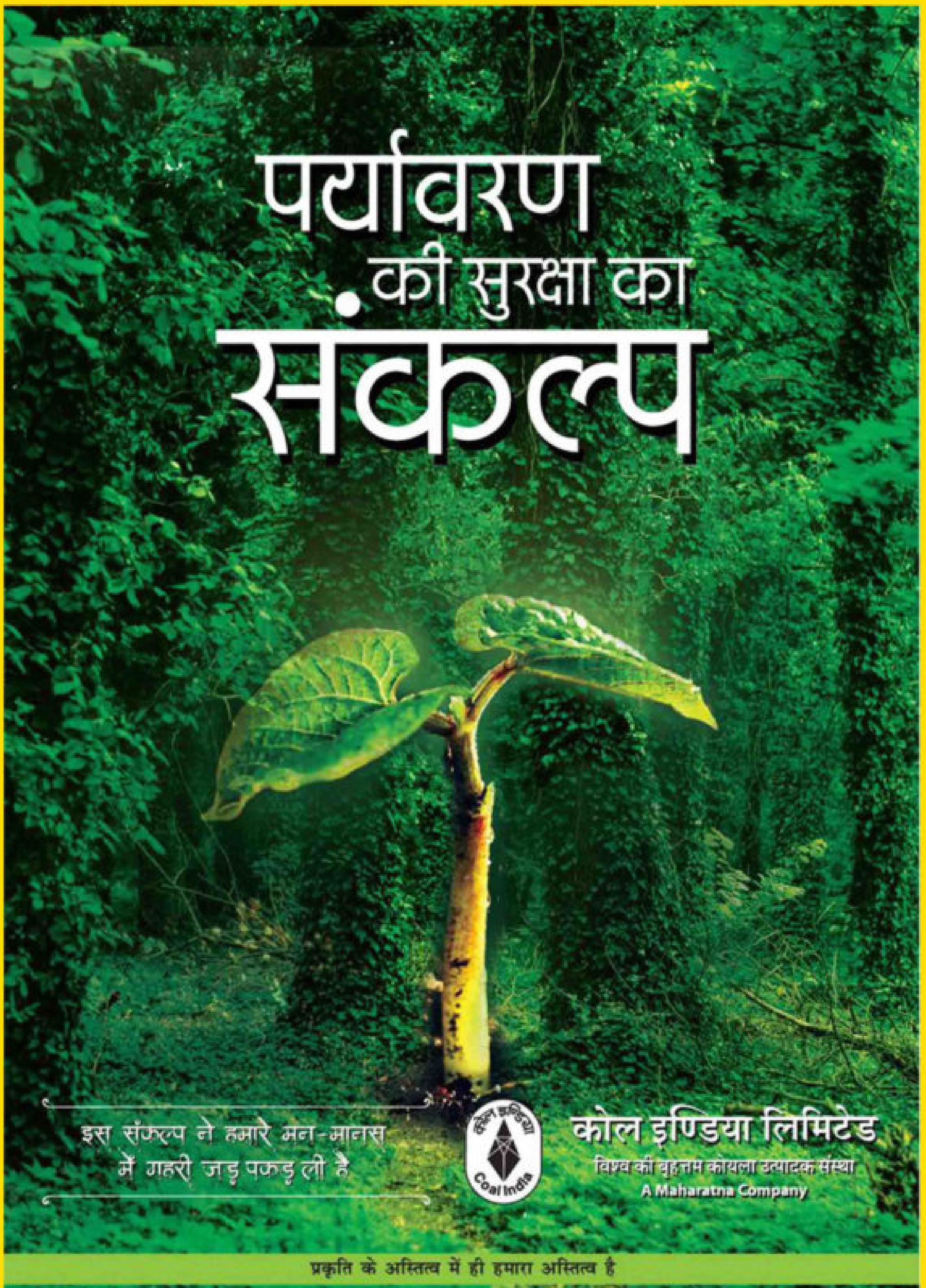

पर्यावरण
की सुरक्षा का
संकल्प
इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है
कोल इण्डिया
Coal India
कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company
प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है